

कौमी पत्रिका

राष्ट्रीय दैनिक अखबार

दिल्ली-हरियाणा-पंजाब-चण्डीगढ़-उत्तर प्रदेश से प्रसारित
शनिवार, 11 अप्रैल 2026

VISIT:
www.qaumipatrika.in
Email: qpatrika@gmail.com

R.N.I. No. UP-HIN/2007/21472 सम्पादक - गुरचरन सिंह बख्तर चर्च 19 अंक 156 qaumipatrikahindi 011-41509689, 23315814, 9312262300 गाजियाबाद संवत् 2077-78, पेज (12) मूल्य 3.00 रुपये (हवाई शुल्क 50 पैसे अतिरिक्त)

संक्षिप्त समाचार

अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

• विधानसभा सदस्यता बनी रहेगी बरकरार

एजेंसी

मऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। हेट स्प्रीच से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सजा पर रोक खाले फैसले को बरकरार रखा था। कोर्ट के इस तार्का फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता बनी रहेगी और फिलहाल उस पर कोई खतरा नहीं है। दरअसल हेट स्प्रीच से जुड़े एक केस में निचली अदालत ने अब्बास अंसारी को सजा सुनाई थी। सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते उनकी सदस्यता फिलहाल बच गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए भारत का सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायित्व की थी। सरकार ने मांग की थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया जाए, जिसमें सजा पर रोक लगाई गई थी। सरकार का कहना था कि हाईकोर्ट का फैसला गलत है और सजा पर रोक हटाई जानी चाहिए, ताकि कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

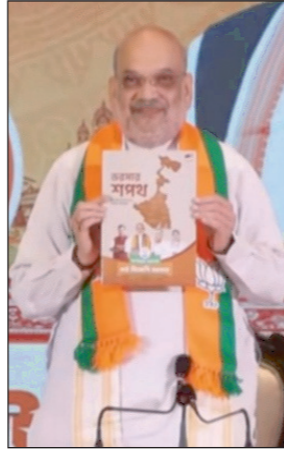


बंगाल के लिए बीजेपी का घोषणापत्र

• अमित शाह बोले- 45 दिन के अंदर 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे; यूसीसी भी लागू होगा

एजेंसी

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुरुवार को पश्चिम बंगाल के दौर में हैं। इस दौरान वे विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का घोषणापत्र जारी कर रहे हैं। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए इसे 'भरोसे का पत्र' बताया। पार्टी ने इसे 'सोना बांग्ला' का रोडमैप बताते हुए विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा पर फोकस किया है। साथ ही, उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भाजपा बंगाल के ही नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी।



निकलने का रास्ता दिखाएंगे। अमित शाह के अनुसार, इस घोषणापत्र में

में रखते हुए तैयार किया गया है और मौजूदा निराशा के माहौल से बाहर किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में आ रही चुनौतियों से जूझ रहे किसानों को इससे नई दिशा मिलेगी, जबकि युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी खास जोर दिया गया है।

इसके साथ ही बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और गौरव को पुनर्स्थापित करने की बात भी इसमें प्रमुख रूप से शामिल है।

इसके अलावा अमित शाह ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान करते हुए कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों और वेतनभोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिनों के भीतर ही सातवें वेतन आयोग और आयुष्मान भारत समेत भारत सरकार

भाजपा के घोषणापत्र की 10 बड़ी बातें

- सरकार बनने के 6 महीने के अंदर बंगाल में यूसीसी लागू करने का वादा।
- राज्य की महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3000 रुपये देने का एलान।
- मवेशी तस्करी पर सख्त रोक लगाने का वादा।
- बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए 'वंदे मातरम म्यूजियम' बनाने की घोषणा।
- राज्य सरकार की सभी नौकरियों (पुलिस सहित) में महिलाओं को 33फीसदी आरक्षण देने का वादा।
- सरकार बनने के 45 दिन के भीतर सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू का एलान।
- उत्तर बंगाल में AIIMS, IIT, IIM और फेशन डिजाइन संस्थान स्थापित का वादा।
- पीएम किसान से इतर राज्य सरकार की ओर से 3,000 रुपये अतिरिक्त मदद देने का वादा।
- राज्य में विकास को बढ़ावा देने के लिए चार नए टाउनशिप विकसित करने की घोषणा।
- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को आयुष्मान भारत से जोड़ने का वादा।

की सभी योजनाओं को लागू करेंगे। साथ ही छह माह के अंदर ही यूसीसी भी लागू करेंगे। महिलाओं के लिए एलान करते हुए कहा कि हमारी सरकार 'लक्ष्मी भंडार' योजना के लाभार्थियों को हर महीने 1 से 5 तारीख तक खाते में 3 हजार रुपए ट्रांसफर करेगी।

इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं को 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट देने की योजना है। वहीं, राज्य संचालित बसों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा लागू करने का भी वादा किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि में हम राज्य की तरफ से अतिरिक्त 3,000 रुपये जोड़ेंगे और किसानों को सालाना 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता देंगे।

पंजाब को बकाया 9,000 करोड़ रुपए के आरडीएफ फंड

जारी करने संबंधी सचिव स्तरीय बैठक की जाएगी: मुख्यमंत्री मान

कौमी पत्रिका

नई दिल्ली/पंजाब, 10 अप्रैल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्य के किसानों और मंडियों के लिए कई महत्वपूर्ण गृह उपाय सुनिश्चित किए। इस दौरान केंद्र ने पंजाब में पड़े 155

हमने आदतियों की मांगों सहित पंजाब से संबंधित विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा- बेटक के दौरान केंद्र के सामने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए, जिसमें पंजाब में पड़े 155 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल की तुल्य लिफ्टिंग तथा आरडीएफ के तहत बकाया 9,000 करोड़ रुपए की तुरंत अदायगी के मुद्दे शामिल थे। इसके साथ ही, नकद ऋण सीमा के तहत रज्यों पर लगाई गई उच्च ब्याज दरों को कम करने और आदतियों की केंद्र से संबंधित मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने की मांग की गई। इसके अलावा, मंडी मजदूरों के ईपीएफ से संबंधित मुद्दों को तुरंत हल करने की अपील की गई और असामयिक बारिश के कारण हुए नुकसान के लिए किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग भी की गई। उन्होंने आगे लिखा, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि केंद्रीय मंत्री जी ने इन सभी मुद्दों पर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हम पंजाब के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। फसलों के भंडारण संबंधी भारी कमी पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, राज्य के कवरड गोदामों में 180.88 लाख मीट्रिक टन अनाज (151.20 लाख मीट्रिक टन चावल और 29.67 लाख मीट्रिक टन गेहूं) पहले से ही स्टोर किया गया है, जबकि कुल उपलब्ध कवरड भंडारण क्षमता लगभग 183 लाख मीट्रिक टन (173 लाख मीट्रिक टन कवरड गोदाम + 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं साइलो) है। नतीजतन, चावलों के लिए केवल 0.50 लाख मीट्रिक टन कवरड स्पेस और गेहूं के लिए 1.75 लाख मीट्रिक टन साइलो स्पेस उपलब्ध है। उन्होंने कहा, राज्य में 1 अप्रैल, 2026 से रबी मंडीकरण सौजन (आरएमएस) 2026-27 शुरू हो गया है, जिसमें संभावित रूप से 130-132 लाख मीट्रिक टन

गेहूं की खरीद की जाएगी। मौजूदा स्टॉक के बोझ को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल के 38 लाख मीट्रिक टन गेहूं के स्टॉक में से लगभग 8.71 लाख मीट्रिक टन स्टॉक पहले ही राज्य में सीएपी या खुली स्टोरेज में पड़ गई, जिससे

वैज्ञानिक तरीके से भंडारण क्षमता की कमी हो गई है और लगभग 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं को कम अनुकूल परिस्थितियों में स्टोर करना पड़ेगा। अनाज की धीमी उड़ई का मुद्दा उठते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमारी सरकार लगातार

गेहूं और चावल की राज्य से उड़ई की मांग करती रही है ताकि चावल की खरीद और स्टोरेज के लिए जरूरी भंडारण क्षमता बनाई जा सके।

पृष्ठ 3 पर



लाख मीट्रिक टन अनाज की लिफ्टिंग के लिए विशेष रेल गाड़ियां चलाने पर सहमत दे दी, जिससे रबी मंडीकरण सौजन से पहले राज्य में अनाज भंडारण संबंधी गंभीर संकट से निपटने में मदद मिलेगी। इस हस्तक्षेप के साथ-साथ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब पर बोझ बने संचनात्मक मुद्दों के समाधान पर जोर दिया, जिसमें उच्च नकद ऋण ब्याज दरें, ग्रामीण विकास फंड के तहत लॉबित 9,000 करोड़ रुपए, ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए मुआवजा और आदतियों की लंबे समय से लंबित मांगें शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने इन मुद्दों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और लंबित मुद्दों के समाधान के लिए सचिव स्तरीय व्यवस्था बनाने सहित ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया। एकस हेंडल पर बेटक की जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा- आज दिल्ली में मैंने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी जी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान

संबंधी भारी कमी पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, राज्य के कवरड गोदामों में 180.88 लाख मीट्रिक टन अनाज (151.20 लाख मीट्रिक टन चावल और 29.67 लाख मीट्रिक टन गेहूं) पहले से ही स्टोर किया गया है, जबकि कुल उपलब्ध कवरड भंडारण क्षमता लगभग 183 लाख मीट्रिक टन (173 लाख मीट्रिक टन कवरड गोदाम + 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं साइलो) है। नतीजतन, चावलों के लिए केवल 0.50 लाख मीट्रिक टन कवरड स्पेस और गेहूं के लिए 1.75 लाख मीट्रिक टन साइलो स्पेस उपलब्ध है। उन्होंने कहा, राज्य में 1 अप्रैल, 2026 से रबी मंडीकरण सौजन (आरएमएस) 2026-27 शुरू हो गया है, जिसमें संभावित रूप से 130-132 लाख मीट्रिक टन

मजाक और अपमान के बीच का फर्क समझे सरकार: संजय राउत

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में %ब्रीच ऑफ प्रिविलेज% यानी विशेषाधिकार हनन का मामला एक बार फिर गरमा गया है। स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की ओर से उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी और पैरोडी गाने को लेकर मंच घमासान के बीच अब शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि कुणाल कामरा ने जो किया वह पैरोडी है, न कि अपमान या पवित्रता भंग करना। राउत ने सत्ता पक्ष पर तंज करते हुए कहा कि सरकार को कला और अपराध के बीच का महीन अंतर समझना चाहिए। दरअसल, कुणाल कामरा ने पिछले साल मुंबई में एक शो के दौरान फिल्म %दिल तो पागल है% के एक गाने में बदलाव कर महाराष्ट्र में हुए सत्ता परिवर्तन पर कटाक्ष किया था। इस पैरोडी के जरिए उन्होंने जून 2022 में शिवसेना में हुई बगावत और महा विकास अघाड़ी सरकार के गिरने पर निशाना साधा था।

परिसीमन को लेकर चुनावी फायदा लेना चाहती है सरकार: खरगे

कौमी पत्रिका

नई दिल्ली। महिला आरक्षण कानून और परिसीमन को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार का यह कदम चुनावी फायदा लेने के लिए उठाया जा रहा है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस मुद्दे पर बिना गहराई से चर्चा किए कोई भी फैसला देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।



खरगे ने कहा कि सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुला रही है, जिसका मकसद महिला आरक्षण कानून को लागू करने से जुड़ा संशोधन बिल जल्दबाजी में पास करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति जताई है और सभी दलों के साथ मिलकर संयुक्त रणनीति बनाने की

ध्यान में रखकर इस मुद्दे को तेजी से आगे बढ़ा रही है, ताकि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। खरगे के मुताबिक सरकार लोकसभा सीटों की 543 से बढ़ाकर 816 करने की योजना बना रही है। साथ ही राज्यों की विधानसभा सीटों में भी बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। उनका कहना है कि इस तरह का परिसीमन देश के चुनावी ढांचे को पूरी तरह बदल सकता है और

इसके दूरगामी असर होंगे। खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस मुद्दे पर विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध किया था कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटी है। खरगे ने कहा कि इस तरह के फैसले लोकतंत्र को कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि वह इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हमेशा से महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के पक्ष में रही है और पंचायत से लेकर शहरी निकायों तक आरक्षण को पहल उसी ने की थी। खरगे ने कहा कि अब विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ रणनीति बनाएगा और संसद में इस पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखेगा। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक कानून का मामला नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे से जुड़ा बड़ा सवाल है।

वंचितों को उपहार संवेदनशील सरकार

नदियों द्वारा भूमि क्षरण से प्रभावित पूर्वी उत्तर प्रदेश के **2,350 परिवारों** एवं स्थानीय थारु जनजाति के **4,356 परिवारों** को भौमिक अधिकार पट्टों का आवंटन एवं **₹817 करोड़+** से पलिया, श्रीनगर, निधासन और गोला विधान सभा क्षेत्र की **314 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास**

दिनांक : 11 अप्रैल, 2026 | समय : पूर्वाह्न 11:00 बजे
स्थान : चंदन चौकी (पलिया), लखीमपुर खीरी

बांग्लादेश से विस्थापित **331 हिन्दू परिवारों** को लखीमपुर खीरी में संक्रमणीय/ असंक्रमणीय भूमिधारी अधिकार पत्र का वितरण एवं **₹417 करोड़** से लखीमपुर, धौरहरा और मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र की **213 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास**

दिनांक : 11 अप्रैल, 2026 | समय : अपराह्न 1:00 बजे
स्थान : ग्राम मियापुर (मोहम्मदी), लखीमपुर खीरी

द्वारा
योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

नितिन अग्रवाल
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आबकारी एवं मद्य निषेध, उत्तर प्रदेश

अरुण कुमार सक्सेना
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तर प्रदेश

योगेश वर्मा
विधायक, लखीमपुर

अमन गिरि
विधायक, गोला गोकर्ननाथ

लोकेन्द्र प्रताप सिंह
विधायक, मोहम्मदी

मंजु त्यागी
विधायक, श्रीनगर

हरविंदर कुमार साहनी
विधायक, पलिया

शाशांक वर्मा
विधायक, निधासन

विनोद शंकर अवस्थी
विधायक, धौरहरा

सौरभ सिंह 'सोनू'
विधायक, कस्ता

अनूप कुमार गुप्ता
सदस्य, विधान परिषद

एवं अन्य गणमान्य महानुभाव

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को आवास की चाबी का वितरण

वंचितों को वरीयता

जोी पावर्टी कार्यक्रम के अंतर्गत 13.57 लाख निर्धन परिवार चिह्नित, 17 योजनाओं का लाभ पहुंचाकर निर्धन परिवारों की सतत आय को ₹1.25 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य

2,209 मधुआ परिवारों को सुरक्षित आवासों का आवंटन

सफाईकर्मियों को नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया गतिमान

प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना एवं माफिया से मुक्त कराई भूमि पर निर्मित 62 लाख से अधिक आवासों का आवंटन

विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

लाइव प्रसारण DD NEWS & YouTube.com/DDNEWS

UPGovOfficial CMOUHrPradesh CMOHCUP

मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 में आग, समय रहते पाया काबू

-रनवे क्षेत्र से उड़ा धुआं तो कुछ उड़ानें अस्थायी रूप से रोकीं

मुंबई (एजेंसी)। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर गुरुवार शाम अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीमों मौके पर पहुंचीं और कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। एयरपोर्ट प्रवक्ता के अनुसार, आग शाम करीब 6-10 बजे लगी। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। आग ग्राउंड फ्लोर स्थित पावर हाउस के सीलिंग लेवल तक सीमित रही, लेकिन वहां मौजूद इलेक्ट्रिक ट्रे, वायरिंग, केबल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिक पैनल को नुकसान पहुंचा। सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट के सभी गेट कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए, जिससे यात्रियों की लंबी कतारें लग गईं। टर्मिनल-1 से संचालित कुछ उड़ानों को एहतियातन रोकना गया, जिससे प्लाइट संचालन प्रभावित हुआ। फिलहाल स्थिति सामान्य कर दी गई है और अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

तीन लड़कियों की मौत की वजह बनी सेल्फी... झरने के पास कार्ड में पैर पिसलने से गहरे पानी में गिरी

अहमदाबाद (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के अहमदाबाद राज जिले में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। विशाखापत्तनम के पास स्थित घटना में पिकनिक मनाने गईं चार सहैलियों में से तीन की झरने के तेज बहाव में डूबने से मौत हो गई, जबकि एक लड़की को लोगों की मदद से सुरक्षित बचाया गया। जानकारी के अनुसार, जंघुबलका गांव की चार सहैलियां अपनी परीक्षाएं खत्म होने के बाद पास की पहाड़ियों में स्थित मुलामुम्मी झरने घूमने गई थीं। सभी लड़कियां खुश और उत्साहित थीं और पिकनिक का आनंद लेकर झरने के पास पहुंचीं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जल्द ही यह खुशी का पल एक भयानक हादसे में बदल गई। बताया जा रहा है कि 17 वर्षीय शिशा, 16 वर्षीय रत्नकुमारी और 16 वर्षीय पवित्रा झरने के बेहद करीब फिसलन भरी चट्टानों पर खड़ी होकर सेल्फी ले रही थीं। तभी चट्टानों पर जमी कार्ड की वजह से संतुलन बिगड़ने के कारण तीनों लड़कियां अचानक गहरे और तेज बहाव वाले पानी में गिर गईं। चौथी सहैली ने मदद की कोशिश की, लेकिन वह खुद सुरक्षित बाहर नहीं निकल सकी। झरने के पास मौजूद लोगों ने लड़कियों की चीखें सुनकर तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाईं। ग्रामीणों ने साहस दिखाकर एक लड़की को किसी तरीके बाहर निकाल कर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर है। हालांकि, बाकी तीन लड़कियां तेज बहाव में बह गईं और उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सूचना मिलने पर पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की तलाश के बाद तीनों लड़कियों के शव बरामद किए गए।

अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से शुरू पांजीकरण, आधार कार्ड रखना जरूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए पांजीकरण 15 अप्रैल से शुरू होगा। पांजीकरण की अंतिम तिथि 20 मई है। श्री अमरनाथ श्राद्ध बोर्ड ने इसकी घोषणा की है। यह पांजीकरण देश भर के तय कहे शाखाओं में होगा। यात्रा परमिट 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर मिलेगा। अमरनाथ यात्रा की तारीखें जल्द सामने आएगी। देश के कुल 554 बैक शाखाओं में पांजीकरण होगा। हर बैक शाखा को रोज एक तय संख्या दी गई है। हर रास्ते के लिए अलग कोटा होगा। 13 साल से कम उम्र के बच्चों का पांजीकरण नहीं होगा। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का भी पांजीकरण नहीं होगा। 16 हफ्ते से ज्यादा गभवंती महिलाओं का भी पांजीकरण नहीं होगा। इस बार पांजीकरण आधार से होगा। हर यात्री को बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के बाद परमिट मिलेगा। यह प्रक्रिया एनआईसी पोर्टल पर होगी। अगर तकनीकी समस्या आई, तब मैन्युअल तरीका भी अपनाया जाएगा। यात्रा के इच्छुक लोग बैंक में फोटो और डेटा लेकर पांजीकरण कर सकते हैं। पांजीकरण के लिए आधार कार्ड जरूरी है। हेल्थ सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा। मोदी और राज्य सरकार की कोशिश रहेगी इस यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएं। यात्रा को आरामदायक बनाने पर जोर है। साथ में सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।

आतंकी दाग से बेदाग हुए कर्नल पुरोहित बनंगे ब्रिगेडियर, सेना ने लगाई प्रमोशन पर मुहर

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय सेना ने एक ऐतिहासिक और भावुक फैसले में कर्नल श्रीकांत पुरोहित को ब्रिगेडियर रैंक पर पदोन्नत करने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला कर्नल पुरोहित के लिए किसी पुनर्जन्म से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के करीब दो दशक कानूनी लड़ाइयों और जेल की सलाखों के पीछे बिताए हैं। 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद उनका चमकता हुआ सैन्य करियर पूरी तरह पटरी से उतर गया था। हालांकि, लंबी कानूनी जंग के बाद अब सेना ने उन्हें उनका हक देने का फैसला किया है। कर्नल पुरोहित मूल रूप से 31 मार्च, 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन उनकी किस्मत ने तब करंट ली जब सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एफफटी) ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी रिटायरमेंट पर रोक लगा दी। ट्रिब्यूनल ने माना कि पुरोहित के साथ न्याय होना बाकी है। 31 जुलाई, 2025 को मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से ससम्मान बरी कर दिया था, जिसके बाद उनके प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उनके खिलाफ सबूतों का अभाव है और अभियोजन पक्ष की कहानी विश्वासार्थ से भरी थी। सेना के सूत्रों का कहना है कि यह प्रमोशन कर्नल पुरोहित के उन खोए हुए सालों की भरपाई है जो उन्होंने ट्रायल के दौरान गुंजा दिए। यदि यह विवाद न होता, तो वे अब तक मेजर जनरल के पद तक पहुंच चुके होते। उनके बेच के साथी आज सेना में शीर्ष नेतृत्व संभाल रहे हैं। इस प्रमोशन के बाद अब वे ब्रिगेडियर के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। एक समय में आतंकी कहे जाने वाले अधिकारी का एक सीनियर कमांडर के तौर पर वापस लौटना भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे चर्चित वापसी में से एक है।

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एफफटी) ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी रिटायरमेंट पर रोक लगा दी। ट्रिब्यूनल ने माना कि पुरोहित के साथ न्याय होना बाकी है। 31 जुलाई, 2025 को मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से ससम्मान बरी कर दिया था, जिसके बाद उनके प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उनके खिलाफ सबूतों का अभाव है और अभियोजन पक्ष की कहानी विश्वासार्थ से भरी थी। सेना के सूत्रों का कहना है कि यह प्रमोशन कर्नल पुरोहित के उन खोए हुए सालों की भरपाई है जो उन्होंने ट्रायल के दौरान गुंजा दिए। यदि यह विवाद न होता, तो वे अब तक मेजर जनरल के पद तक पहुंच चुके होते। उनके बेच के साथी आज सेना में शीर्ष नेतृत्व संभाल रहे हैं। इस प्रमोशन के बाद अब वे ब्रिगेडियर के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। एक समय में आतंकी कहे जाने वाले अधिकारी का एक सीनियर कमांडर के तौर पर वापस लौटना भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे चर्चित वापसी में से एक है।

यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी, मतदाता सूची से हटाए गए दो करोड़ से अधिक नाम

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। इस व्यापक अभियान के दौरान प्रदेश में दो करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से डिलीट किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवनदीप रिन्वा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 10 अप्रैल 2026 को कर दिया गया है। यह प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ संचालित की गई।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में गणना चरण 4 नवंबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 तक चला, जबकि दवे और आपत्तियों के लिए 6 जनवरी से 6 मार्च 2026 तक का समय दिया गया था। इसके बाद 27 मार्च तक सभी दलों और आपत्तियों का निस्तारण किया गया। रिन्वा ने कहा कि कोई भी मतदाता निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपना नाम देख सकता है। जिनका नाम सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर पुनः पंजीकरण करा सकते हैं।



उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, वृक्ष लेवल एजेंटों और आम जनता के व्यापक सहयोग मिला। साथ ही प्रिट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया ने भी जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने बताया कि 166 दिनों तक चले इस अभियान को सफल बनाने में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 12,758 सहायक अधिकारियों, 18,026 बीएलओ सुपरवाइजरों और 1,77,516 बीएलओ ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इसके अलावा

5,82,877 वृक्ष लेवल एजेंटों ने भी सहयोग दिया। रिन्वा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची के अनुसार कुल मतदाता 13,39,84,792 हैं जिसमें पुरुष मतदाता 7,30,71,061 (54.54 फीसदी) और महिला मतदाता: 6,09,09,525 (45.46 फीसदी) हैं। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित मसौदा सूची में कुल 12,55,56,025 मतदाता शामिल थे, जिनमें 6,88,43,159 पुरुष (54.83 फीसदी), 5,67,08,747 महिलाएं (45.17 फीसदी) और 4,119 तृतीय लिंग मतदाता शामिल थे। 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 3,33,981 रही, जबकि जेंडर रेशियो 824 दर्ज किया गया। मतदाता वृद्धि के मामले में प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और जौनपुर जिले आगे रहे। वहीं साहिबाबाद, जौनपुर, लखनऊ पश्चिम और फिरोजाबाद विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई।

हिमाचल हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को झटका

शिमला। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल हाईकोर्ट से झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा नेता हर्ष महाजन के निर्वाचन को लेकर कांग्रेस नेता सिंघवी ने याचिका दाखिल की थी। इस मामले में सिंघवी ने आवेदन दाखिल कर महाजन की ओर से दी गई गवाहों की सूची और क्रॉस एग्जामिनेशन को लेकर आवेदन दाखिल किया था। हिमाचल हाईकोर्ट ने सिंघवी के उक्त आवेदन को खारिज किया। साथ ही अदालत ने महाजन की तरफ से पेश की गई गवाहों की सूची को वैध माना है। हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव से जुड़े ट्रायल में गवाह आवश्यक हैं। उल्लेखनीय है कि सिंघवी ने अपने आवेदन में हाईकोर्ट के समक्ष आग्रह किया था कि केस में गवाहों की जरूरत नहीं है और न ही किसी प्रकार के विस्तृत साक्ष्यों की जरूरत है। हाईकोर्ट ने सिंघवी के इस आवेदन को खारिज किया। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव याचिका एक ट्रायल बेस्ड प्रोसीडिंग है। इसमें साक्ष्यों के साथ-साथ गवाहों की भूमिका भी अत्यंत आवश्यक है। अदालत ने कहा कि भाजपा नेता महाजन की तरफ से पेश की गई गवाहों की सूची प्रक्रिया के अनुरूप उचित और वैलिड है। यहां बता दें कि 10 मार्च को हाईकोर्ट ने इस आवेदन के संदर्भ में अपना फैसला सुरक्षित किया था।

आईटी कंपनी में गंदा खेल! पुलिस वेश बदलकर दबोचे यौन शोषण और जबर्न धर्मांतरण कराने वाले

कोलकाता (एजेंसी)। विशेष टीम ने अपनी पहचान छिपाकर नासिक, (इंफामस)। महाराष्ट्र के नासिक में एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी के भीतर चल रहे रेप, यौन शोषण और जबर्न धर्मांतरण के सनसनीखेज रैकेट का पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने सातवीं गिरफ्तारी करते हुए कंपनी के एचआर मैनेजर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोप है कि एचआर ने पीड़ित महिला कर्मचारियों की शिकायतों को लगातार नजरअंदाज किया और इस विनोद खेल को फलने-फूलने का मौका दिया। यदि समय रहते एक्शन लिया गया होता, तो कई महिलाओं को इस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से बचाया जा सकता था। पुलिस ने वेश बदलकर आरोपियों को दबोचा और पूरे मामले का पर्दाफाश किया।

इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच किसी फिल्मो पटकथा से कम नहीं रही। शिकायतों मिलने के बाद जब पुलिस को मामले की गंभीरता का अहसास हुआ, तो नासिक पुलिस ने एक गुप्त मिशन तैयार किया। सात महिला पुलिसकर्मियों की एक

और वेश बदलकर कंपनी के भीतर एंट्री ली। कई दिनों तक कर्मचारी बनकर रहने के दौरान इन महिला अधिकारियों ने संदिग्धों की अस्थिर हस्तियों और धर्मांतरण के दबाव को रोग हाथों पकड़ा। पुलिस ने लगभग 40 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिनमें आरोपियों की कारती कारतूतों के पुष्पा स्फूर्ति मिले हैं। अब तक इस मामले में कुल सात गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और मुंबई नाका पुलिस थाने में नौ अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अब गिरफ्तार एचआर मैनेजर से यह उमालवाने की कोशिश कर रही है कि इस नेक्सस के पीछे और कौन-कौन से बड़े नाम शामिल हैं। क्या यह केवल एक कंपनी तक सीमित मामला है या इसके तार किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय धर्मांतरण गिरोह से जुड़े हैं? इस घटना ने कॉर्पोरेट जगत में महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रशासन अब जिले की अन्य कर्मचारियों को भी कड़ी नजर रख रहा है।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दी

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। तेलंगाना की अदालत ने उन्हें एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नियमित जमानत के लिए उन्हें निर्धारित समय के अंदर सक्षम अदालत के पास जाना होगा। मामले में फैसला न्यायमूर्ति के सुझाने से सुनाया, जिन्होंने एक दिन पहले कांग्रेस नेता को याचिका पर सुनवाई की थी। यह आदेश उस समय में आया है जब कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा 7 अप्रैल से जांच एजेंसियों की नजरों से दूर बचाए जा रहे थे। दरअसल, असम और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर खेड़ा से पूछताछ करने उनके दिल्ली स्थिति आवास पर पहुंची थी, लेकिन वे वहां मौजूद नहीं मिले। यह कार्रवाई उस मामले में हो रही थी जिसमें कांग्रेस नेता खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी पर तीन विदेशी पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था।

इस बीच, कांग्रेस नेता खेड़ा ने अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटया था। उन्होंने अदालत में अपना आवासीय पता हैदराबाद बताकर गिरफ्तारी की

स्थिति में राहत देने की मांग की। बताया जा रहा है कि उनका तेलंगाना से पारिवारिक संबंध है और हैदराबाद में उनका निजी निवास भी है। साथ ही, राज्य में कांग्रेस की सरकार होने को भी इस कदम से जोड़कर देखा जा रहा है।

मामले ने तूल तब पकड़ा जब खेड़ा ने प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री सरमा और उनकी पत्नी रिनिकी सरमा पर गंभीर आरोप लगाए। खेड़ा ने दावा किया कि रिनिकी के पास तीन अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं और उनके समर्थकों के पास इस्तरह को दस्तावेज हैं जो इस कथित खुलासे को साबित करते हैं। उन्होंने इस स्वतंत्र भारत की राजनीति में एक बड़ा मामला बताया।

हालांकि, सीएम सरमा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर पूरी तरह निराधार, दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि खेड़ा जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले सरमा ने तंज कसते हुए कहा था कि जो व्यक्ति पहले गिरफ्तारी की चुनौती दे रहा था, वहीं अब जांच से बचने के लिए हैदराबाद चला गया है। तब सीएम हिमंता ने कहा था कि वह और उनकी पत्नी अगले 48 घंटों के भीतर खेड़ा के खिलाफ



आपराधिक और दीवानी, दोनों तरह के मानहानि के मुकदमे दायर करने वाले हैं।

सुनवाई के दौरान खेड़ा का प्रतिनिधित्व कर रहे कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि यह मामला असम सरकार की राजनीतिक बदले की भावना का परिणाम है। हालांकि, असम सरकार के वकील जनरल देवजीत सैकिया ने इस बात से इंकार किया। वकील सैकिया ने कहा कि खेड़ा की याचिका तेलंगाना उच्च न्यायालय में सुनवाई योग्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेता ने हैदराबाद स्थित अपना आवासीय पता प्रस्तुत किया।

सिंघवी ने तर्क दिया कि कांग्रेस नेता खेड़ा समाज में गहरी जड़ें जमा चुके हैं और एक प्रमुख राजनीतिक हस्तियां हैं। हम संवैधानिक ममाना की युग में नहीं जी रहे हैं। हम इस्तरह युग में नहीं जी रहे हैं जहां बंदूक निकालकर असम से 100 लोगों को निजामुद्दीन (खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए) भेजा जाए, जबकि शिकायत में मानहानि का आरोप लगाया गया है। जवाब में, सैकिया ने कहा कि असम कोई लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है और पूर्वोत्तर राज्य में कानून पालन होता है।

राघव चड्ढा ने वीडियो जारी कर दिया अपने विरोधियों को जबाब तमिलनाडु में बड़ा उल्टफेर... एनडीए गठबंधन के समर्थन में उतरे नौ मुस्लिम संगठन

नई दिल्ली (एजेंसी)। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अपने संसदीय प्रदर्शन पर सवाल उठाने वालों को सोशल मीडिया के माध्यम से जबाब दिया। उन्होंने कहा कि वे आलोचनाओं का जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम से देना पसंद करते हैं। वीडियो में उन्होंने कई अहम विषयों को प्रमुखता से उठाया है, जिसमें डेटा प्राइवसी, पितृत्व अवकाश को कानूनी अधिकार बनाने की मांग और बैंकों द्वारा न्यूनतम बैलेंस पर लगाने वाले जुर्माने को समाप्त करने जैसे जनहित के मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा खाद्य मिलावट, 28 दिन के मोबाइल रिचार्ज प्लान, एयरलाइंस के अतिरिक्त बैगेज शुल्क और पेंशन लीक जैसे गंभीर मामलों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी।



राघव चड्ढा ने वायु प्रदूषण, गिग वर्कर्स पर अधिक वसूली और महंगे एयरपोर्ट खर्चा पदार्थों जैसे मुद्दों को भी संसद में उठाया। उन्होंने लोगों को राहत देने के लिए मुफ्त वार्षिक हेल्थ चेकअप का अधिकार देने की वकालत की। साथ ही डिजिटल कॉपीराइट स्ट्राइक, बढ़ते कर्ज-खेड़ा, जीडीपी अनुपात और भीड़भाड़ वाले एयरपोर्ट्स की समस्या पर भी चिंता जाहिर की है। वीडियो में सरकारी बैंकों की स्थिति, दिव्यांगों और सशस्त्र बलों पर टैक्स में राहत, वसुंधर हॉल, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में देरी, टोल प्लाजा पर अधिक वसूली और महंगे एयरपोर्ट खर्चा पदार्थों जैसे मुद्दों को भी संसद में उठाया। उन्होंने लोगों को राहत देने के लिए मुफ्त वार्षिक हेल्थ चेकअप का अधिकार देने की वकालत की। साथ ही डिजिटल कॉपीराइट स्ट्राइक, बढ़ते कर्ज-खेड़ा, जीडीपी अनुपात और भीड़भाड़ वाले एयरपोर्ट्स की समस्या पर भी चिंता जाहिर की है।

समर्थन मूल्य (एमएसपी), धामक ब्रांडिंग और ग्रामीण बैंकिंग ढांचे को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने भगत सिंह को भारत रत्न देने, 'वन नेशन, वन मेंडकल ट्रीटमेंट', मासिक धर्म स्वच्छता और श्री नरकाना साहित्य कारिडोर जैसे विषयों को भी उठाया। कुल मिलाकर, यह वीडियो उनके संसदीय कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों को सामने लाने का एक प्रयास है, जिससे वे यह संदेश देना चाहते हैं कि उनका काम ही उनकी पहचान है।

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु की राजनीति में हाल ही में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें नौ मुस्लिम संगठनों ने एआईएडीएमके (एआईएडीएमके) के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला चेन्नई में हुई बैठक के बाद सामने आया, जिसमें दक्षिण भारत दरगाह मस्जिद एसोसिएशन, तमिलनाडु उर्दू मुस्लिम विकास संगठन सहित कई सूफी-सुन्नी मुस्लिम समूहों के प्रतिनिधि शामिल थे। इन संगठनों ने एआईएडीएमके महासचिव एडुयादी के पलानोस्वामी से मुलाकात की और राजनीतिक समर्थन की घोषणा की। बैठक के दौरान एआईएडीएमके नेतृत्व ने मुस्लिम प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है, तब राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों,

विशेषकर सूफी-सुन्नी मुस्लिमों के हितों को रक्षा होगी और उनके कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद मुस्लिम संगठनों ने एनडीए गठबंधन को समर्थन देने का निर्णय लिया।

दक्षिण भारत दरगाह मस्जिद एसोसिएशन ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। संगठन ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मुख्य काजी की नियुक्ति को लेकर आपत्ति जाहिर की है। उनका कहना है कि परंपरागत रूप से तमिलनाडु में मुख्य काजी की नियुक्ति सूफी-सुन्नी समुदाय की सहमति और परामर्श से होती रही है, लेकिन इस बार बिना समुदाय की राय लिए एक गैर-तंबी कबी मुस्लिम को यह पद दे दिया गया, जिससे समुदाय के एक हिस्से में असंतोष पैदा हुआ है। संगठन ने दावा किया कि तमिलनाडु में सुनवाई 2,500 से अधिक मस्जिदें और दरगाहें हैं, जो वक्फ

बोर्ड को अपने राज्य का एक निश्चित हिस्सा दान करती हैं। इसके बावजूद वक्फ संपत्तियों से जुड़े कई मुद्दे पिछले कई वर्षों से अनसुलझे पड़े हैं। कई कानूनी विवाद और याचिकाएं भी लंबित हैं, जिसके कारण मस्जिदों और दरगाहों के प्रबंधन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इसी कारण समुदाय के प्रतिनिधियों ने एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन से हस्तक्षेप और सहयोग की अपेक्षा जताई है। कुल मिलाकर, यह घटनाक्रम तमिलनाडु की राजनीति में मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से के रुख में बदलाव और आगामी राजनीतिक समीकरणों पर संभावित प्रभाव का संकेत देता है।

अनोखा ग्रीन कॉरिडोर, 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन... 7 घंटे का सफर 2.30 घंटे में

- 100 की रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन, जानवर भी सुरक्षित

देहरादून (एजेंसी)। पहाड़ों के बीच सिंगल लेन सड़क पर सामने से अचानक हाथियों का झुंड आने से पीछे गाड़ियों को लंबा जाम लगाता था, कभी उफनती नदी...तब कभी शिवालिक पहाड़ियों से गिरता मलबा सड़क पर जमा लगा देता था। पहले ऐसा ही नजारा दिखाता था दिल्ली से देहरादून रोड पर आने वाला मोहड़-बेटल पर। 210 किमी लंबे और तीन राज्यों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेस-वे का 20% का हिस्सा राजाजी टाइगर रिजर्व में आता है। लेकिन यह हिस्सा अब पूरी तरह बदल चुका है। अब मोहड़ घाटी के ऊपर बने एलिवेटेड कारिडोर से गाड़ी 100 किमी प्रति

घंटे की रफ्तार से बिना ब्रेक, बिना जाम दौड़ रही है और नीचे हाथियों का झुंड आराम से गुजर रहा है। 20 किमी लंबे हिस्से में एलिवेटेड पार्ट 12 किमी का है। यह ग्रीन कारिडोर पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन का बेहतरीन मिसाल बना है। इस शानदार एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 14 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। मोहड़ घाटी जिस बरसाती नदी से घिरती थी, वहां अब नजर नहीं आती, क्योंकि उस नदी को एलिवेटेड रोड के नीचे से निकाला गया है। सड़क को 35-40 फीट ऊपर, 400 से ज्यादा पिलर्स पर खड़ा किया गया है, ताकि नदी का बहाव, जानवरों के झुंड और विकास तीनों बिना कवच चलते

रहें। राजाजी टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर बताते हैं कि 14 हजार करोड़ रुपये में बने एक्सप्रेस-वे का 12 किमी का हिस्सा एशिया का सबसे लंबा वाइल्डलाइफ एलिवेटेड कारिडोर है। तस्वीरें इस बात का संकेत हैं कि जानवर इसके नीचे से सुरक्षित निकल रहे हैं। ऊपर से भारी वाहन 80 की स्पीड पर दौड़ चलने वाले हैं। पे-पर-यूज टोल सिस्टम, टोल पारंपरिक नाकों वाला नहीं, बल्कि क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम होगा। एंटी-एग्जिट इंटरचेंज पर दूरी के हिसाब से शुल्क कटेगा। फास्टेय से बिना रुके भुगतान, जाम की

समस्या नहीं। सहारनपुर के कुम्हारहेड़ा में एक टोल प्लाजा पहले से सक्रिय, बाकी एंटी-एग्जिट पॉइंट्स पर टोल गेट्स। इस शानदार एक्सप्रेसवे के बनने से सफर तेज, खर्च कम होगा। 6-7 घंटे का सफर अब 2.5-3 घंटे में, दूरी 260 किमी से 210 किमी होगी। 20 किमी जोखिम भरा पहाड़ी रस्ता अब 12 किमी एलिवेटेड, एक्सप्लेड रिस्क कम होगा। इतना ही नहीं सालाना 93 लाख किलो कार्बन उत्सर्जन घटेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से पर्यटन, व्यापार को बूस्ट मिलेगा। हरिद्वार-ऋषिकेश-देहरादून का सफर आसान, छुट्टमलपुर इंटरचेंज से लॉजिस्टिक्स तेज। पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं बागपत,



शामली, सहारनपुर जैसे शहरों में एक्सप्रेसवे वाले हैं। पर नए ग्रोथ हब के रूप में विकसित होने

अपना पार्क मुखर्जी नगर में भारतीय संस्थान का 60वाँ स्थापना दिवस मनाया गया

विशेष खबर

तेजेंद्र कौर बब्बर

नई दिल्ली। आज भारतीय योग संस्थान का 60वाँ स्थापना दिवस अपना पार्क मुखर्जी नगर में मनाया गया जिसमें मुख्य अध्यक्ष सुनीता मेहरा जी जो की डाइरेक्शन और स्पॉन्सर्स में मेयरथ नर युनाइटेड ग्रिप्ट और क्रेडिट सोसाइटी में डायरेक्टर और सहकारिता मंत्रालय दिल्ली प्रदेश में दिल्ली प्रदेश में महिला अध्यक्ष हैं, भारतीय योग संस्थान की महिला क्षेत्र की नीरू खनेजा जो कि जिला मंत्री हैं छाया गुप्ता जो कि क्षेत्रीय प्रभार हैं तन्वी जो क्षेत्रीय मंत्री हैं केंद्र प्रमुख सतिता मुगलियाज जी और उप केंद्र प्रमुख रीता मनोचा द्रोग इन सब का स्वागत किया गया कार्यक्रम में योग सधना करवाई गई। दीप प्रज्वलित किया गया भजन गाय गए एवं शांतिपत्र किया गया और योग के लाभ बताए गए।



पंजाब को बकाया 9,000 करोड़ रुपए के आरडीएफ फंड जारी करने संबंधी सचिव स्तरीय बैठक की जाएगी: मुख्यमंत्री मान

प्रथम पृष्ठ का शेष

हलांकि पिछले कई महीनों से राज्य से गेहूँ और चावल की औसत उत्पाद प्रति माह केवल 5 लाख मीट्रिक टन रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर महीने कम से कम 12 लाख मीट्रिक टन गेहूँ और चावल की उतर्ई की जाए या वैकल्पिक रूप से, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के दौरान आम लोगों को पेश मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए प्रभावशाली गेहूँ कल्याण अन्न योजना (पीएमफोकेवार्ड) के तहत अनाज का वितरण बढ़ाने जैसे प्रबंध किए जाएं, जैसा कोविड-19 महामारी के दौरान किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि इससे खी मंडीकरण सौजन्य 2026-27 के दौरान सुचारु खंडित कार्य सुनिश्चित होंगे और खरीफ मंडीकरण सौजन्य 2025-26 के लिए धन की मिलियां को तेज किया जा सकेगा। एक

अन्य मुद्दा उठते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि खरीद के लिए फंडों का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिभूत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के एक समूह द्वारा किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय स्टेट बैंक जो ब्याज दर वसूल रहा है, वह भारतीय खाद्य निगम पर लागू रिजर्व दर से 0.5 प्रतिशत अधिक है और मौसिक मिश्रित आधार पर ब्याज लगा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हलांकि भारत सरकार द्वारा हर सीजन के लिए जारी की गई अस्थायी लागत शीटों में राज्य को फूड वॉरिंटेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) की ब्याज दर पर केवल साधारण ब्याज की अनुमति है। नतीजतन पंजाब राज्य को हर सीजन में लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जिससे बचा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि हमने यह मुद्दा

केंद्रीय वित्त मंत्री के पास भी उठया है। तीसरा मुद्दा ग्रामीण विकास फंड से संबंधित है। हमने बार-बार कहा है कि हमारी मंडियों तक जाने वाली सड़कों के निर्माण की जरूरत है और हमने विधानसभा में एक बिल भी पास किया है। आरडीएफ के कमीशन के मुद्दे पर विचार करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने आरडीएफ (कमीशन एजेंट) के कमीशन को खरीफ मार्केटिंग सीजन (क्रेमएस) 2020-21 के लिए धन के लिए 45.88 रुपए प्रति क्विंटल और खरीफ मार्केटिंग सीजन (आरएमएस) 2021-22 के लिए 46.00 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया था। उन्होंने आगे कहा, उस समय से हर साल धन और गेहूँ दोनों के लिए एक समान निर्धारित

पर ब्याज लेने की अनुमति दी जाए। आरडीएफ के मुद्दे पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, मुख्य मुद्दा यह है कि आरडीएफ 2.5 प्रतिशत कमीशन की मांग कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार ने अपना कमीशन मौजूदा दरों पर निर्धारित किया है। आरडीएफ के कमीशन के मुद्दे पर विचार करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने आरडीएफ (कमीशन एजेंट) के कमीशन को खरीफ मार्केटिंग सीजन (क्रेमएस) 2020-21 के लिए धन के लिए 45.88 रुपए प्रति क्विंटल और खरीफ मार्केटिंग सीजन (आरएमएस) 2021-22 के लिए 46.00 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया था। उन्होंने आगे कहा, उस समय से हर साल धन और गेहूँ दोनों के लिए एक समान निर्धारित

कमीशन जारी रखा गया है, जिसके कारण आरडीएफ अस्तित्व में और राज्य सरकार आरडीएफ का कमीशन बढ़ाने के लिए बंधु सरकार को लगातार लिख रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय ने गेहूँ के लिए 4.75 रुपये प्रति क्विंटल (46 रुपए से 50.75 रुपए) और धान के लिए 4.73 रुपये प्रति क्विंटल (45.88 रुपए से 50.61 रुपए) के कमीशन में मामूली बढ़ोतरी की है, जो आरएमएस 2026-27 से लागू होगी। उन्होंने आगे कहा, आरडीएफ द्वारा इस मामूली बढ़ोतरी को स्वीकार नहीं किया गया है और मांग की गई है कि पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम, 1961 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, आरडीएफों का कमीशन एकमात्र 2.5 प्रतिशत पर निर्धारित किया जाए। उन्होंने अपील की, भारत

सरकार को डीएफपीडी के माध्यम से आरडीएफों के कमीशन में इस मामूली बढ़ोतरी की समीक्षा करनी चाहिए और पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 के अनुसार एएमएसपी के 2.5 प्रतिशत की दर से कमीशन को मंजूरी दी जानी चाहिए। एक अन्य चिंता को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पिछले कई सालों से, भारतीय खाद्य निगम डीएफए से संबंधित मुद्दों के कारण हर सीजन में खरीदी जाने वाली फसलों के लिए भुगतान किए जाने वाले मंडी लेबर चार्ज का 30 प्रतिशत अपने पास रख रहा है। उन्होंने आगे कहा, इसके परिणामस्वरूप, आरडीएफों से संबंधित लागभग 50 करोड़ रुपए की गतिशीलता के 2.5 प्रतिशत को कमीशन के अनुसार, आरडीएफों का कमीशन एकमात्र 2.5 प्रतिशत पर निर्धारित किया जाए। उन्होंने अपील की, भारत

सरकार को डीएफपीडी के माध्यम से आरडीएफों के कमीशन में इस मामूली बढ़ोतरी की समीक्षा करनी चाहिए और पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 के अनुसार एएमएसपी के 2.5 प्रतिशत की दर से कमीशन को मंजूरी दी जानी चाहिए। एक अन्य चिंता को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पिछले कई सालों से, भारतीय खाद्य निगम डीएफए से संबंधित मुद्दों के कारण हर सीजन में खरीदी जाने वाली फसलों के लिए भुगतान किए जाने वाले मंडी लेबर चार्ज का 30 प्रतिशत अपने पास रख रहा है। उन्होंने आगे कहा, इसके परिणामस्वरूप, आरडीएफों से संबंधित लागभग 50 करोड़ रुपए की गतिशीलता के 2.5 प्रतिशत को कमीशन के अनुसार, आरडीएफों का कमीशन एकमात्र 2.5 प्रतिशत पर निर्धारित किया जाए। उन्होंने अपील की, भारत

आरडीएफों से अंडरटेकिंग या हलफिया बयान प्राप्त करने के बाद उन्हें भुगतान कर रही है, जिसमें कहा गया है कि यदि डीएफपीए अधिकारियों द्वारा कोई इंत्यारी निर्धारित की जाती है, तो आरडीएफ इसे पूरा करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा, इतना ही नहीं कि वे एफसीआई को राज्य एजेंसियों की तरह हलफिया बयान लेकर भुगतान जारी करने के निश्चय दें, राष्ट्रीय खाद्य खंडित प्रणाली में पंजाब को प्रमुख भूमिका को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि निर्बंधन बढ़ाकर सुनिश्चित करने, किसानों के हितों को रखा करने और एफसीआई के पास पड़े हैं, जिससे उनका वित्तीय बोझ और बढ़ेगा है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य की एजेंसियां

राजधानी के जहरीले पहाड़ पर रोजगार की कीमत बनी बीमारी

दिल्ली। दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में स्थित ओखला लैंडफिल साइट पर काम करने वाले मजदूरों की हालत बेहद चिंताजनक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की शोधकर्ता सोम एंगमो और इन्फो प्रोफेसर शाची शाह के विस्तृत अध्ययन में यह बात साफ हुई है। पर्यावरण संरक्षण जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में खुलासा हुआ है कि यहां 55 से 60 लाख टन पुराना कचरा (लेगोसी वेस्ट) अभी पड़ा है। यह साइट 1996 से चालू है और 2010 में भर चुकी थी, फिर भी काम डालना जारी रहा। ऐसे में यहां काम करने वाले मजदूरों के लिए यह जहरीला पहाड़ बन गया है। करीब 36 मजदूरों को रिकन एलर्जी, 32 को सांस की बीमारी, 23 को आंखों में लालिमा या बाल झड़ने की समस्या और 8.5 को दिल से जुड़ी दिक्कतें हैं। अध्ययन के अनुसार, इनमें से 76 प्रतिशत मजदूर अक्सर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। शोध में 107 मजदूरों से सीधे सवाल-जवाब किए गए, जिनमें ज्यादातर पुरुष थे

और उनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच थी। नतीजे देखकर हैरानी होती है। 95 प्रतिशत मजदूरों को पता है कि रोजाना कितना कचरा (लगभग 2000 टन) यहां आता है लेकिन क्या करें रोजी-रोटी के लिए काम करते हैं। मजदूर लैंडफिल की असली स्थिति से अनजान हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि लैंडफिल पर आरामगारों की हालत बेहद खराब है। 51 प्रतिशत मजदूरों ने बताया कि टॉयलेट और आराम की जगह गंदी, बिना पानी और अस्वच्छ है। लीचेट यानी कचरे से निकलने वाला जहरीला पानी का कोई प्रबंधन नहीं है। शोधकर्ता सोम एंगमो के अनुसार, 2018 में लैंडफिल में आग लगी थी, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य को भारी नुकसान हुआ। 2019 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पुराने कचरे को हटाने का आदेश दिया। एफसीआईसी ने बायो-माइनिंग शुरू की और छह ट्रीमल मशीनें लगाईं। 2024 तक साइट साफ करने का टारगेट था। कचरे में 52 प्रतिशत

मिट्टी जैसा पदार्थ, 42 प्रतिशत ईट-पत्थर-कंक्रीट और 5 प्रतिशत प्लास्टिक है। ऑर्गेनिक कंटेंट सिर्फ 6.3 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि एफसीआईसी ने वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट शुरू किया, जिससे लैंडफिल पर बोझ कम हुआ, लेकिन मजदूरों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया। शोध में बताया गया है कि कचरा मुख्य रूप से साउथ दिल्ली के चार जों से आता है। 46 प्रतिशत कचरा एनर्जी प्लांट में जाता है, 3 प्रतिशत कंपोस्टिंग के लिए और बाकी सीधे लैंडफिल में। घरों में अस्थायी पौधे को से समस्या बढ़ती है। रेग-पिकर्स अनौपचारिक रूप से कचरा अलग करते हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य कर्दाई या सुविधाएं नहीं मिलतीं। शोधकर्ताओं ने सिफारिशें की हैं। इसमें एफसीआईसी को हर वर्ड में सेग्रिगेशन सेंटर बनाना चाहिए। रेग-पिकर्स को स्वास्थ्य कर्दाई और सुविधाएं देनी चाहिए। मजदूरों को सालाना स्वास्थ्य जांच, अच्छी क्वालिटी का पीपीई और ट्रेनिंग देनी

चाहिए। आरामगार साफ-सुथरे बनाने चाहिए। लीचेट का प्रोपर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए। कचरा स्रोत पर अलग करने से लैंडफिल का बोझ कम होगा और ग्रीनहाउस गैस भी घटेगी। ओखला लैंडफिल ओखला बर्ड सैंक्यूअरी और अन्य इको-सैंसिटिव जोंनों के पास है, इसलिए इसे जल्द साफ करना जरूरी है। कोरोना महामारी के दौरान भी मजदूरों ने बिना रुके काम किया। लोकडाउन में कचरा कम हुआ, लेकिन 73 प्रतिशत मजदूर रोजाना आते रहे। इन्फो की अंतर्विषयक एवं पत्र-विषयक अधिनियम पीसी को प्रो. शाची शाह ने बताया कि बारिश के मौसम में यह पानी खुली नालियों से बहकर आसपास के इलाकों में फैल जाता है। मजदूरों को पता है कि लीचेट ज्यादातर मानसून में बनता है

लेकिन निगरानी या ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (एसडीएमसी) पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देता है लेकिन क्वालिटी बेहद खराब है। 86 प्रतिशत मजदूरों को पूरा सेट मिलता है लेकिन वे कहते हैं कि मास्क और दस्ताने जल्दी फट जाते हैं और पहनने में तकलीफ होती है। कई मजदूर सिर्फ मास्क या जूते पहनकर काम चलाते हैं। आज तक कोई डॉक्टर या हेल्थ इस्पेक्टर साइट पर स्वास्थ्य जांच करने नहीं आया।

लेकिन निगरानी या ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (एसडीएमसी) पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देता है लेकिन क्वालिटी बेहद खराब है। 86 प्रतिशत मजदूरों को पूरा सेट मिलता है लेकिन वे कहते हैं कि मास्क और दस्ताने जल्दी फट जाते हैं और पहनने में तकलीफ होती है। कई मजदूर सिर्फ मास्क या जूते पहनकर काम चलाते हैं। आज तक कोई डॉक्टर या हेल्थ इस्पेक्टर साइट पर स्वास्थ्य जांच करने नहीं आया।

लेकिन निगरानी या ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (एसडीएमसी) पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देता है लेकिन क्वालिटी बेहद खराब है। 86 प्रतिशत मजदूरों को पूरा सेट मिलता है लेकिन वे कहते हैं कि मास्क और दस्ताने जल्दी फट जाते हैं और पहनने में तकलीफ होती है। कई मजदूर सिर्फ मास्क या जूते पहनकर काम चलाते हैं। आज तक कोई डॉक्टर या हेल्थ इस्पेक्टर साइट पर स्वास्थ्य जांच करने नहीं आया।

लेकिन निगरानी या ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (एसडीएमसी) पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देता है लेकिन क्वालिटी बेहद खराब है। 86 प्रतिशत मजदूरों को पूरा सेट मिलता है लेकिन वे कहते हैं कि मास्क और दस्ताने जल्दी फट जाते हैं और पहनने में तकलीफ होती है। कई मजदूर सिर्फ मास्क या जूते पहनकर काम चलाते हैं। आज तक कोई डॉक्टर या हेल्थ इस्पेक्टर साइट पर स्वास्थ्य जांच करने नहीं आया।

थोक बाजारों पर महंगाई की मार, कच्चे माल की कमी से जूझ रहा हार्दवेयर बाजार

नई दिल्ली। मध्य एशिया में जारी संघर्ष के कारण कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। आयात-निर्माणा महंगा होने से व्यापारियों की लागत बढ़ गई है और बाजार में अस्थिरता का माहौल है। पुरानी दिल्ली के प्रमुख थोक बाजार चावड़ी बाजार, लालकुआं, अजमेरी गेट, गली पीपल महादेव और सीताराम बाजार आर्थिक दबाव से गुजर रहे हैं। यहां बांस, स्टील, एल्युमीनियम, आयरन, मशीन पार्ट्स, टूल्स, औद्योगिक उपकरण और सैनिकी सामान का बड़ा कारोबार होता है, जहां देशभर से व्यापारी खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। दिल्ली स्टील टूल्स एंड हार्डवेयर ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार, स्टील और लोहे की कीमतों में अचानक वृद्धि ने कारोबारियों का बजट बिगाड़ दिया है। जिस दर पर पहले माल बेचा गया, उसी कीमत पर अब नया स्टील खरीदना संभव नहीं

रह गया है। इससे बाजार में नकदी का प्रवाह भी प्रभावित हुआ है और व्यापारियों की पूंजी पर संकट गहरा गया है। छोटे कारोबारों पर असर इस कारोबार से जुड़े हजारां छोटे कारोबार और मैकेनिक सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कच्चे माल की बढ़ती कीमत और काम में कमी के कारण उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। निर्माण और इंधनसंस्करण से जुड़े कार्य धीमे पड़ते जा रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी घट रहे हैं। व्यापारियों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। व्यापारियों के अनुसार, कच्चे माल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ठोस नीति बनाई जानी चाहिए। साथ ही, आयात शुल्क और जीएसटी में अस्थायी राहत दी जाए ताकि छोटे व्यापारियों को राहत मिल सके। उत्पादन ठप, बाजार में कमी - युद्ध के कारण राजधानी में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कई छोटी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जबकि बड़े उद्योगों का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। पीपल स्क्रैप की

कीमत कुछ ही महीनों में 520 रुपये प्रति किलो से बढ़कर करीब 740 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं, पीवीसी उत्पादों के दाम में 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है। बाजार में ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है और बाहरी व्यापारियों ने भी खरीदारी सीमित कर दी है। ऐसे में व्यापारी अतिरिक्त भविष्य को लेकर चिंतित हैं और हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं।

कीमत कुछ ही महीनों में 520 रुपये प्रति किलो से बढ़कर करीब 740 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं, पीवीसी उत्पादों के दाम में 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है। बाजार में ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है और बाहरी व्यापारियों ने भी खरीदारी सीमित कर दी है। ऐसे में व्यापारी अतिरिक्त भविष्य को लेकर चिंतित हैं और हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं।

कीमत कुछ ही महीनों में 520 रुपये प्रति किलो से बढ़कर करीब 740 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं, पीवीसी उत्पादों के दाम में 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है। बाजार में ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है और बाहरी व्यापारियों ने भी खरीदारी सीमित कर दी है। ऐसे में व्यापारी अतिरिक्त भविष्य को लेकर चिंतित हैं और हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं।

कीमत कुछ ही महीनों में 520 रुपये प्रति किलो से बढ़कर करीब 740 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं, पीवीसी उत्पादों के दाम में 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है। बाजार में ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है और बाहरी व्यापारियों ने भी खरीदारी सीमित कर दी है। ऐसे में व्यापारी अतिरिक्त भविष्य को लेकर चिंतित हैं और हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं।

कीमत कुछ ही महीनों में 520 रुपये प्रति किलो से बढ़कर करीब 740 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं, पीवीसी उत्पादों के दाम में 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है। बाजार में ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है और बाहरी व्यापारियों ने भी खरीदारी सीमित कर दी है। ऐसे में व्यापारी अतिरिक्त भविष्य को लेकर चिंतित हैं और हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं।

कीमत कुछ ही महीनों में 520 रुपये प्रति किलो से बढ़कर करीब 740 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं, पीवीसी उत्पादों के दाम में 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है। बाजार में ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है और बाहरी व्यापारियों ने भी खरीदारी सीमित कर दी है। ऐसे में व्यापारी अतिरिक्त भविष्य को लेकर चिंतित हैं और हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं।

द्वारका सेक्टर 6 में मुख्य सड़क की स्ट्रीट लाइटें कई दिन से बंद, लोग चिंतित

नई दिल्ली। द्वारका सेक्टर 6 के आकाश गंगा अपार्टमेंट्स के सामने वाली मुख्य सड़क की स्ट्रीट लाइटें पिछले 5-6 दिनों से बंद हैं। यह समस्या प्लांट नंबर 17 के पास के रास्ते को अंधेरा और असुरक्षित बना रही है। स्थानीय निवासी अजय नांगिया ने बताया कि सड़क पर प्रकाश की कमी के कारण शाम के समय वहां चलना मुश्किल है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे इस समस्या पर ध्यान दें और जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइटें चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंधेरे में न केवल सड़क पर कार मुश्किल हो गया है, बल्कि रात के समय सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। प्रशासन की तरफ से इस मामले में कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। स्थानीय प्रशासन या विद्युत विभाग को तुरफ से जल्द समाधान न होने पर नागरिक सोशल मीडिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

नई दिल्ली। द्वारका सेक्टर 6 के आकाश गंगा अपार्टमेंट्स के सामने वाली मुख्य सड़क की स्ट्रीट लाइटें पिछले 5-6 दिनों से बंद हैं। यह समस्या प्लांट नंबर 17 के पास के रास्ते को अंधेरा और असुरक्षित बना रही है। स्थानीय निवासी अजय नांगिया ने बताया कि सड़क पर प्रकाश की कमी के कारण शाम के समय वहां चलना मुश्किल है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे इस समस्या पर ध्यान दें और जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइटें चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंधेरे में न केवल सड़क पर कार मुश्किल हो गया है, बल्कि रात के समय सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। प्रशासन की तरफ से इस मामले में कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। स्थानीय प्रशासन या विद्युत विभाग को तुरफ से जल्द समाधान न होने पर नागरिक सोशल मीडिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

नई दिल्ली। द्वारका सेक्टर 6 के आकाश गंगा अपार्टमेंट्स के सामने वाली मुख्य सड़क की स्ट्रीट लाइटें पिछले 5-6 दिनों से बंद हैं। यह समस्या प्लांट नंबर 17 के पास के रास्ते को अंधेरा और असुरक्षित बना रही है। स्थानीय निवासी अजय नांगिया ने बताया कि सड़क पर प्रकाश की कमी के कारण शाम के समय वहां चलना मुश्किल है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे इस समस्या पर ध्यान दें और जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइटें चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंधेरे में न केवल सड़क पर कार मुश्किल हो गया है, बल्कि रात के समय सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। प्रशासन की तरफ से इस मामले में कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। स्थानीय प्रशासन या विद्युत विभाग को तुरफ से जल्द समाधान न होने पर नागरिक सोशल मीडिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

नई दिल्ली। द्वारका सेक्टर 6 के आकाश गंगा अपार्टमेंट्स के सामने वाली मुख्य सड़क की स्ट्रीट लाइटें पिछले 5-6 दिनों से बंद हैं। यह समस्या प्लांट नंबर 17 के पास के रास्ते को अंधेरा और असुरक्षित बना रही है। स्थानीय निवासी अजय नांगिया ने बताया कि सड़क पर प्रकाश की कमी के कारण शाम के समय वहां चलना मुश्किल है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे इस समस्या पर ध्यान दें और जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइटें चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंधेरे में न केवल सड़क पर कार मुश्किल हो गया है, बल्कि रात के समय सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। प्रशासन की तरफ से इस मामले में कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। स्थानीय प्रशासन या विद्युत विभाग को तुरफ से जल्द समाधान न होने पर नागरिक सोशल मीडिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

नई दिल्ली। द्वारका सेक्टर 6 के आकाश गंगा अपार्टमेंट्स के सामने वाली मुख्य सड़क की स्ट्रीट लाइटें पिछले 5-6 दिनों से बंद हैं। यह समस्या प्लांट नंबर 17 के पास के रास्ते को अंधेरा और असुरक्षित बना रही है। स्थानीय निवासी अजय नांगिया ने बताया कि सड़क पर प्रकाश की कमी के कारण शाम के समय वहां चलना मुश्किल है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे इस समस्या पर ध्यान दें और जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइटें चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंधेरे में न केवल सड़क पर कार मुश्किल हो गया है, बल्कि रात के समय सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। प्रशासन की तरफ से इस मामले में कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। स्थानीय प्रशासन या विद्युत विभाग को तुरफ से जल्द समाधान न होने पर नागरिक सोशल मीडिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

नई दिल्ली। द्वारका सेक्टर 6 के आकाश गंगा अपार्टमेंट्स के सामने वाली मुख्य सड़क की स्ट्रीट लाइटें पिछले 5-6 दिनों से बंद हैं। यह समस्या प्लांट नंबर 17 के पास के रास्ते को अंधेरा और असुरक्षित बना रही है। स्थानीय निवासी अजय नांगिया ने बताया कि सड़क पर प्रकाश की कमी के कारण शाम के समय वहां चलना मुश्किल है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे इस समस्या पर ध्यान दें और जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइटें चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंधेरे में न केवल सड़क पर कार मुश्किल हो गया है, बल्कि रात के समय सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। प्रशासन की तरफ से इस मामले में कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। स्थानीय प्रशासन या विद्युत विभाग को तुरफ से जल्द समाधान न होने पर नागरिक सोशल मीडिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

नई दिल्ली। द्वारका सेक्टर 6 के आकाश गंगा अपार्टमेंट्स के सामने वाली मुख्य सड़क की स्ट्रीट लाइटें पिछले 5-6 दिनों से बंद हैं। यह समस्या प्लांट नंबर 17 के पास के रास्ते को अंधेरा और असुरक्षित बना रही है। स्थानीय निवासी अजय नांगिया ने बताया कि सड़क पर प्रकाश की कमी के कारण शाम के समय वहां चलना मुश्किल है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे इस समस्या पर ध्यान दें और जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइटें चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंधेरे में न केवल सड़क पर कार मुश्किल हो गया है, बल्कि रात के समय सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। प्रशासन की तरफ से इस मामले में कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। स्थानीय प्रशासन या विद्युत विभाग को तुरफ से जल्द समाधान न होने पर नागरिक सोशल मीडिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

नई दिल्ली। द्वारका सेक्टर 6 के आकाश गंगा अपार्टमेंट्स के सामने वाली मुख्य सड़क की स्ट्रीट लाइटें पिछले 5-6 दिनों से बंद हैं। यह समस्या प्लांट नंबर 17 के पास के रास्ते को अंधेरा और असुरक्षित बना रही है। स्थानीय निवासी अजय नांगिया ने बताया कि सड़क पर प्रकाश की कमी के कारण शाम के समय वहां चलना मुश्किल है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे इस समस्या पर ध्यान दें और जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइटें चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंधेरे में न केवल सड़क पर कार मुश्किल हो गया है, बल्कि रात के समय सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। प्रशासन की तरफ से इस मामले में कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। स्थानीय प्रशासन या विद्युत विभाग को तुरफ से जल्द समाधान न होने पर नागरिक सोशल मीडिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

लाखों रुपये की गड़बड़ी में बैंक के कई कर्मचारियों की मिलीभगत

एजेंसी
सिरसा। सिरसा जिले के खंड बड़ागढ़ स्थित दि.के.के.ए.स.स. बैंक शाखा में उपभोक्ताओं के खाते से लाखों रुपये की ठगी के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट महाप्रबंधक को सौंप दी है, जिसके बाद बैंक प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए रिकवरी नोटिस जारी कर दिए हैं। महाप्रबंधक ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर राशि की रिकवरी नहीं होने पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ थाना में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। इस मामले में एसआईटी को 15 दिन में जांच पूरी करनी थी, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने में करीब 40 दिन लग गए। जांच के दौरान सबसे अहम तथ्य यह सामने आया कि मुख्य आरोपी कैशियर सुभाष चहल एक बार भी जांच में शामिल नहीं हुआ। उसे कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिलहाल फरार बताया जा रहा है। एसआईटी जांच में करीब 18 से 20 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है। जांच में कैशियर सुभाष के साथ शाखा प्रबंधक इंद्रपाल, पूर्व शाखा प्रबंधक ओमप्रकाश और कैशियर धर्मपाल को भी आरोपी ठहराया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि गबन के लिए विभिन्न अधिकारियों की गोपनीय आईडी का दुरुपयोग किया गया।

अनुपस्थित आईएसएस अधिकारी रानी नागर की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार वर्ष 2014 बैच की आईएसएस अधिकारी रानी नागर की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी में है। साढ़े पांच साल से अनुपस्थित चल रही विवादित अधिकारी के खिलाफ पांच मई 2022 को अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हुई थी। पिछले साल जुलाई में प्रदेश सरकार ने उन्हें जबनम सेवानिवृत्ति देने का निर्णय कर लिया था, लेकिन संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) ने इस पर रोक लगाते हुए उनका ग्रेड दो साल तक कम करने की सलाह देते हुए उनका पक्ष जानने के निर्देश दिए थे। तभी से रानी को पक्ष रखने के लिए लगातार ई-मेल के माध्यम से नोटिस भेजे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका जवाब सरकार को नहीं मिला है। अब कार्मिक विभाग की ओर से रानी को अंतिम नोटिस देते हुए जवाब दखिल करने को 15 दिन का समय दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि संच लोके सेवा आयोग द्वारा 30 मई 2024 को सलाह पर अपना जवाब इस अवधि में नहीं दिया तो मान लिया जाएगा कि उन्हें कुछ भी नहीं कहना है। इसके बाद नियमों के अनुसार उन्हें कोई और नोटिस दिए जाएंगे और कार्यभार को जारी रखा जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय से रानी की सेवाएं समाप्त करने की सिफारिश की जा सकती है।

सांसद नवीन जिंदल ने सुनी समस्याएं, टीम को दिए समाधान के निर्देश

कैथल। कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद नवीन जिंदल ने अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्र से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान जिले के विभिन्न गांवों और शहरों से पहुंचे लोगों ने अपनी-अपनी समस्याएं सांसद के समक्ष रखीं और उनके शीघ्र समाधान की मांग की। मुलाकात के दौरान सांसद नवीन ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की प्रशासनिक छिटाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद ने अपनी टीम को निर्देश देते हुए कहा कि सभी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रत्येक समस्या का समयबद्ध समाधान किया जाए। साथ ही उन्होंने विकास कार्यों की नियमित प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए, ताकि कोई भी कार्य लंबित न रहे और लोगों को समय पर राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का वास्तविक दायित्व समस्याओं का प्रभावी और स्थायी समाधान करना है। इसी उद्देश्य के साथ वे लगातार क्षेत्र के लोगों के संपर्क में रहते हैं और उनकी जरूरतों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर सांसद कार्यालय प्रभारी रविंद्र धीमान ने बताया कि सांसद नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं।

अनाज मंडी में तौल में गड़बड़ी पर सख्ती, 100 ग्राम कम वजन पाए जाने पर भरपाई के निर्देश

पानीपत। उपायुक्त वीरेंद्र कुमार दहिया ने इसराना की नई अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर्मियों की एक टोली के संबंधित किसान को पूरी ढेरी के लिए 100 ग्राम प्रति बोरी के हिसाब से भरपाई के निर्देश दिए। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि मंडी में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, और कहा कि चाहे बायोमेट्रिक सत्यापन हो या तौल संबंधी समस्या, यदि कहीं भी कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए संबंधित अधिकारी और आढ़ती जिम्मेदार द्वारा गाड़ियों के लिए पोर्टल पर मैसेज आ गया है। हैफेड के पोर्टल पर मैसेज आने ही लिफ्टिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि इस वर्ष किसानों को मंडी में सुविधाओं के साथ-साथ तौल और लिफ्टिंग की समस्या के लिए उच्च अधिकारियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

मातनहेल में तेज हुई जनगणना 2027 की तैयारियां, दूसरे चरण के प्रशिक्षण की शुरुआत

एजेंसी
इज्जर। मातनहेल में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए द्वितीय बैच के प्रशिक्षण का पहला दिन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को जनगणना कार्य से जुड़ी अहम जानकारियां दी गईं। प्रशिक्षण के आरंभ में मातनहेल के तहसीलदार कृष्ण कुमार ने दोनों बैचों के ट्रेनरों और प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए जनगणना की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जनगणना देश की योजनाओं और विकास की दिशा तय करने का सबसे बड़ा आधार है, इसलिए इस कार्य को पूरी जिम्मेदारी, ईमानदारी और सटीकता के साथ करना बेहद जरूरी है। इसके बाद फील्ड ट्रेनर राजेश कुमार और ओमबीर ने प्रतिभागियों को बिल्डिंग, सेंसस हाउस और हाउसहोल्ड की अवधारणाओं की विस्तार से



कार्य की व्यावहारिक समझ मिल सके। प्रशिक्षण के अगले सत्र में फील्ड ट्रेनर सबीन और पवन ने प्रतिभागियों को एचएलओ एप डाउनलोड करने और उसके उपयोग की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से

उत्कृष्ट सेवाओं पर इंजीनियर होशियार सिंह को प्रो. असीम कुमार घोष ने किया सम्मानित

एजेंसी
हिसार। हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डी.सी.बी.वी.एन.) के कार्यकारी अभियंता (सीबीओ) एवं एसजीआरए, इंजीनियर होशियार सिंह को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एसजीआरए के रूप में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने पर सम्मानित किया यह सम्मान उन्हें चंडीगढ़ में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किया गया।

इंजीनियर होशियार सिंह ने एसजीआरए के रूप में अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन करते हुए उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित एवं संतोषजनक निपटान में



महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके उत्कृष्ट कार्य और समर्पण के लिए उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने इंजीनियर

होशियार सिंह को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि उनकी कार्यशीलता, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा अन्य अधिकारियों के लिए प्रेरणास्रोत है।

हरियाणा में तेज होगी फाइल निपटान प्रक्रिया

एजेंसी
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सभी विभागों, बोर्डों, निगमों तथा स्वायत्त संस्थाओं को सीएफएमएस एवं टीआईएस पोर्टल पर लंबित फाइलों की समीक्षा कर उन्हें 15 दिनों के भीतर निपटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव अनुपम रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2025 और 2026 से संबंधित बड़ी संख्या में फाइलें पोर्टल पर 'पेंडिंग' श्रेणी में दर्ज हैं। इनमें से कई फाइलें भौतिक रूप से निपटाई जा चुकी हैं, लेकिन उनकी स्थिति पोर्टल पर अपडेट नहीं की गई है, जिसके कारण लंबित मामलों की संख्या वास्तविकता से अधिक दिखाई दे रही है। सरकार ने सभी विभागों की स्थिति नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की विसंगति न रहे और फाइलों की वास्तविक स्थिति का सटीक आकलन किया जा सके। इस संबंध में सभी प्रशासनिक

सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को 15 दिनों के भीतर यह कार्य पूरा करने को कहा गया है। निर्धारित समयविधि के बाद पोर्टल पर



दर्शाए गए लंबित मामलों के आंकड़ों को अंतिम और प्रमाणिक माना जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में सभी फाइलों की स्थिति नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की विसंगति न रहे और फाइलों की वास्तविक स्थिति का सटीक आकलन किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर में सुनी जनता की फरियाद

तुरंत कार्रवाई के निर्देश

62 परिवारियों से किया सीधा संवाद, राशन कार्ड मामले में आय सत्यापन के आदेश, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

अटेली क्षेत्र से पहुंची ललिता की राशन कार्ड संबंधी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता से संज्ञान



लिया। उन्होंने उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार को निर्देश दिए कि संबंधित परिवार की आय का दोबारा सत्यापन कराया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि यदि जांच के दौरान महिला निर्धारित आय सीमा के भीतर पात्र पाई जाती है, तो बिना किसी देरी के

उसका राशन कार्ड बनाया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तुरंत बाद उपायुक्त ने संबंधित

संबंधित करते हुए उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि यह शिविर हरियाणा सरकार का एक अत्यंत प्रभावी मंच है, जहां आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं इन शिविरों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। उपायुक्त ने चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती गई, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर डीएसपी सुरेश कुमार, डीएसपी रणवीर सिंह और नाराधीश डॉ. मंगल सेन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

सीएम घोषणा के तहत सैनी सभा को 31 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान

एजेंसी
नारनौला। आज नारनौला उप मंडल अधिकारी (नागरिक) अनिरुद्ध यादव ने अपने कार्यालय में सैनी सभा के प्रधान बिशन सैनी, सचिव भारत सैनी एवं कोषाध्यक्ष बलवंत सैनी को सरकार की ओर से 31 लाख रुपये की सहायता राशि का चेक भेंट किया। यह राशि पूर्व में आयोजित महाराज शूर सैनी जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई घोषणा के अंतर्गत जारी की गई है। कार्यक्रम के दौरान की गई घोषणाओं के क्रम में यह 31 लाख रुपये की पहली किस्त के रूप में प्रदान की गई सहायता राशि है।

इस अवसर पर एसडीएम अनिरुद्ध यादव ने बताया कि यह राशि घोषित योजनाओं के तहत जारी की गई है और आगे भी शेष राशि चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। सैनी सभा के प्रधान बिशन सैनी, सचिव भारत सैनी एवं कोषाध्यक्ष बलवंत सैनी ने मुख्यमंत्री एवं प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग समाजहित के कार्यों एवं विकास गतिविधियों में किया जाएगा।

संयोजित करते हुए उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि यह शिविर हरियाणा सरकार का एक अत्यंत प्रभावी मंच है, जहां आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं इन शिविरों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। उपायुक्त ने चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती गई, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर डीएसपी सुरेश कुमार, डीएसपी रणवीर सिंह और नाराधीश डॉ. मंगल सेन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को पूरी तरह प्रशिक्षित और जागरूक बनाना है, ताकि वे फील्ड में जाकर जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक और सटीक तरीके से पूरा कर सकें।

करने के लिए किसानों से अनेक प्रकार के कागज लिए। फिर गेट पास के लिए ट्रैक्टर और ट्रॉली पर नंबर और बायोमेट्रिक सत्यापन की शर्त लगाई, जिसमें से कुछ नियमों को इनलेन के दबाव में हटा दिया गया, जबकि बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी बेमतलब की

शर्त अभी भी किसानों के लिए पेशानियों का सबब बनी हुई है। इनलेन ने किसानों की फसल बेचने में मदद करने के लिए सभी मंडियों में किसान कष्ट निवारण केंद्र खोले जा चुके हैं और किसानों को इससे बहुत लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक इनलेन द्वारा की गई

हरियाणा सरकार ने कोटक बैंक को पैनल से हटाया

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने पंचकूला नगर निगम से जुड़े 160 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में कोटक महिंद्रा बैंक को पैनल लिस्ट से हटा दिया है। वित्त विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को इसकी सूचना लिखित रूप में भेज दी है। कोटक महिंद्रा बैंक ने राज्य सरकार को 127 करोड़ रुपये लौटा दिए हैं। यह राशि केवल मूलधन को ही कवर करती है। हरियाणा सरकार को भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो वर्तमान में पंचकूला नगर निगम के सेक्टर 11 स्थित कोटक महिंद्रा बैंक शाखा में खातों से कथित तौर पर धन की हेराफेरी की जांच कर रहा है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा है कि कोटक महिंद्रा बैंक को हरियाणा राज्य में सरकारी कामकाज करने के लिए तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक पैनल से हटा दिया गया है।

रेशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिश, एचएसएससी को मजबूत ढांचा प्रदान करे सरकार

एजेंसी
चंडीगढ़। हरियाणा राज्य के रेशनलाइजेशन कमीशन ने अपनी मुख्य सचिव की 27वीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट हरियाणा स्टॉफ सिलेक्शन कमीशन (एचएसएससी) के पुनर्गठन एवं युक्तिकरण से संबंधित है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, एचएसएससी राज्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है, जिसे ग्रुप-सी एवं ग्रुप-डी के पदों पर भर्ती के लिए सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार के लगभग 85-90 प्रतिशत पद इन्हीं श्रेणियों में आते हैं। उन्होंने बताया कि कमीशन ने एचएसएससी के अध्यक्ष, सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर उनके समक्ष आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। एचएसएससी को करीब 400

विभिन्न प्रकार के पदों के लिए भर्ती संबंधी सिफारिशें करनी होती हैं, जिसके कारण इसकी कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाना आवश्यक है। रिपोर्ट में कमीशन ने सुझाव दिया है कि एचएसएससी के लिए एक मजबूत और सुव्यवस्थित संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जाए, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ शाखाएं स्थापित की जाएं। इनमें गोपनीय शाखा, भर्ती शाखा, स्कूटिनी शाखा, परीक्षा शाखा, प्रशिक्षण एवं विधिक शाखा आदि शामिल हों, ताकि भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और कुशल बन सके। प्रवक्ता ने आगे बताया कि कमीशन अब तक विभिन्न सरकारी विभागों के युक्तिकरण से संबंधित 26 रिपोर्ट (जिनमें तीन सामान्य रिपोर्टें शामिल हैं) प्रस्तुत कर चुका है।

आईडीएफसी बैंक घोटाले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा : विज

एजेंसी
चंडीगढ़। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आईडीएफसी बैंक में लगभग 560 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर कहा कि "लगभग 560 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है और इस घोटाले में कुछ लोग खा गए और अपने खातों में भी राशि डाल ली या जो कुछ भी किया गया है, इसलिए सरकार इस मामले में सरकारी किसी को भी नहीं बखोसीगी"।

इसके अलावा, विज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मामले को सीबीआई को दिया जाएगा। विज मीडिया कर्मियों द्वारा बैंक घोटालों को लेकर आज दो आईएसएस अधिकारी और एक एचसीएस अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा निर्वासित किए जाने के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। "घोटालों के इन मामलों में

में कई लोगों को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है" - विज

विज ने कहा कि "घोटालों के इन मामलों में कई लोगों को पहले भी



गिरफ्तार किया जा चुका है और बैंक के अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है कि हम यह मामला सीबीआई को दे देंगे और, जब सीबीआई को मामला जाएगा तो

देखा कि कैसे लाईन लगती है"। "अब हम असम भी जीतेंगे, बंगाल भी जीतेंगे, केरल भी जीतेंगे, तमिलनाडु और पुडुचेरी भी जीतेंगे"।

"सरकार द्वारा मंडियों में फसल उपज की सुरक्षा हेतु सारी व्यवस्थाएं भी की जा रही है" - विज

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा मंडियों में किए जा रहे दौरों के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने ब्यानी प्रहार करते हुए कहा कि "हुड्डा साहब खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने समय में कुछ भी नहीं किया लेकिन अब हम कर रहे हैं, तो उसमें कमी निकाल रहे हैं"। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि "बरसात हमारी सरकार पैदा नहीं कर रही है, बरसात ऊपर से आ रही है, और इसके लिए फसल उपज की सुरक्षा हेतु सारी व्यवस्थाएं भी की जा रही है"।

सोनीपत में भीषण सड़क हादसा : बर्थडे मनाने आ रहे परिवार की कार को ट्रक ने 100 मीटर तक घसीटा, दो सगी बहनों की मौत

एजेंसी

सोनीपत (हरियाणा)। नेशनल हाईवे-44 पर शुक्रवार की सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। दिल्ली के उत्तम नगर से मुथल में बेटे का जन्मदिन मनाने आ रहे एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने सर्विस लेन पर खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी और उसे करीब 100 मीटर तक घसीटा हुआ ले गया। इस भीषण टक्कर में दो सगी बहनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मिली जानकारी के अनुसार, उत्तम नगर निवासी परिवार का में सवार होकर मुथल के ढाबे पर जन्मदिन सेलिब्रेट करने जा रहा था। जब उनकी कार राई थाना क्षेत्र के पास गोल्डन हट ढाबे के सामने सर्विस लेन में रुकी और एक सदस्य चिल्ले लेने नीचे उतरा, तभी पीछे से आए एक ट्रक ने रेलिंग तोड़ते हुए कार को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकाला। हादसे में मनदीप कौर और मनीषी कौर नामक दो बहनों की मौके पर ही जान चली गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर घायलों को सोनीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके पर ही वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश की जा रही है। परिजनों के आने के बाद मृतकों और घायलों की विस्तृत शिनाख्त की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।



एजेंसी
बहादुरगढ़। इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा की विभिन्न अनाज मंडियों में गेहूं खरीद की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शीला नर्फ सिंह राठी ने इनेलो

नेताओं के साथ बहादुरगढ़ की अनाज मंडी में जोरदार प्रदर्शन किया और किसान कष्ट निवारण केंद्र स्थापित किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर पोर्टल की तकनीकी खामियों और बायोमेट्रिक प्रक्रिया लागू करने से किसानों को परेशानियों देने का आरोप भी लगाया।

लेकर कड़ी आपत्ति जताई। इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शीला नर्फ सिंह राठी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों पर इतनी कठोर शर्तें थोपी दी हैं जो अब किसानों के लिए जो का जंजाब बन गई हैं। पहले तो बीजेपी सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्टर

करने के लिए किसानों से अनेक प्रकार के कागज लिए। फिर गेट पास के लिए ट्रैक्टर और ट्रॉली पर नंबर और बायोमेट्रिक सत्यापन की शर्त लगाई, जिसमें से कुछ नियमों को इनलेन के दबाव में हटा दिया गया, जबकि बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी बेमतलब की

शर्त अभी भी किसानों के लिए पेशानियों का सबब बनी हुई है। इनलेन ने किसानों की फसल बेचने में मदद करने के लिए सभी मंडियों में किसान कष्ट निवारण केंद्र खोले जा चुके हैं और किसानों को इससे बहुत लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक इनलेन द्वारा की गई

मांगों, जैसे 24 घंटे मंडियों को खोलने, ट्रैक्टर और ट्रॉली पर नंबर प्लेट हटाना, फसल खरीद केंद्र के लिए लाइसेंस रिन्यू करने और मेरी फसल मेरा ब्योरा के पोर्टल को खोलने की चार मांगों को मान चुकी है जिसका श्रेय चौधरी अध्यक्ष सिंह चौटाला को जाता है।

किसान अपनी फसल को सुचारू रूप से मंडियों में बेच सके उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि बायोमेट्रिक सत्यापन की शर्त को तुरंत हटाए सरकार। अगर घोटाले रोकने हैं तो अधिकारियों और व्यापारियों की मिलीभगत रोकें, लेकिन को नहीं रोकेंगे।

बायोमेट्रिक सत्यापन की शर्त हटाकर किसानों को राहत दे सरकार : शीला नर्फे सिंह राठी

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

संसेक्स 918, निफ्टी 275 अंक ऊपर आया

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुआ। समाह के अंतिम कारोबारी दिन दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीदारी हावी होने से बाजार में ये तेजी आई है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई संसेक्स 918.60 अंक बढ़कर 77,550.25 जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 275.50 अंक उछलकर 1.10 24,050.60 पर बंद हुआ। बाजार में बढ़त ऑटो स्टॉक्स में

तेजी से आई है। इस कारण निफ्टी ऑटो में सबसे अधिक 2.85 फीसदी की तेजी रही जबकि निफ्टी रियल्टी में 2.08 फीसदी और निफ्टी फार्मेशियल सर्विसेज में 2.06 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक 2.01 फीसदी, निफ्टी की तेजी के साथ बंद हुआ। सूचकांकों में केवल निफ्टी आईटी ही 1.91 फीसदी गिरावट पर बंद हुआ।

आज लाजकैप के साथ ही मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी उछाल आया। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 865.20 अंक बढ़कर 57,843.95 और निफ्टी

स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 274.10 अंक ऊपर आकर 16,840.10 पर बंद हुआ। संसेक्स पैक में एशियन पेटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, एमएडएम्, इंडिगो, एसबीआई, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अदाणी पोर्टर्स, ट्रेट, एचडीएफसी बैंक, एलएंडटी, एचयूएल, पावर ग्रिड, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा स्टील, बीईएल और एनटीपीसी के शेयर लाभ में रहे थे जबकि सन फार्मा, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक के

शेयर गिरे हैं। इससे पहले आज सुबह बाजार की मजबूती के साथ शुरुआत हुई। संसेक्स 77,198 अंक पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 577.35 अंक की बढ़त के साथ 77,209 के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी 50 भी मजबूती के साथ 23,880 पर खुला। एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने भी बाजार को सपोर्ट दिया। हालांकि, वैश्विक स्तर पर यूएस-ईरान तनाव अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। इस कारण निवेशक पूरी तरह



बेफिक्र नहीं हैं और सतर्कता के साथ निवेश कर रहे हैं।

इंदौर व्यापार महोत्सव में साबु ट्रेड करेगा न्यूट्रीदाना का प्री-लॉन्च

स्टाल नंबर 7 पर मिलेगा शुद्धता और स्वाद का संगम

इंदौर। इंदौर में माहेश्वरी समाज द्वारा आयोजित दो दिवसीय व्यापार महोत्सव में देश की प्रतिष्ठित खाद्य उत्पाद कंपनी साबु ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, सेलम अपनी विशेष

उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। 11 और 12 अप्रैल को आयोजित होने वाले इस महोत्सव में कंपनी न केवल अपने लोकप्रिय उत्पादों का प्रदर्शन करेगी, बल्कि अपने आगामी इनोवेटिव उत्पाद सच्चासाबु न्यूट्रीदाना की पहली झलक भी पेश करेगी।

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया शुक्रवार को 35 पैसे की गिरावट के साथ ही 92.85 पर बंद हुआ। आज सुबह रुपया 10 पैसे की तेज होकर 92.41 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा

विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.58 पर खुला। फिर शुरुआती कारोबार में 92.41 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 10 पैसे की बढ़त दिखाता है। रुपया गुरुवार को तीन पैसे की

मामूली बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.51 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.07 फीसदी की बढ़त के साथ 98.69



पर रहा।

एडीबी ने भारत की विकास दर 6.9 फीसदी रहने का अनुमान लगाया

- घरेलू मांग और आसान वित्तीय परिस्थितियों से वृद्धि मजबूत रहने की उम्मीद



नई दिल्ली।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। बैंक के अनुसार मजबूत घरेलू मांग और आसान वित्तपोषण परिस्थितियां अर्थव्यवस्था को सहारा देंगी। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है

ऊर्जा कीमतों में वृद्धि, व्यापार बाधाएं और रेगुलेशन में कमी के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। एडीबी ने अनुमान लगाया है कि मुद्रास्फीति 2025-26 के 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 2026-27 में 4.5 प्रतिशत हो सकती है, जिसका कारण तेल कीमतों में वृद्धि, मुद्रा में कमजोरी और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव है।

हालांकि 2027-28 में तेल कीमतों में नरमी से मुद्रास्फीति घटकर लगभग 4 प्रतिशत रहने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार घरेलू सुधार, यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते और सरकारी वेतन वृद्धि भविष्य में आर्थिक विकास को और गति दे सकते हैं।

कि भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका के कम शुल्क और निवेश माहौल में सुधार से भी वृद्धि को समर्थन मिलेगा। वहीं 2027-28 में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 7.3 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पश्चिम एशिया में लंबे समय तक संघर्ष जारी रहने से

भारत एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ढांचा अपनाए, बढ़ेगी दक्षता और घटेगा लाभों का दोहराव एडीबी

- पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और दिव्यांगता लाभों को जोड़ने से बेहतर लक्ष्यकरण और कम होगा राजकोषीय बोझ

नई दिल्ली।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत को सलाह दी है कि वह अपनी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ढांचा अपनाए। इससे न केवल योजनाओं में दोहराव कम होगा, बल्कि लाभार्थियों तक सहायता बेहतर तरीके से पहुंच सकेगी और सरकारी खर्च अधिक संतुलित होगा। एडीबी ने अपनी एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। बैंक ने कहा है कि भारत को एक एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ढांचा अपनाना चाहिए, जिससे विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय बढ़े और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। रिपोर्ट के

अनुसार वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों की कई योजनाएं समान लाभार्थी समूहों को कवर करती हैं, लेकिन इनके बीच समन्वय सीमित है। इसके कारण कई बार एक ही व्यक्ति या परिवार को अलग-अलग योजनाओं से समान प्रकार के लाभ मिल जाते हैं, जिसे 'लाभों का दोहराव' कहा जाता है। एडीबी ने सुझाव दिया कि पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और दिव्यांगता कवरेज जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक साझा ढांचे में जोड़ा जाए। इसमें अंशदायी योजनाओं को भी शामिल किया जा सकता है, जिससे लाभ वितरण अधिक व्यवस्थित और लक्षित हो सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सामाजिक सुरक्षा की जरूरतें राज्यों की जनसंख्या संरचना, रोजगार पैटर्न और वित्तीय क्षमता के अनुसार अलग-अलग होती हैं।



इसलिए एकीकृत ढांचा राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लचीलापन देगा। मनीला स्थित इस बहुपक्षीय संस्था ने यह भी बताया कि इस सुधार से सरकारें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सुरक्षा भूमिका को बनाए रखते हुए राजकोषीय लागत को नियंत्रित कर सकेंगी। इससे बचने वाले संसाधनों को बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी जैसे क्षेत्रों में लगाया जा सकता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी हैं। एडीबी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

प्रणाली को और मजबूत करने की भी सिफारिश की है, ताकि सत्यापित लाभार्थियों तक ही सहायता पहुंचे और अनावश्यक दोहराव कम हो। इसके अलावा रिपोर्ट में उपभोग आधारित सब्सिडी से हटकर निवेश आधारित सहायता पर जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए, मुफ्त बिजली की जगह घरों में सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना, जिससे सरकारी खर्च कम होगा और परिवारों की आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी।

आरबी आई डिजिटल भुगतान में सुरक्षा बढ़ाने नए नियम लागू करेगी

- बड़े लेनदेन में देरी से क्रेडिट, डिजिटल भुगतान को बंद करने का विकल्प

मुंबई।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल भुगतान प्रणाली में बढ़ती धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई नए और सख्त सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव रखा है। इनमें बड़े लेनदेन में देरी से क्रेडिट, डिजिटल भुगतान को बंद करने का विकल्प और कमजोर वर्गों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा शामिल है। केंद्रीय बैंक ने इस पर सुझाव और प्रतिक्रिया 8 मई तक मांगी है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने डिजिटल भुगतान प्रणाली में तेजी से बढ़ रही धोखाधड़ी पर चिंता जताते हुए एक चर्चा पत्र जारी किया है। इसमें

ग्राहकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। सबसे प्रमुख प्रस्ताव के अनुसार, 10,000 रुपये से अधिक के पुरा पेंमेंट लेनदेन पर राशि को तुरंत खाली में जमा करने के बजाय लगभग एक घंटे की देरी से क्रेडिट किया जाएगा। इस दौरान ग्राहक के पास ट्रांजैक्शन रद्द करने का विकल्प रहेगा। इससे फर्जी लेनदेन पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा आरबीआई ने 'किल स्विच' प्रणाली का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत ग्राहक अपने सभी डिजिटल भुगतान विकल्पों को एक क्लिक में बंद कर सकेंगे। आवश्यकता

पड़ने पर उचित प्रमाणीकरण के बाद ही इन्हें दोबारा चालू किया जा सकेगा। बैंक ने खाताधारकों को यह सुविधा देने का भी सुझाव दिया है कि वे अपने खाते में विभिन्न प्रकार के डिजिटल लेनदेन की सीमाएं तय कर सकें। साथ ही, सौम्य गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ खातों में क्रेडिट सीमा लगाने का भी प्रस्ताव है, ताकि मूल अकाउंट जैसी धोखाधड़ी पर रोक लग सके। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा का भी प्रावधान सुझाया गया है। इनके बड़े डिजिटल लेनदेन के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त



अनुमति की आवश्यकता हो सकती है। आरबीआई ने यह भी बताया कि डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, 2025 में लगभग 28 लाख मामले दर्ज हुए, जिनमें हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी शामिल है।

आपूर्ति संकट और मध्य पूर्व तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी

- होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा और अमेरिका-ईरान तनाव से ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई में बढ़त

मुंबई।

वैश्विक कच्चे तेल बाजार में शुक्रवार को फिर तेजी देखने को मिली, जब भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति बाधाओं की आशंकाओं ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। अमेरिका-ईरान सीजफायर को लेकर अनिश्चितता, मध्य पूर्व में सैन्य तनाव और प्रमुख समुद्री मार्गों पर जोखिम के कारण तेल की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया। ब्रेंट क्रूड 1.13 प्रतिशत बढ़कर 97.01 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि वेस्ट टैक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 1.39

प्रतिशत बढ़कर 99.24 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता नजर आया। भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी असर दिखा, जहां 20 अप्रैल डिलीवरी वाला क्रूड ऑयल फ्यूचर्स करीब 2.43 प्रतिशत की बढ़त के साथ 9,150 रुपये प्रति बैरल पर पहुंच गया। बाजार में यह तेजी ऐसे समय आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर स्पष्टता नहीं है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के साथ-साथ सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचे पर हमलों की आशंका और स्पलाई चैन बाधित होने के डर ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। सबसे बड़ा जोखिम स्ट्रेट आफ

होर्मुज में देखा जा रहा है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। रिपोर्टों के अनुसार, इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से शिपिंग गतिविधियां सामान्य स्तर से काफी कम हो गई हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई पर दबाव बना है। मध्य पूर्व में इजरायल और लेबनान के बीच जारी तनाव ने भी स्थिति को और जटिल बना दिया है। वहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी है कि यदि सीजफायर की शर्तों का पालन नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि उन्होंने इसे कम संभावना वाला



बताया है। विश्लेषकों के अनुसार कुछ दिन पहले तेल कीमतों में करीब 20 प्रतिशत की गिरावट आई थी, लेकिन मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों ने बाजार को फिर अस्थिर कर दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा है कि जब तक तनाव कम नहीं होता, तब तक तेल की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं, हालांकि दीर्घकाल में स्थिरता की उम्मीद की जा सकती है।

इफ्टी न्यूचुअल फंड में मार्च में निवेश 56 फीसदी बढ़कर 40,450 करोड़

- गोल्ड ईटीएफ में निवेश घटकर 2,266 करोड़ रुपये रह गया

नई दिल्ली।

मार्च महीने में बाजार में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद निवेशकों का भरोसा शेयर आधारित म्यूचुअल फंडों में बना रहा। इफ्टी योजनाओं में तेज वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि डेट फंडों से भारी निकासी ने कुल उद्योग आंकड़ों को प्रभावित किया। मार्च महीने में भारतीय शेयर आधारित म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेशकों का भरोसा मजबूत बना रहा, जिससे शुद्ध निवेश 56 प्रतिशत बढ़कर 40,450 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। फरवरी में यह आंकड़ा 25,978 करोड़ रुपये था। बाजार में उतार-चढ़ाव और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद इफ्टी योजनाओं में लगातार निवेश बढ़ा, जिसका मुख्य कारण फ्लेक्सि कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंडों में भारी प्रवाह रहा। फ्लेक्सि कैप फंड में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश दर्ज किया गया, जबकि स्मॉल कैप में 6,263 करोड़ रुपये और मिड कैप में 6,063 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। व्यवस्थित निवेश योजना यानी एसआईपी के माध्यम से भी निवेश बढ़कर 32,087 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले महीने से अधिक है। हालांकि इंग्लिसएस श्रेणी में मामूली निकासी देखी गई। वहीं गोल्ड ईटीएफ में निवेश घटकर 2,266 करोड़ रुपये रह गया। दूसरी ओर डेट फंडों से भारी निकासी के कारण पूरे उद्योग में कुल 2.4 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी दर्ज हुई, जिससे एयूएम घटकर 73.73 लाख करोड़ रुपये रह गया। यह प्रवृत्ति निवेश धारणा में बदलाव को दर्शाती है।

रियल एस्टेट दिवाला मामलों में परियोजना पूर्णता को प्राथमिकता देने की सिफारिश

- आईबीबीआई की विशेष समिति ने 155 सुझाव दिए, घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा पर जोर



नई दिल्ली।

रियल एस्टेट क्षेत्र के दिवाला मामलों के समाधान में अब वित्तीय वसूली की बजाय अटकी परियोजनाओं को पूरा करने पर अधिक ध्यान देने का सुझाव दिया गया है। रियल एस्टेट से जुड़े दिवाला मामलों में घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए परियोजना-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की गई है। भारतीय दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा गठित एक विशेष समिति ने सुझाव दिया है कि ऐसे मामलों में पूरी कंपनी को दिवालिया घोषित करने के बजाय केवल अटकी हुई परियोजनाओं के समाधान पर ध्यान दिया जाए। समिति का मानना है कि इस क्षेत्र में खरीदारों की प्राथमिकता पैसा वापस पाने के बजाय अपने घर का निर्माण पूरा होना और कब्जा प्राप्त करना होती है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गठित इस समिति में कॉरपोरेट मामलों और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति ने 55 प्रमुख मुद्दों की समीक्षा कर 155 सिफारिशें की हैं। इसमें आईबीसी और रेग के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया है ताकि परियोजनाएं समय पर पूरी हों और खरीदारों का भरोसा मजबूत हो सके।

गोदरेज प्रॉपर्टीज की बिक्री बुकिंग रिकॉर्ड स्तर पर

- कंपनी की बिक्री 16 प्रतिशत बढ़ी, 34,171 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार



नई दिल्ली।

रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 में मजबूत आवासीय मांग के दम पर अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी की बिक्री बुकिंग सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 34,171 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि इस दौरान उसने 32,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था, जिसे उसने आसानी से पार कर लिया। इस अवधि में कुल 17,515 आवासीय इकाइयों की बिक्री हुई, जिनका संयुक्त क्षेत्रफल लगभग 2.7 करोड़ वर्ग फुट रहा। मात्रा के आधार पर बिक्री में भी सालाना 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी का यह अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक बुकिंग मूल्य और वॉल्यूम बताया जा रहा है। कंपनी के एक वे रिष्ठ अे धिकारी के अनुसार यह प्रदर्शन भारत के प्रमुख महानगरों में मजबूत आवासीय मांग को दर्शाता है। कंपनी का फोकस भविष्य में भी परियोजनाओं के विस्तार और निवेश पर रहेगा।

रुपया 10 पैसे की बढ़त के साथ 92.41 प्रति डॉलर पर

- रुपया गुरुवार को डॉलर के मुकाबले 92.51 पर बंद हुआ था

मुंबई। रुपया शुक्रवार को 10 पैसे मजबूत होकर 92.41 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि रुपये में कारोबार के दौरान भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है क्योंकि बैंकों को अपने ओवरनाइट पोजिशन को 10 करोड़ डॉलर तक सीमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के निर्देशों की समय सीमा आज समाप्त हो रही है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.58 पर खुला। फिर शुरुआती कारोबार में 92.41 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 10 पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया गुरुवार को तीन पैसे की मामूली बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.51 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 98.69 पर रहा।

राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव 2026



विनोद कुमार सिंह

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों ने इस लोकतांत्रिक उत्सव को और अधिक अर्थपूर्ण बना दिया है। असम में लगभग 85 प्रतिशत से अधिक मतदान, केरल में लगभग 78 प्रतिशत और पुदुचेरी में लगभग 90 प्रतिशत के आसपास रिकॉर्ड मतदान यह स्पष्ट संकेत देता है कि भारत का मतदाता अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय और निर्णायक मागीदार बन चुका है। यह आंकड़े केवल प्रतिशत नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति जनता के विश्वास, उसकी प्रतिबद्धता और उसकी आकांक्षाओं का जीवंत प्रमाण हैं।

प्रथम चरण का मतदान मंजमत की गूंज, लोकतंत्र का आत्मविश्वास और बदलते राजनीतिक संकेत...

हमारा लोकतंत्र केवल एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं, बल्कि जनचेतना की वह जीवंत धारा है, जो समय-समय पर अपने स्वरूप, अपने तेवर और अपनी दिशा को स्वयं निर्धारित करती है। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनावों का प्रथम चरण - असम, केरल और केन्द्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में सम्पन्न मतदान - इसी लोकतांत्रिक चेतना का प्रखर और व्यापक प्रतिबिंब बनकर सामने आया है। यह चरण केवल मतपेटियों तक सीमित एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनमत की वह गूंज है जिसमें सामाजिक परिवर्तन की आहट, राजनीतिक पुनर्संतुलन की छया और भविष्य की राजनीति की स्पष्ट रूपरेखा सुनाई देती है।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों ने इस लोकतांत्रिक उत्सव को और अधिक अर्थपूर्ण बना दिया है। असम में लगभग 85 प्रतिशत से अधिक मतदान, केरल में लगभग 78 प्रतिशत और पुदुचेरी में लगभग 90 प्रतिशत के आसपास रिकॉर्ड मतदान यह स्पष्ट संकेत देता है कि भारत का मतदाता अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय और निर्णायक मागीदार बन चुका है। यह आंकड़े केवल प्रतिशत नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति जनता के विश्वास, उसकी प्रतिबद्धता और उसकी आकांक्षाओं का जीवंत प्रमाण हैं। असम में उच्च मतदान यह संकेत देता है कि वहां चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि जनसरोकारों की अभिव्यक्ति का मंच बन चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक जिस प्रकार मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, वह इस बात का द्योतक है कि मतदाता अब अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग और सचेत हैं। यह उत्साह जहां एक ओर सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती का संकेत देता है, वहीं दूसरी ओर यह भी दर्शाता है कि यदि सरकार ने अपने कार्यों से जनविश्वास अर्जित किया है, तो उसे पुनः अक्सर भी मिल सकता है।

केरल का मतदान प्रतिशत अपनी प्रकृति में भले ही संतुलित प्रतीत होता हो, लेकिन उसकी गहराई में एक परिपक्व लोकतांत्रिक चेतना का प्रवाह दिखाई देता है। यहाँ का मतदाता परंपरागत रूप से विचारधारा आधारित मतदान करता है और यही कारण है कि मतदान का प्रतिशत स्थिर रहते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत देता है। लगभग 78 प्रतिशत मतदान यह बताता है कि केरल में लोकतंत्र केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक वैचारिक अभ्यास है, जिसमें हर मतदाता अपने निर्णय को एक जिम्मेदारी के रूप में देखता है। पुदुचेरी में लगभग 90 प्रतिशत के आसपास मतदान ने यह



सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र का उत्साह क्षेत्रफल या जनसंख्या पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जनभागीदारी की भावना पर आधारित होता है। छोटे से केन्द्र शासित प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का मतदान करना यह दर्शाता है कि लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। यह मतदान न केवल राजनीतिक दलों के लिए संदेश है, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा भी है कि लोकतंत्र की असली शक्ति जनता की सक्रिय भागीदारी में निहित है। इस प्रथम चरण का एक और महत्वपूर्ण पक्ष मतदाता संरचना में हो रहा परिवर्तन है। लगभग 5.3 करोड़ से अधिक मतदाताओं की भागीदारी यह दर्शाता है कि लोकतंत्र अब केवल संख्याओं का खेल नहीं, वरन् विविधता और समावेश का उत्सव बन चुका है। महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या और उनकी सक्रिय भागीदारी इस परिवर्तन का सबसे सशक्त संकेत है। केरल और पुदुचेरी जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर या उससे अधिक होना केवल एक सांख्यिकीय तथ्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का संकेत है।

महिलाएं अब केवल मतदान करने वाली इकाई नहीं, बल्कि नीति निर्धारण को प्रभावित करने वाली शक्ति बन चुकी हैं। इनके मुद्दे अब चुनावी विमर्श के केंद्र में हैं - चाहे वह महंगाई हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों, शिक्षा हो या सुरक्षा राजनीतिक दलों ने भी इस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है और महिला मतदाताओं को ध्यान में रखकर योजनाएं और घोषणाएं प्रस्तुत की हैं। यह

स्पष्ट है कि आने वाले समय में महिला मतदाता भारतीय राजनीति की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। युवा मतदाताओं की भागीदारी इस चुनाव की आत्मा है। लाखों नए मतदाताओं का पहली बार मतदान करना यह दर्शाता है कि भारत का भविष्य अब मतदान केंद्रों तक पहुंच चुका है। यह युवा वर्ग पारंपरिक राजनीति से अलग सोच रखता है। इसके लिए जातीय या धार्मिक समीकरणों की अपेक्षा रोजगार, शिक्षा, डिजिटल अवसर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा अधिक महत्वपूर्ण हैं। यह केवल वादों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि परिणाम चाहता है, पारदर्शिता चाहता है और अवसर चाहता है। यही कारण है कि आज की राजनीति में युवाओं की भूमिका केवल सहायक नहीं, बल्कि निर्णायक बन चुकी है। पुरुष मतदाताओं की भूमिका अब भी महत्वपूर्ण है, लेकिन महिला और युवा मतदाताओं के उभार ने चुनावी समीकरणों को अधिक संतुलित और प्रतिस्पर्धी बना दिया है। यह परिवर्तन लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है, क्योंकि इससे चुनाव अधिक निष्पक्ष और परिणाम अधिक प्रतिनिधिक बनते हैं। अगर हम वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो असम, केरल और पुदुचेरी तीनों ही क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार के चुनावी समीकरण देखने को मिल रहे हैं। असम में जहां भाजपा ने तृत्व वाले गठबंधन और काँग्रेस गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, वहीं केरल में पारंपरिक एल डी एफ (छउअर) और यू डी एफ (वउअर) के बीच वैचारिक संघर्ष जारी है। पुदुचेरी में त्रिकोणीय मुकाबला चुनाव को और

अधिक जटिल और रोचक बना रहा है। असम में उच्च मतदान यह संकेत देता है कि चुनावी अल्पमत प्रतिस्पर्धी है। राजनीतिक विक्षेपकों का मानना है कि यदि सत्तारूढ़ गठबंधन अपने लाभार्थी वर्ग और महिला मतदाताओं का समर्थन बनाए रखने में सफल रहता है, तो उसे बढ़त मिल सकती है, लेकिन उच्च मतदान अक्सर सत्ता विरोधी भावना का भी संकेत होता है, जिससे चुनाव परिणाम अनिश्चित हो जाता है। केरल में स्थिति और भी जटिल है, क्योंकि वहां का मतदाता अत्यंत जागरूक और वैचारिक है। यहाँ चुनाव परिणाम बहुत ही सूक्ष्म अंतर से तय होते हैं और यही कारण है कि दोनों प्रमुख गठबंधन पूरी ताकत से मैदान में हैं। पुदुचेरी में रिकॉर्ड मतदान यह संकेत देता है कि मतदाता परिवर्तन चाहता है या स्पष्ट जनादेश देना चाहता है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले के कारण यहां हंग असेंबली की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

मतदान प्रतिशत के भीतर छिपे राजनीतिक संकेतों को यदि समझा जाए कि उच्च मतदान केवल संख्या नहीं, बल्कि एक संदेश है। यह संदेश कभी बदलाव का होता है, कभी समर्थन का और कभी संतुलन का। महिला मतदाताओं की सक्रियता यह दर्शाती है कि कल्याणकारी योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा अब राजनीति के केंद्र में हैं। युवा मतदाताओं की भागीदारी यह बताती है कि भविष्य की राजनीति विकास और अवसरों के इर्द-गिर्द घूमनी। प्रथम चरण का यह मतदान यह भी स्पष्ट करता है कि भारतीय लोकतंत्र अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। यह दौर परंपरागत समीकरणों से आगे बढ़कर विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित है। मतदाता अब केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, वरन् अपने अनुभव और अपेक्षाओं के आधार पर निर्णय लेता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 2026 के विधानसभा चुनावों का प्रथम चरण केवल एक चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक आत्मविश्वास का सशक्त प्रमाण है। यह वह क्षण है जब राज्य का हर नागरिक यह महसूस करता है कि उसकी आवाज महत्वपूर्ण है, उसका वोट मूल्यवान है और उसका निर्णय देश के भविष्य को दिशा देने में सक्षम है।

यह केवल मतदान नहीं, बल्कि जनविश्वास का उत्सव है। यह केवल मतदान के आंकड़े नहीं, बल्कि जनभावनाओं की अभिव्यक्ति है। मतदाताओं की यही अभिव्यक्ति भारत के लोकतंत्र को न केवल जीवित रखती है, बल्कि उसे निरंतर सशक्त और समृद्ध भी बनाती है। (स्वतंत्र पत्रकार व स्तम्भकार)

संपादकीय

घातक किशोर अपराध

बदलते वक्त के साथ समाज में बढ़ते आक्रामक व्यवहार के चलते अपराधों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन किशोरों की अपराधों में संतुलितता बढ़ना गंभीर चिंता का विषय है। हाल के दिनों में देश में किशोर अपराधों से जुड़ी अनेक ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने देश को गहरी चिंता में डाला है। जो बाल अपराधों के सामाजिक कारणों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत पर बल देता है। निस्संदेह, यह विचारणीय प्रश्न है कि छोटे-छोटे विवादों के बीच किशोर हिंसक क्यों हो रहे हैं। जिसकी परिणति अक्सर क्रूर हत्या के रूप में सामने आती है। पिछले दिनों दिल्ली के दयालपुर क्षेत्र में सिर्फ चार सौ रुपये के विवाद में एक युवक की निर्मम हत्या डराने वाली है। वहीं किशोरों में कानून का भय न होना गंभीर मसला है। बताया जाता है कि इस युवक की हत्या में तीन नाबालिग संलिप्त थे। इस घटना में तीन किशोर एक युवक पर लगातार चाकू मारते रहे। हिंसक प्रवृत्ति की पराकाष्ठा देखिए कि इनका चौथा साथी बाकायदा मोबाइल पर घटना का वीडियो बनाता रहा। निस्संदेह, यह घटना किसी भी सभ्य समाज में सहन पैदा करने वाली है कि किशोरों में यह अपराधिक दुस्साहस कहाँ से आ रहा है। जाहिर बात है कि इन किशोरों में पुलिस-प्रशासन का कोई भय नहीं था, तभी वे सरेआम चाकूबाजी करते रहे। देश की राष्ट्रीय राजधानी जहाँ के बारे में अक्सर कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाने में अग्रणी रहता है, वहाँ यह घटना सामने आयी। सवाल उठाना जा सकता है कि देश के दूर-दराज के इलाकों में यह स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि किशोरों की अपराधिक घटनाओं में तेजी से बढ़ती भूमिका की असली वजह क्या है? उल्लेखनीय है कि दयालपुर की घटना से पहले भी कई गंभीर अपराधों में किशोरों की संलिप्तता की घटनाएं गाढ़े-बगाहे सामने आती रही हैं। लेकिन किशोर अपराध से जुड़े कानून उन्हें जल्दी रिहा करा देते हैं। दरअसल, देश में अक्सर किशोरों के गंभीर अपराधों में लिप्त होने के चलते उनकी वयस्क होने की उम्र घटाने की मांग होती है। इसकी वजह यह है कि किशोर गंभीर अपराधों में संलिप्तता के बावजूद किशोर अपराध से जुड़े कानूनों के लचीलेपन के चलते जेल से जल्दी रिहा हो जाते हैं। जेल से बाहर आने के बाद फिर दूसरे गंभीर अपराधों में लिप्त हो जाते हैं।

चिंतन-मनन

सर्वत्यापी है आत्मा

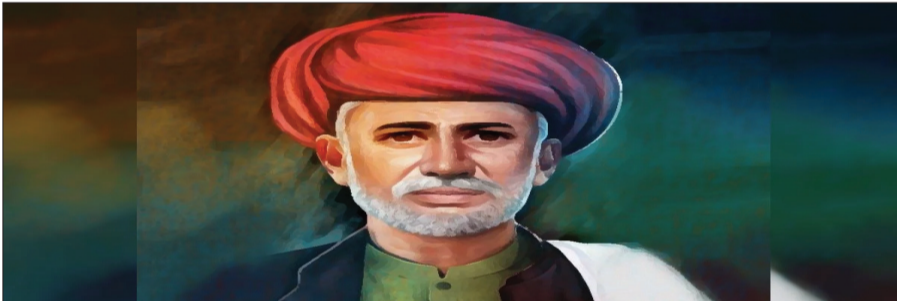
केवल वह जो क्षणिक है, छोटा या नर है, उसे ही सुरक्षा की आवश्यकता है, जो स्थायी है, बड़ा या विशाल है, उसे सुरक्षा की जरूरत नहीं। सुरक्षा का अर्थ है समय विशेष को लंबा कर देना; इसीलिए सुरक्षा परिवर्तन में बाधक भी होती है। पूर्ण सुरक्षा की स्थिति में रूपांतरण नहीं हो सकता। सुरक्षा के बिना इच्छित रूपांतरण नहीं हो सकता। एक बीज को पौधे में परिवर्तित होने के लिए सुरक्षा चाहिए; एक पौधे के वृक्ष बनने के लिए सुरक्षा चाहिए। अत्यधिक सुरक्षा रूपांतरण में या तो सहायक हो सकती है या बाधक, इसीलिए रक्षक को यह समझ होनी चाहिए कि किस मात्रा तक उसे रक्षा करनी है। सुरक्षा और रूपांतरण- दोनों काल और समय के अनुसार होते हैं और समय से परे होने के लिए इन नियमों का सम्मान आवश्यक है। सुरक्षा एक विशेष समय और नर चीजों तक ही सीमित है। चिकित्सक कब तक किसी को स्वस्थ रख सकता है या बचा सकता है? सदा के लिए? नहीं। सत्य को किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। शांति और खुशी को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे क्षणिक नहीं। तुम्हारे शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता है, तुम्हारी आत्मा को नहीं; तुम्हारे मन को सुरक्षा की जरूरत है, स्वरूप को नहीं। आत्मा केवल मन और शरीर का समिश्रण नहीं है। आत्मा न मन है, न शरीर। शरीर के अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य है तुम्हें सचेत करना कि तुम कितने सुंदर हो; और तुमको जागरूक करना कि तुम जिन आदर्शों का सम्मान करते हो, उन सभी को तुम अपने जीवन में ढालकर, अपने चारों ओर एक दिव्य-जगत की सृष्टि करो। जो योगासन तुम करते हो, वह शरीर के लिए और जो ध्यान करते हो, वह मन के लिए है। शांत हो या विचलित; मन, मन ही रहता है। रोगी हो या निरोगी; शरीर, शरीर ही रहता है। आत्मा सर्वव्यापी है। शरीर के किसी अंग को उतेजित करने से मजा आता है, सुख का आभास होता है। जब आत्मा का उदीपन होता है, प्रेम जागृत होता है। प्रेम अनंत है, परंतु सुख सीमित है। प्रायः व्यक्ति समझते हैं कि सुख ही प्रेम है। सुख और प्रेम के फर्क को केवल भाग्यशाली ही समझ सकता है।



दिलीप कुमार पाठक

इतिहास अक्सर उन लोगों को भूल जाता है जो किसी भया इमारत की नींव में ईंट बनकर समा जाते हैं। लेकिन जब-जब आधुनिक भारत में न्याय और बराबरी की बात होगी, ज्योतिबा फुले का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। फुले कोई पारंपरिक नेता नहीं थे, वे एक ऐसे दूरदृष्ट शि्षक थे जिन्होंने ब्लैकबोर्ड पर अक्षर लिखने से पहले समाज की कड़वी सच्चाइयों और गरीबों के आंसू पढ़ना सीखा था। आज हम जिस आधुनिक भारत में सांस ले रहे हैं, जहाँ महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और समाज का हर वर्ग तरक्की के सपने देख रहा है, उसकी पहली मजबूत ईंट 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले ने ही रखी थी। वह एक ऐसा दैतृ था जब शिक्षा पर कुछ खाल लोगों का एकाधिकार था और समाज के एक बहुत बड़ी आबादी अज्ञानता के घने अंधेरे में कैद थी। ज्योतिबा ने बहुत कम उम्र में ही यह समझ लिया था कि किसी को गुलाम बनाने के लिए लोहे की जंजीरें जरूरी नहीं होतीं, बल्कि उसने अधिकांश के पिंजरे में कैद रखना ही काफी होता है। उन्होंने बड़ी बेबाकी से समाज को आईना

सत्यशोधक ज्योतिबा फुले: जिनके विचारों ने बदली समाज की दिशा



दिखाते हुए कहा था- शिक्षा के बिना ईंसान की बुद्धि मर जाती है और बुद्धि के बिना उसका विकास और नैतिकता हमेशा के लिए रुक जाती है। ज्योतिबा फुले के जीवन का सबसे साहसी अध्याय उनकी जीवनसंगिनी सावित्रीबाई फुले के साथ जुड़ा है। उन्होंने किसी बड़े मंच से केवल भाषण देने के बजाय, बदलाव की शुरुआत अपने घर से की। उस कट्टर समाज की कल्पना कीजिए, जहाँ औरतों का पढ़ना एक महापाप माना जाता था, वहाँ ज्योतिबा अपनी पत्नी के हाथ में कलम और किताब थमा रहे थे। जब सावित्रीबाई स्कूल पढ़ने निकलती थीं और उन पर गोबर और कीचड़ फेंका जाता था, तो ज्योतिबा एक चट्टान की तरह उनके पीछे खड़े रहते थे। यह उन दोनों का अटूट साहस और जित में ही थी, जिसने 1848 में पुणे के भिडेवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूल का रास्ता खोला और सदियों पुराने बंद दरवाजे हमेशा के लिए तोड़ दिए। फुले के सुधार केवल स्कूलों की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहे। उनकी पत्नी नजर समाज की हर उस बुराई पर थी जो एक

ईंसान को दूसरे ईंसान से छोटा समझती थी। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों को अंधविश्वासों के मानसिक चंगुल से बाहर निकालना था। वे केवल बातों के धनी नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने सिद्धांतों को जीकर दिखाया। जब अक्षरों के लिए पानी पीना भी अपराध माना जाता था, तब उन्होंने अपने खुद के घर का पानी का टैंक उनके लिए खोल दिया। यह उस समय के कट्टरपंथी समाज के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। वे जानते थे कि जब तक एक आम ईंसान अपनी नजरों में खुद को गौरवशाली नहीं समझेगा, तब तक वह समाज में अपना हक कभी नहीं मांग पाएगा। अक्सर हम फुले को इतिहास की एक पुरानी तस्वीर मानकर दीवार पर टांग देते हैं, लेकिन उनके विचार आज के आधुनिक युग में भी उतने ही अनिवार्य हैं। आज हमारे पास बड़ी-बड़ी डिग्रियां तो हैं, लेकिन क्या हमारे भीतर वह सामाजिक चेतना है जो फुले पैदा करना चाहते थे? उन्होंने स्पष्ट कहा था कि शिक्षा का असली मकसद केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि खुद को स्वतंत्र बनाना और समाज के प्रति संवेदनशील होना है।

राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस: हर माँ की सुरक्षा का संकल्प

कोई बीमारी नहीं है और किसी भी महिला को जीवन देते समय अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने सुरक्षित मातृत्व के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, जबकि अन्य देश और वैश्विक संगठन सामान्यतः 28 मई को 'इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमन हेल्थ' मनाते हैं। यह दिवस कस्तूरबा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षित प्रसव के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। साबरमती आश्रम में उन्होंने महिलाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और उस समय, जब स्वास्थ्य सुविधाएं अत्यंत सीमित थीं, वे स्वयं एक कुशल प्रसव सहायिका के रूप में कार्य करती थीं तथा ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए शिक्षित करती थीं। इस प्रकार यह दिवस उनके मौन लेकिन महत्वपूर्ण योगदान को स्मरण करने का अवसर भी है।

बहरहाल, यहाँ पाठकों को बताता चूँ कि हमारे देश में मातृ स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' के अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क विशेषज्ञ जांच की सुविधा प्रदान की जाती है। 'जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम' के तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसव, भोजन और जांच की सुविधा मिलती है। इसके अतिरिक्त, 'नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी' के माध्यम से पारंपरिक दाइयों को अनुभव को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जोड़कर एमिडवाइफरी लेड केयर यूनिट्स स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे प्रसव प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, सज्ज और कम तनावपूर्ण बनाया जा सके। वास्तव में, यह कालिंके-तारिफ है कि पिछले एक

दशक में भारत ने मातृ मृत्यु दर में लगभग 70 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की है और आज लगभग 90 प्रतिशत प्रसव अस्पतालों में (संस्थागत प्रसव) हो रहे हैं, जबकि 2003 में यह संख्या काफी कम थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) घटकर 88 प्रति लाख जीवित जन्म हो गया है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के निर्धारित लक्ष्य (100 से कम) से बेहतर है। यदि वैश्विक स्तर पर तुलना करें तो 1990 के बाद से भारत ने अपनी मातृ मृत्यु दर में लगभग 86 प्रतिशत की कमी हासिल की है, जबकि इसी अवधि में वैश्विक औसत गिरावट केवल 48 प्रतिशत रही है। वर्तमान में भारत का लक्ष्य 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप इस दर को 70 से नीचे लाना है। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने उल्लेख प्रदर्शन करते हुए मातृ मृत्यु दर को 40 से नीचे ला दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम में यह दर अभी राष्ट्रीय औसत से अधिक है, फिर भी संस्थागत प्रसव में वृद्धि के कारण वहाँ तेजी से सुधार हो रहा है। इस सफलता के पीछे 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' और 'लक्ष्य' जैसे कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिनसे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, विशेषकर लेबर रूम सुविधाओं में सुधार हुआ है। साथ ही, व्यापक टीकाकरण, बेहतर पोषण और प्रसव के दौरान प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता ने मातृ स्वास्थ्य की स्थिति में व्यापक बदलाव लाया है।

प्रत्येक वर्ष इस दिवस को एक थीम निर्धारित की जाती है। वर्ष 2024 की थीम स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य रखी गई थी, जिसका उद्देश्य गर्भावस्था की शुरुआत से ही माँ और शिशु के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करना था। वर्ष 2025 की थीम समान मातृत्व देखभाल: हर माँ का अधिकार रही, जबकि वर्ष

आज जब हम समाज में बढ़ती नफरत और भेदभाव की नई दीवारें देखते हैं, तो फुले की गुलामगिरी जैसी कालजयी रचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि असली मानसिक आजादी पाना अभी भी एक लंबा संघर्ष है। महात्मा फुले ने कभी अपने व्यक्तिगत सुख या आराम की चिंता नहीं की। अपनी प्रतिभा और पढ़ाई के दम पर वे चाहते तो एक बहुत ही समृद्ध जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने उन लोगों के लिए काटों भरा रास्ता चुना जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े थे। यही कारण है कि जिनता ने उन्हें अपने दिल से महात्मा की उपाधि दी थी। उनकी लड़ाई किसी विशेष धर्म या जाति के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उनकी जंग उस अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध थी जो ईंसान और ईंसान के बीच ऊंच-नीच की दीवार खड़ी करती थी। वे किसानों के दुख-दर्द को भी उतनी ही शिद्दत से समझते थे और उनके शोषण के खिलाफ हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे। 11 अप्रैल का यह दिन हमें रकबर यह आत्मचिंतन करने का मौका देता है कि हम फुले के सपनों के भारत के कितने करीब पहुँचे हैं। क्या आज हर गाँव के बच्चे के हाथ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है? क्या आज भी हमारी महिलाएं समाज में पूरी तरह सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करती हैं? महात्मा फुले ने जो मशाल डेढ़ सौ साल पहले जलाई थी, उसे बुझने न देना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आइए, आज हम फुले के उन सिद्धांतों को याद करें जो कहते हैं कि ज्ञान ही वह एकमात्र प्रकाश है जो हमें अंधकार से बाहर निकालकर सम्मान का जीवन दिला सकता है। उनका संघर्ष हमें भरोसा दिलाता है कि अगर हमारे इरादे नेक हों, तो एक अकेला व्यक्ति भी वक्त की धारा को मोड़ने का दम रखता है।



2026 की थीम सुरक्षित मातृत्व के लिए नवाचार और सुलभ स्वास्थ्य सेवा निर्धारित की गई है। अंततः, यही कहना कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस केवल एक जागरूकता दिवस नहीं, बल्कि एक मानवीय और सामाजिक दायित्व का प्रतीक है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति उसकी माताओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य से मापी जाती है। जब तक हर गर्भवती महिला को समय पर उचित देखभाल, पर्याप्त पोषण, प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवाएं और सम्मानजनक व्यवहार नहीं मिलेगा, तब तक विकास अधूरा रहेगा। इस दिवस का मूल संदेश यही है कि सुरक्षित मातृत्व कोई विकल्प नहीं, बल्कि हर महिला का मौलिक अधिकार है। वास्तव में, सामूहिक प्रयासों, जन-जागरूकता और सशक्त स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के माध्यम से ही हम एक ऐसा समाज व देश बना सकते हैं, जहाँ हर माँ सुरक्षित हो और हर नवजीवन स्वस्थ भविष्य की ओर अग्रसर हो।

संक्षिप्त समाचार

नाइजीरिया के दो गांवों पर बंदूकधारियों ने किया हमला, कम से कम 20 लोगों की मौत

अबुजा, एजेंसी। नाइजीरिया के उत्तर-मध्य क्षेत्र में बंदूकधारियों ने दो गांवों पर हमला कर कम से कम 20 लोगों की हत्या कर दी। स्थानीय निवासियों ने यह जानकारी दी है। ये हमले मंगलवार तड़के नाइजर राज्य के शिरोरो क्षेत्र में स्थित बगना और एरेना गांवों में हुए। शिरोरो, राजधानी अबुजा से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। एरेना के निवासी जिब्रिन इसाह ने बताया, 'हमलावर मोटरसाइकिलों पर आए और अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। यह तड़के का समय था, इसलिए हमला पूरी तरह से अचानक हुआ।' स्थानीय लोगों के अनुसार, हमले में 20 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई लोग अब भी लापता हैं। हालांकि, पुलिस ने केवल तीन लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावर कई घंटों तक गांवों में सक्रिय रहे, घरों में लूटपाट की और लोगों को जान बचाने के लिए पड़ोसी इलाकों में भागने पर मजबूर कर दिया।

शेख हसीना के 'सियासी अंत' पर मुहर? : आवासी लीग आतंकी संगठन घोषित, बांग्लादेश संसद ने लगाया स्थायी वेन

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश की संसद ने बेहद सख्त कानून पारित किया है। इसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवासी लीग पर लगे प्रतिबंध को आधिकारिक कानूनी मोहर लगा दी गई है। अब आवासी लीग बांग्लादेश में एक प्रतिबंधित संगठन है। संसद में गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने इस विधेयक को पेश किया। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर आवासी लीग का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह कानून एक ऐसी संस्था को प्रतिबंधित करने के लिए है जो 'नरसंहार और आतंकी गतिविधियों' में शामिल रही है। यह नया कानून पिछले 'आतंकवाद विरोधी अधिनियम' में संशोधन है, जिसे पहले मुहम्मद युनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने एक अघ्यादेश के जरिए लागू किया था। इस कानून के लागू होने के बाद अब आवासी लीग का चुनाव आयोग में पंजीकरण स्थायी रूप से रद्द रहेगा। पार्टी ने तो चुनाव लड़ सकेगी और न ही किसी तरह की राजनीतिक गतिविधि कर पाएगी। कानून में यह भी प्रावधान है कि सोशल मीडिया या मुख्यधारा की मीडिया में पार्टी के समर्थन में कोई भी बयान प्रकाशित करना अपराध माना जाएगा। यहां तक कि पार्टी के समर्थन में जुलूस निकालना या भाषण देना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस विधेयक का विरोध केवल बाहर से नहीं, बल्कि संसद के भीतर से भी हुआ है। मुख्य विपक्षी दल जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने बिल की समीक्षा के लिए और समय मांगा। वहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के मानवाधिकार अधिकारियों ने इस कदम की आलोचना की है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना लोकतंत्र के स्वस्थ भविष्य के लिए ठीक नहीं है। संवैधानिक विशेषज्ञ स्वाधीन मलिक ने कहा कि दुनिया के इतिहास में बांग्लादेश दूसरा ऐसा देश बन गया है, जिसने अपनी आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाली पार्टी को ही बेन कर दिया है।

ट्रंप को पसंद नहीं आया 10 शर्तों वाला पीएस प्लान, टूट जाएगा सीजफायर?

वाशिंगटन, एजेंसी। ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में हुआ दो हफ्तों का युद्धविराम अब अनिश्चितता के दौर में पहुंचता नजर आ रहा है। लेबनान पर लगातार हो रहे इजरायली हमलों के कारण तनाव बढ़ गया है। ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है कि यदि ये हमले नहीं रुके तो वह सीजफायर से पीछे हट सकता है। इसी बीच, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने ईरान के कथित 10 सूत्रीय प्रस्ताव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया था और इसे 'कूड़ेदान में फेंक दिया गया।' ईरान ने पहले दावा किया था कि उसका 10-पॉइंट प्रस्ताव अमेरिका को स्वीकार्य था, लेकिन लेविट ने इसे गलत बताया। उनके अनुसार, यह प्रस्ताव 'गेर-गंभीर' था और अमेरिकी नेतृत्व ने इसे बातचीत के लायक नहीं माना। हालांकि, बाद में ईरान की ओर से एक संशोधित योजना पेश की गई, जिसे अमेरिका ने अपने 15 सूत्रीय प्रस्ताव के साथ जोड़कर बातचीत के आधार के रूप में देखने की बात कही है। लेविट ने यह भी दोहराया कि ट्रंप प्रशासन की 'रेड लाइन' साफ है ईरान के भीतर यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान की 'विश लिस्ट' को किसी समझौते के रूप में स्वीकार करना संभव नहीं है। ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव में कई बड़ी मांगें शामिल थीं, जैसे उस पर किसी भी तरह का हमला न होना, होर्मुज जलडमरूमध्य पर उसका नियंत्रण बनाए रखना, यूरेनियम संवर्धन जारी रखने की अनुमति, सभी प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिबंधों को हटाना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को समाप्त करना, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रस्तावों को खत्म करना, मुआवजा देना और क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की वापसी। इसके अलावा, लेबनान सहित सभी मौकों पर युद्ध समाप्त करने की भी मांग की गई थी।

अमेरिका में जाति विवाद गहटाया: भारतीय और हिंदू समुदाय को निशाना बनाने का आरोप

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में जाति आधारित भेदभाव को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने कैलिफोर्निया की नागरिक अधिकार नियामक एजेंसी के खिलाफ नवीं संकट अपील न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। संगठन का आरोप है कि एजेंसी ने गलत तरीके से जाति को हिंदू धर्म से जोड़ते हुए भारतीय और दक्षिण एशियाई समुदायों को निशाना बनाया है।

6 अप्रैल को दाखिल अनुवाची याचिका में एचएएफ ने अदालत से अनुरोध किया है कि निचली अदालत द्वारा उसके मुकदमे को खारिज करने में जिन प्रक्रियात्मक बाधाओं का हवाला दिया गया था, उन्हें हटाया जाए। संगठन का कहना है कि जिला अदालत ने उसके दावों के मूल मुद्दों पर विचार किए बिना ही मामला खारिज कर दिया।

क्यों हो रहा यह विवाद : यह पूरा विवाद कैलिफोर्निया नागरिक अधिकार

विभाग द्वारा सिस्को सिस्टम्स और उसके दो प्रबंधकों के खिलाफ दर्ज शिकायत से जुड़ा है। इस शिकायत में जाति के आधार पर भेदभाव के आरोप लगाए गए थे और यह कार्रवाई कैलिफोर्निया के फेयर एम्प्लॉयमेंट एंड हाइसिंग एक्ट के तहत की गई थी। सीआरडी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उसने सिस्को और उसके पूर्व प्रबंधकों के खिलाफ जाति-आधारित भेदभाव का मामला दर्ज किया है। एचएएफ का आरोप है कि सीआरडी ने अपनी कार्रवाई में जाति को हिंदू धर्म और भारतीय मूल के कर्मचारियों से जोड़ने की कोशिश की। संगठन के मुताबिक, एजेंसी की शिकायत में जाति शब्द का बार-बार इस्तेमाल किया गया और यह धारणा बनाई गई कि भारतीय कर्मचारियों के बीच जाति-आधारित भेदभाव होता है, जिसे कंपनी को रोकना चाहिए था। एजेंसी की कार्रवाई नस्लवादी और तथ्यहीन धारणाओं पर आधारित है



संगठन ने यह भी कहा कि एजेंसी की प्रस्तुति भारतीय और हिंदुओं के बारे में नस्लवादी और तथ्यहीन धारणाओं पर आधारित है। एचएएफ ने सीआरडी के एक पुराने बयान का हवाला दिया, जिसमें भारत की जाति व्यवस्था को कठोर हिंदू सामाजिक और धार्मिक पदानुक्रम बताया गया था। हालांकि, बाद में विभाग ने इस विवादाित वाक्यांश को

हटा दिया और मामले को अप्रासंगिक बताया, लेकिन संगठन का कहना है कि इससे मूल समस्या खत्म नहीं होती। फाउंडेशन का कहना है कि हिंदू सामाजिक और धार्मिक पदानुक्रम जैसे शब्द हटाने के बावजूद सीआरडी अब भी कंपनी के धार्मिक पदानुक्रम और हिंदू धर्म के कर्मचारियों पर जाति से जुड़ी नीतियां लागू

पाकिस्तान की बड़ी फजीहत; ट्रंप की टीम ने देखा था शहबाज का ट्वीट, फिर दी पोस्ट करने की इजाजत

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका-ईरान संघर्ष में पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता की पूरी कहानी एक सोशल मीडिया गलती के कारण खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर युद्धविराम की अपील वाला पोस्ट डाला था, लेकिन उसमें ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मेसेज आन एक्स लिखा हुआ छूट गया। बाद में इसे एडिट कर हटा दिया गया, लेकिन स्क्रीनशॉट वायरल हो गए। कहा जा रहा है कि पाक पीएम ने ये पोस्ट अमेरिका के कहने पर पोस्ट की थी। अब खुद अमेरिकी मीडिया भी इस पर मुहर लगाती नजर आ रही है।

वाइट हाउस ने देखा था ट्वीट : न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वाइट हाउस ने इस पोस्ट को एक्स पर शेयर किए जाने से पहले ही देख लिया था और अपनी मंजूरी भी दे दी थी। यह खुलासा दर्शाता है कि पाकिस्तान की स्वतंत्र कूटनीतिक पहल असल में अमेरिका की तैयारी की गई स्क्रिप्ट थी।

दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलो, वरना अमेरिका ईरान के बुनियादी ढांचे और सभ्यता को नष्ट कर देगा। ट्रंप ने 7 अप्रैल (मंगलवार) को शाम 8 बजे (वाशिंगटन समय) तक की डेडलाइन दी थी। इसी बीच पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने



पिछले कई हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच गुप्त संपर्क साधे हुए थे। फाहनेशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, वाइट हाउस ने पाकिस्तान को इस अस्थायी युद्धविराम को फाइल कराने के लिए दबाव डाला था, ताकि ट्रंप सार्वजनिक रूप से धमकियां देते हुए भी पीछे हट सकें।

इसके बाद 8 अप्रैल को सुबह शहबाज शरीफ ने अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किया कि अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह का सीजफायर हो गया है। पोस्ट में ट्रंप, जेडी वेंस, ईरानी नेताओं और अन्य को टैग किया गया था। लेकिन असली पोस्ट के ऊपर 'ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मेसेज आन

एक्स' लिखा हुआ था, जो एडिट हिस्ट्री में साफ दिखाई दिया। शरीफ के स्टाफ ने इसे कॉपी-पेस्ट कर दिया और हटाया भूल गए। पाकिस्तानी अधिकारियों को खुद प्रधानमंत्री को 'पाकिस्तान पीएम' कहकर संबोधित करने की जरूरत नहीं होती- यह शब्द अमेरिकी या इजरायली ड्राफ्ट का संकेत था।

पढ़ें के पीछे की कहानी : न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि वाइट हाउस ने इस स्ट्रेटमेंट को पहले ही देख लिया था और मंजूरी दे दी थी। यानी पाकिस्तान की अपील असल में पहले से कोऑर्डिनेटेड थी। ट्रंप ने ट्यू सोशल पर लिखा कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और

फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद ईरान पर बमबारी दो हफ्तों के लिए रोकने का फैसला किया है। कुछ घंटों बाद शहबाज शरीफ ने दूसरा पोस्ट डालकर युद्धविराम की घोषणा का स्वागत किया।

पोस्ट के ड्राफ्ट वाले स्क्रीनशॉट वायरल हो गए। कई यूजर्स ने मजाक उड़ाया। लोग इसे कॉपी-पेस्ट पीएम, व्हाइट हाउस ने स्क्रिप्ट लिखी आदि कह रहे हैं। अमेरिकी पत्रकार रयान ग्रिम ने लिखा- शरीफ ने जो भेजा गया था, उसे कॉपी-पेस्ट कर दिया, जिसमें 'ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मेसेज आन एक्स' भी शामिल था। उनके अपने स्टाफ तो उन्हें ऐसे नहीं बुलाते।

पूर्व पीएम केपी ओली के बाद देखा पर भी बालेन सरकार ने कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वारंट जारी

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल की राजनीति में बड़ा उथल-पुथल देखने को मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने से सियासी माहौल गरमा गया है। इससे पहले केपी शर्मा ओली पर भी कार्रवाई की जा चुकी है, जिससे साफ है कि नई सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में सख्ती दिखा रही है।

इस पूरे मामले में काठमांडू जिला अदालत ने जांच एजेंसी की मांग पर यह वारंट जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फैसला जज महेंद्र खड्का की पीठ की मंजूरी के बाद लिया गया। जांच एजेंसी लंबे समय से देउबा, उनकी पत्नी और अन्य नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही थी। बताया जा रहा है कि पिछले साल सितंबर में हुए जेन-जेन ऑडिलन के दौरान कई नेताओं के घरों से जली हुई नकदी की तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे। इनमें देउबा के घर से जुड़े दृश्य भी थे। फॉरेंसिक जांच में इन नोटों के असली होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद मामला गंभीर हो गया और व्यापक जांच

शुरू की गई। जानकारी के अनुसार, देउबा और उनकी पत्नी इस समय नेपाल में नहीं हैं। दोनों 26 फरवरी को इलाज के लिए सिंगापुर गए थे और उसके बाद हांगकांग भी पहुंचे। अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई है, जिससे जांच एजेंसियों की कार्रवाई और तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी वारंट जारी करने का मकसद इंटरपोल रेड नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इससे विदेश में मौजूद आरोपियों को हिरासत में लेकर नेपाल लाया जा सकता है। पांच मार्च को हुए चुनाव के बाद नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। नई सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी से कार्रवाई शुरू हुई है। यही वजह है कि अब देउबा और अन्य नेताओं के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ाया गया है।

देउबा पांच बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 1991 से लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं। हालांकि हालिया घटनाक्रम और जांच के चलते उनका राजनीतिक भविष्य संकट में नजर आ रहा है। नई सरकार के सख्त रुख के कारण उनके लिए स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

'पूर्ण समझौते तक अमेरिकी सेना ईरान में रहेगी', ट्रंप का अल्टीमेटम; लेबनान पर फिर बरसे बम

वाशिंगटन, एजेंसी। ट्रंप ने कहा इसमें अमेरिकी जहाज, विमान और सैनिक शामिल होंगे, साथ ही अतिरिक्त गोला-बारूद, हथियार और वह सब कुछ जो दुश्मन के कमजोर किए गए ढांचे को पूरी तरह नष्ट करने के लिए जरूरी हो। राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि समझौते का पालन किसी भी कारण से नहीं हुआ, तो कार्रवाई बड़ी, मजबूत और ऐसी होगी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी। ट्रंप ने आगे कहा यह लंबे समय पहले तय हुआ था और सभी झूठी बातें और बयानबाजी के बावजूद कोई परमाणु हथियार नहीं होगा और होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह सुरक्षित और खुला रहेगा।

लेबनान से दगे गए रॉकेट को इस्त्राइल ने किया निष्क्रिय : इस्त्राइल सेना ने जानकारी दी है कि लेबनान की ओर से उतरी इस्त्राइल की दिशा में दगे गए एक रॉकेट को सफलतापूर्वक हवा में ही रोक दिया



गया। इस हमले के बाद गलील क्षेत्र में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बज उठे, जिससे इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब इस्त्राइल ने हाल ही में लेबनान पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक को अंजाम दिया है। इन हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं।

इस्त्राइल ने फिर दक्षिण लेबनान पर बरसाए बम : इस्त्राइल सेना ने एक बार फिर बेरूत

के दक्षिणी इलाकों पर हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हमला शहर के दक्षिणी अंगरों में किया गया। इसके अलावा इस्त्राइल ने दक्षिणी लेबनान के कई कस्बों सफाद अल-बतित, माजदल सेलेम, चाकरा और खेरबेत सेलेम पर भी बमबारी की है। हालांकि अभी हमलों में हुए नुकसान और हाताहतों की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। स्थिति को लेकर लगातार अपडेट का इंतजार किया जा रहा है। होर्मुज पर

फिर चलेंगी मिसाइलें, पाकिस्तान का कराया सीजफायर टूटने की कगार पर? ईरान ने दे दी धमकी



तेहरान, एजेंसी। पश्चिम एशिया में हुए सीजफायर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खबर है कि ईरान की तरफ से इजरायल को धमकी दी गई है। तेल अवीव को उड़ाने की धमकियां लेबनान में हुए हमले के जवाब में दी गई हैं। खास बात है कि मध्यस्थ पाकिस्तान ने कहा था कि सीजफायर में लेबनान में शांति भी शामिल है। जबकि, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि लेबनान को युद्धविराम समझौते में 'हिज्जल्लाह की वजह से' शामिल नहीं किया गया है। ट्रंप ने पीबीएस न्यूज आवर के साथ बातचीत में कहा, 'उन्हें समझौते में शामिल नहीं किया गया है। इसे भी ध्यान रखना चाहिए।' 'आगर कुछ घंटों में दक्षिण लेबनान में फायरिंग नहीं रुकी, तो एयर और मिसाइल यूनिट तेल अवीव में हमला करेंगी...।'

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था, 'मुझे लगता है कि ईरान और अमेरिका, अपने सहयोगियों के साथ, लेबनान और अन्य सभी जगहों पर तुरंत युद्धविराम के लिए सहमत हो गए हैं। यह फैसला अभी इसी वक्त से प्रभावित है।'

ट्रंप और जेडी वेंस दोनों ने मना कर दिया : अमेरिका के उप

यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने चाहिए। बयान के साथ ही इस जलमार्ग में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए नए मार्गों के स्पष्ट निर्देश भी शेयर किए गए हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच यह दो सप्ताह का संघर्ष विराम मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को हुआ। यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दी गई समझौते के तहत तेहरान ने दुनिया के सबसे व्यस्त तेल व्यापार मार्गों में से एक को अस्थायी रूप से खोलने पर सहमति जताई है।

अस्थायी युद्धविराम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का खुलना : अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमति बनी है। इसके तहत ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अस्थायी रूप से फिर से खोलने के लिए राजी हो गया है। गौरतलब है कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल का लगभग पांचवा हिस्सा (20%) इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है।

रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का बयान : ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने स्थानीय मीडिया के हवाले से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाजों को सूचित किया जाता है कि समुद्री सुरक्षा के सिद्धांतों का पालन करने और समुद्री माइन्स से सशक्त टकराव से बचने के लिए... उन्हें

ईरान का बड़ा फैसला, जहाजों के लिए नए रास्ते तय ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना ने होर्मुज में पाकिस्तानी जहाजों के लिए नए वैकल्पिक रास्तों का एलान किया है। यह कदम समुद्र में संभावित बाहरी सुरांगों (माइन्स) से जहाजों को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक, आईआरजीसी नौसेना ने सभी जहाजों को निर्देश दिया है कि वे इन तय मार्गों का पालन करें और उनकी निगरानी में ही गुजरें। नेत-यूह बोले- ईरान कमजोर, इस्त्राइल मजबूत; जीत अब तक की शानदार इस्त्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेत-यूह ने ट्वीट कर कहा कि इस्त्राइल ने अब तक की लड़ाई में शानदार जीत हासिल की है, जो पहले असंभव लगती थी। उनका कहना है कि अब ईरान पहले से कमजोर और इस्त्राइल पहले से मजबूत है।

फिर चलेंगी मिसाइलें, पाकिस्तान का कराया सीजफायर टूटने की कगार पर? ईरान ने दे दी धमकी

तेहरान, एजेंसी। पश्चिम एशिया में हुए सीजफायर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खबर है कि ईरान की तरफ से इजरायल को धमकी दी गई है। तेल अवीव को उड़ाने की धमकियां लेबनान में हुए हमले के जवाब में दी गई हैं। खास बात है कि मध्यस्थ पाकिस्तान ने कहा था कि सीजफायर में लेबनान में शांति भी शामिल है। जबकि, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि लेबनान को युद्धविराम समझौते में 'हिज्जल्लाह की वजह से' शामिल नहीं किया गया है। ट्रंप ने पीबीएस न्यूज आवर के साथ बातचीत में कहा, 'उन्हें समझौते में शामिल नहीं किया गया है। इसे भी ध्यान रखना चाहिए।' 'आगर कुछ घंटों में दक्षिण लेबनान में फायरिंग नहीं रुकी, तो एयर और मिसाइल यूनिट तेल अवीव में हमला करेंगी...।'

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था, 'मुझे लगता है कि ईरान और अमेरिका, अपने सहयोगियों के साथ, लेबनान और अन्य सभी जगहों पर तुरंत युद्धविराम के लिए सहमत हो गए हैं। यह फैसला अभी इसी वक्त से प्रभावित है।'

ट्रंप और जेडी वेंस दोनों ने मना कर दिया : अमेरिका के उप

हाईकोर्ट से सुक्खू सरकार को झटका: कोर्ट बोली- कानून भविष्य के लिए होते हैं, बदले के लिए नहीं

एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सुक्खू सरकार की राजनीति 'समान दृष्टि' नहीं बल्कि 'बदले की भावना' पर आधारित है। भाजपा प्रवक्ता आशीष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही झूठ गढ़ने, विपक्ष को निशाना बनाने और विरोध करने वाले नेताओं को परेशान करने की नीति अपनाई, लेकिन अब न्यायालय के फैसले ने उनके इस एजेंडे पर सीधा प्रहार किया है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश 07.04.2026 में स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित संशोधन विधेयक की प्रभावशीलता पूर्व प्रभाव नहीं हो सकती और यह केवल भविष्य (prospective) के लिए ही लागू होगा। न्यायालय ने साफ निर्देश दिए कि संबंधित पूर्व विधायकों को उनकी पेंशन एवं बकाया राशि एक माह के भीतर जारी की जाए, अन्यथा राज्य को 6फरवरी 2026 तक वैधानिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। भाजपा प्रवक्ता आशीष शर्मा ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 'यह फैसला सुक्खू सरकार के चेहरे पर तमाचा है। कांग्रेस ने कानून को बदले का हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन न्यायालय ने साफ कर दिया कि कानून किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि भविष्य के लिए बनाए जाते हैं।

बंगाल में बदलाव जरूरी, डबल इंजन सरकार लाएं : नितिन नवीन

मालदा। पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्य में बदलाव की अपील की। ओल्ड मालदा में आयोजित पार्टी बैठक में उन्होंने तुणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि तुणमूल शासन में 'मां, माटी, मातृपू'—तीनों ही संकट में हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा खतर में है, जमीन पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है और लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। राज्य के औद्योगिक हालात पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि एक समय का विकसित बंगाल अब उद्योगहीन हो गया है और युवाओं के पास रोजगार के अवसर नहीं हैं। लोगों की निर्भरता सिर्फ सरकारी भत्तों पर बढ़ गई है। उन्होंने राज्य की कला, संस्कृति और खेल जगत को लेकर भी सरकार की आलोचना की और कहा कि तुणमूल के शासन में इन क्षेत्रों का विकास रुक गया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को मजबूत करने और राज्य में 'डबल इंजन' सरकार लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा को सत्ता में लाना जरूरी है। इस बैठक को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया।

महाराष्ट्र के नासिक आईटी कंपनी में धर्म परिवर्तन मामले की छानबीन की जाएगी: देवेन्द्र फडणवीस

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि नासिक आईटी कंपनी में धर्म परिवर्तन मामले की गहन छानबीन की जाएगी और आरोपितों को कठोर सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया है, मामले की जांच सही दिशा में चल रही है। नासिक जिले के पुलिस अधीक्षक संदीप कोर्गिके ने मीडिया को बताया कि शहर में एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी के ऑफिस में 8 महिला कर्मचारियों के साथ छेड़छाड़ और एक महिला कर्मी के साथ यौन उत्पीड़न का मामला देवताली और मुंबई नका पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। इन मामलों में पुलिस ने छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक पुलिस आयुक्त संदीप मिटके को अध्यक्षता के एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित की गई है। इस घटना की छानबीन कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता और संदिग्ध आरोपित 2022 से मुंबई नका पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में चलने वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में अलग-अलग पदों पर काम कर रहे थे। ऑफिस में काम करते समय आरोपित पीड़ित महिलाओं के साथ बदतमीजी करते थे और हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते थे। एक पीड़िता का धर्म परिवर्तन कर उसके साथ यौन शोषण भी किया गया है।

भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए दूरदर्शन और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच समझौता

नई दिल्ली। भारतीय संस्कृति की वैश्विक मंच पर पहचान को मजबूत करने की दिशा में दूरदर्शन (प्रसार भारती) ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दूरदर्शन भवन में हुआ। इसमें दूरदर्शन के महानिदेशक के. सतीश नंबूद्विपरियार और आईसीसीआर की महानिदेशक के. नंदिनी सिंगला मौजूद रहे। भारतीय सांस्कृतिक सामग्री को वैश्विक स्तर पर अधिक व्यापक पहुंच देना है। आईसीसीआर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रस्तुतियों और आगोजनों की सामग्री उपलब्ध कराएगा। दूरदर्शन इस सामग्री का प्रसारण करेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विज्ञापित जारी कर बताया कि इस साझेदारी का उद्देश्य दूरदर्शन (प्रसार भारती) के व्यापक टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल नेटवर्क का लाभ उठाकर आईसीसीआर द्वारा उपलब्ध कराई गई सांस्कृतिक सामग्री को पहुंच को बढ़ाना है। इसमें विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथ ही आईसीसीआर मुख्यालय और भारत भर में स्थित स्थानिक क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संचालित कार्यक्रम शामिल हैं। समझौते के तहत, आईसीसीआर सांस्कृतिक सामग्री और प्रस्तुतियों उपलब्ध कराएगा, जबकि दूरदर्शन (प्रसार भारती) टेलीविजन चैनलों, रेडियो नेटवर्क, ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उनका प्रसारण और प्रसार करेगा।

पाकिस्तान में गुरुद्वारों के दर्शन के लिए भारतीय श्रद्धालुओं का जत्था रवाना

एजेंसी
अमृतसर। खालसा साजना दिवस (बैसाखी) के पावन अवसर पर पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए पूरे भारत से करीब 2840 सिख श्रद्धालु शुकुवार सुबह अटारी-वावा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेट्री (एसजीपीसी) की ओर से लगभग 1763 श्रद्धालुओं का जत्था विशेष रूप से रवाना किया गया। इसके अलावा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेट्री और हरियाणा कमेट्री और अन्य राज्यों से श्रद्धालु भी इस जत्थे में शामिल हैं। इस तरह कुल 2840 श्रद्धालु पाकिस्तान में खालसा साजना दिवस मनाने और गुरुधामों के दर्शन के लिए जा रहे हैं।

एसजीपीसी की ओर से इस जत्थे की अगुवाई सदस्य सुरजीत सिंह तुगलवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिख श्रद्धालु अपने गुरुधामों के दर्शनों के लिए गहरी श्रद्धा और आस्था रखते हैं। यह जत्था पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा नक्कना साहिब, गुरुद्वारा श्री



पंजा साहिब (हसन अब्दाल) सहित अजय ऐतिहासिक गुरुद्वारों में मत्था टेकेगा और मुख्य समागम में भाग लेने के बाद 19 अप्रैल को भारत लौटेगा। श्रद्धालुओं को 10 दिन का वीजा दिया गया है। एसजीपीसी के अधिकारियों ने बताया कि इस जत्थे के लिए 1795 पारपेट्टी पाकिस्तान दूतावास को भेजे गए थे, जिनमें से 1763 को वीजा जारी किया गया, जबकि 32 श्रद्धालुओं के वीजा आवेदन खारिज कर दिए गए। जिन श्रद्धालुओं को वीजा नहीं मिल पाया, उनमें निराशा देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने इस मौके पर दोनों देशों की सरकारों से अपील की कि ज्यादा

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में अपनी भागीदारी तेज करे निजी क्षेत्र : डॉ. जितेन्द्र सिंह

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि निजी क्षेत्र से अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में अपनी भागीदारी तेज करने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत के नवाचार तंत्र को मजबूत बनाने के लिए उद्योग की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। जारी करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि सरकार ने अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को निजी भागीदारी के लिए खोलने सहित कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साथ ही, शोध, विकास और नवाचार (आरडीआई) फंड जैसे विशेष तंत्र भी बनाए गए हैं, ताकि निजी क्षेत्र को अनुसंधान में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने जोर

देकर कहा कि अब ध्यान केवल नीतियों के निर्माण पर नहीं, बल्कि उनके वास्तविक प्रभाव पर होना



चाहिए। उन्होंने कहा कि शोधकर्ताओं को आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को समझकर ही प्रभावी सुधार संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में वैज्ञानिक प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रक्रियात्मक जटिलताएं और संस्थागत बाधाएं शोध के परिणामों को प्रभावित करती हैं। इसलिए फंडिंग तक आसान पहुंच, प्रशासनिक बाधाओं में

कमी और परोपकार को बढ़ावा देना आवश्यक है। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि भारत के शोध परिस्थितिकी तंत्र समुदाय की लंबे समय से मांग रही है। उन्होंने शोध प्रणाली में समन्वय और दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। नीति आयोग के सदस्य वी. के. सारस्वत ने कहा कि भारत का अनुसंधान तंत्र एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहां फंडिंग में देरी और प्रशासनिक अड़चनें अभी भी चुनौती बनी हुई हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. ए. के. सूदन ने कहा कि शोध को आसान बनाने के प्रयास लगातार जारी रहने चाहिए, क्योंकि अभी भी कई महत्वपूर्ण कमियां बनी हुई हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि शोध प्रणाली में अधिक लचीलापन, पारदर्शिता और पूर्वाभ्यास लाना आवश्यक है, ताकि वैज्ञानिक बिना रुकावट के अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें।

छत्तीसगढ़ के कांकेर में दो कारों की टक्कर में मासूम सहित 6 की मौत, 3 की हालत गंभीर

एजेंसी
कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात नाथिया नवागांव के पास दो कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 11 बजे यह हादसा हुआ।

परिवार कांकेर के उड़कुड़ा का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि सभी चीवरों में शादी समारोह में शामिल होकर अपने गांव उड़कुड़ा लौट रहे थे, तभी नाथिया नवागांव के पास उनकी कार दूसरी कार से टकरा गई। दोनों कारें तेज रफ्तार में थीं और टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए। कार सवार एक ही परिवार के 3 महिला, 2 पुरुष और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना

की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। कांकेर एसपी निखिल राखेचा ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। हादसे में घायल तीनों लोगों को तुरंत एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल



को पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने की

कोशिश की जा रही है। कांकेर एसपी निखिल राखेचा ने बताया कि नाथिया नवागांव के पास दो कारों की टक्कर में छह लोगों की मौत हुई है और तीन अन्य घायल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, इसके साथ ही मरने वालों की पहचान और बाकी जानकारीयें जुटाई जा रही हैं। घायलों



के उपचार के बाद उनसे भी जानकारी ली जाएगी। शवों का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने की

पश्चिम बंगाल विस चुनाव: असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर से तोड़ा गठबंधन, अकेले लड़ने का ऐलान

एजेंसी
कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन ने हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया है और राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

शुकुवार तड़के सोशल मीडिया पर जारी बयान में पार्टी ने कहा कि वह किसी ऐसे विवाद या बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती, जिससे मुस्लिम समुदाय के आत्मसम्मान पर प्रश्न उठे। बयान में स्पष्ट किया गया कि आज से हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन समाप्त किया जाता है। इस फैसले को हुमायूं कबीर से जुड़े कथित 'गोपनीय वीडियो' विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बयान में किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक हलकों में

माना जा रहा है कि इसी विवाद के बाद दोनों दलों के बीच दूरी बढ़ी। गठबंधन टूटने पर प्रतिक्रिया देते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि ओवैसी अपना निर्णय लेने के लिए



स्वतंत्र हैं और वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि उनके मन में ओवैसी के प्रति व्यक्तिगत सम्मान रहने भी था और आगे भी रहेगा। उन्होंने यह भी

बताया कि 25 मार्च को कोलकाता में हुई संयुक्त पत्रकार वार्ता में दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी 182

उन्होंने 'गोपनीय वीडियो' को लेकर आरोप लगाया कि यह कुत्रिम मेधा के माध्यम से तैयार किया गया है और इसके सत्यता साबित न होने पर उच्च न्यायालय में जाने की चेतावनी दी। मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन ने अपने बयान में यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय लंबे समय से गरीब, उपेक्षित और शोषित रहा है, और उनकी पार्टी का उद्देश्य ऐसे लोगों को स्वतंत्र राजनीतिक आवाज देना है। इसी कारण पार्टी ने राज्य में किसी भी दल के साथ गठबंधन न कर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि पहले दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर माना जा रहा था कि यह राज्य में अल्पसंख्यक मतों के समीकरण को प्रभावित कर सकता है। हालांकि अब इस गठबंधन के टूटने से चुनावी समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है।

पाकिस्तान में गुरुद्वारों के दर्शन के लिए भारतीय श्रद्धालुओं का जत्था रवाना

एजेंसी
अमृतसर। खालसा साजना दिवस (बैसाखी) के पावन अवसर पर पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए पूरे भारत से करीब 2840 सिख श्रद्धालु शुकुवार सुबह अटारी-वावा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेट्री (एसजीपीसी) की ओर से लगभग 1763 श्रद्धालुओं का जत्था विशेष रूप से रवाना किया गया। इसके अलावा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेट्री और हरियाणा कमेट्री और अन्य राज्यों से श्रद्धालु भी इस जत्थे में शामिल हैं। इस तरह कुल 2840 श्रद्धालु पाकिस्तान में खालसा साजना दिवस मनाने और गुरुधामों के दर्शन के लिए जा रहे हैं।

से ज्यादा लोगों को वीजा दिया जाए, ताकि हर कोई अपने गुरुधामों के दर्शन कर सके। साथ ही उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को और सुविधाजनक बनाने और पाकिस्तान सरकार द्वारा लगाए गए 20 डॉलर शुल्क को समाप्त करने की

मांग भी उठाई इस मौके पर एसजीपीसी के सचिव कुलवंत सिंह मन्नन ने बताया कि 14 अप्रैल को खालसा साजना दिवस के उपलक्ष्य में यह यात्रा आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि यह 10 दिनों की धार्मिक यात्रा है, जिसमें श्रद्धालु पाकिस्तान के विभिन्न गुरुद्वारों में मत्था टेकेंगे और खुशी-उत्साह के साथ वापस लौटेंगे। वहीं,

जत्थे के नेता सुरजीत सिंह तुगलवाल ने कहा कि गुरु नानक देव जी की पावन भरती नक्कना साहिब और चंजा साहिब पर मत्था टेकना हर सिख के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने मानवता, एकता और भाईचारे का संदेश दिया और लंगर की परंपरा शुरू कर समाज को समानता का मार्ग दिखाया। उन्होंने अरदास की कि सच्चे पातशाह पूरी मानवता और सिख पंथ को चढ़दी कला में रखें और सभी को खुशहाली प्रदान करें।

इस बार जत्थे में एक अहम पहलू यह भी है कि करीब 200 अकेली महिलाओं को भी वीजा जारी किया गया है, जो बिना किसी पारिवारिक सदस्य के इस धार्मिक यात्रा पर जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि पहले एसजीपीसी की ओर से कहा गया था कि अकेली महिलाओं को जत्थे के साथ नहीं भेजा जाएगा, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में महिलाओं को अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष एक विवाद सामने आया था।

मद्रा में 26 आईएसए अधिकारियों का तबादला, 14 जिलों के कलेक्टर बदले

एजेंसी
भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्य शासन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएसए) के 26 अधिकारियों का तबादला करते हुए उनकी नवीन पदस्थापना की गई है। इस संबंध में गुरुवार की रात सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, जिन आईएसए अधिकारियों का तबादला किया है, उनमें 14 जिलों के कलेक्टरों को इधर से उधर किया गया है। इनमें धार जिले के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को भोपाल जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि मौजूदा भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव पद के साथ आयुक्त सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वहीं, लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त और स्कूल शिक्षा विभाग की पदेन सचिव शिल्पा गुप्ता को हटाकर गृह विभाग में सचिव बनाया गया है। वहीं, उनकी जगह पर गृह विभाग में सचिव अभिषेक सिंह को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय पदस्थ किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग

द्वारा जारी आदेश के अनुसार, तबादला सूची में महिला अधिकारियों को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। इंदौर लोक सेवा आयोग की सचिव राखी सहाय को उमरिया कलेक्टर, सशस्त्रता विभाग की उप सचिव शोला दाहिमा को श्योपुर कलेक्टर और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की उप सचिव बिदिशा मुखर्जी को मैहर

बिहार के सरकारी स्कूल में अवैध शराब पार जाने के मामले में एनएचआरसी ने लिया संज्ञान

एजेंसी
नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बिहार के बेगुसराय जिला स्थित सिस्वा क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल में बड़ी मात्रा में रखी शराब को शीतल पेय समझकर एक छात्र के सेवन करने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नॉटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग के मुताबिक, 08 अप्रैल 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 6 अप्रैल 2026 को इस क्षेत्र में स्थित एक स्कूल के जर्जर शौचालय में बोलतों में भरी हुई अवैध शराब को शीतल पेय समझकर चौथी कक्षा के एक छात्र ने गलती से पी ली। छात्र नशे की हालत में घर लौटा। स्कूल के परिवार ने घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी और मामला पुलिस के संज्ञान में

लाया गया। खबरों के अनुसार, पुलिस ने शौचालय से लगभग 204 लीटर अवैध शराब से भरे कुल 23 कार्टन जब्त किए हैं। उल्लेखनीय है कि यह घटना 05 अप्रैल 2016 से लागू शराब के निर्माण, बिक्री और सेवन पर



प्रतिबंध के बीच घटी है, जब बिहार को शुष्क राज्य घोषित किया गया था। आयोग ने रिपोर्ट में बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति और जांच संबंधी जानकारी शामिल करने का आग्रह किया है।

मद्रा के उज्जैन में खुले बोरवेल के गड्डे में गिरा दो साल का बच्चा

एजेंसी
भोपाल। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला मुख्यालय से करीब 75 किमी दूर बड़नगर इलाके के पास ग्राम झारलिया में गुरुवार रात बोरवेल के खुले गड्डे में गिरे दो साल का मासूम बच्चे को बचाने के लिए राहत एवं बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू टीम को उसकी लोकेशन 75 फीट की गहराई पर मिली है। पांच पोकलेन मशीनों की मदद से बोरवेल के समानांतर सुरंग बनाई जा रही है। खबर लिखे जाने तक करीब 40 फीट खुदाई हो चुकी है। जानकारी के अनुसार, भेड़े चराने के लिए आया राजस्थान के पाली जिले के एक परिवार का दो साल का बच्चा गुरुवार रात करीब साढ़े सात बजे बोरवेल के खुले गड्डे में गिर गया था। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। भोपाल से पहुंची एनडीआरएफ की टीम, हरदा, इंदौर

और उज्जैन की एसडीआरएफ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। बोरवेल में कैमरा डालकर बच्चे की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उसे ऑक्सिजन सपोर्ट भी दिया जा रहा है। मौके पर दो एंबुलेंस भी तैनात हैं। बड़नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार पाटीदार ने बताया कि बोरवेल में गिरने वाला दो वर्षीय मासूम भारीरथ पूज प्रवीण देवासी ग्राम गुडानला, जिला पाली (राजस्थान) का रहने वाला है। परिवार पिछले तीन दिनों से क्षेत्र में भेड़ चराने के लिए रुका हुआ था।

परिजन के मुताबिक, बच्चा दीवार के पास खेल रहा था। उसने पथर से बोरवेल का ढक्कन हटाया और बाल्टी समझकर पैर डाल दिया, जिससे वह सीधे अंदर गिर गया। बच्चे की मां ने उसे गिरते देखा और बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह गहराई में जा चुका था। परिवार ने गांव के सरपंच को सूचना

दी। इसके बाद जिला प्रशासन को जानकारी दी गई। रात करीब साढ़े आठ बजे एसडीआरएफ समेत रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। भोपाल, इंदौर, हरदा और उज्जैन से आए 200 लोगों की रेस्क्यू टीम भारीरथ के बोरवेल से निकालने की कोशिश में जुटी है। जानकारी मिलने पर उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा मौके पर पहुंच गए थे।

पुलिस अधीक्षक शर्मा ने बताया कि बोरवेल करीब 200 फीट गहरा है, जिसमें बच्चा 75 फीट की गहराई पर अटका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों रेस्क्यू में जुटी है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी यह मौजूद हैं। पांच पोकलेन की मदद से समानांतर सुरंग बनाई जा रही है। बीच में चढ़ाने आने से ड्रिलिंग बार-बार रुक रही है। बॉरिंग में पानी आने से भी रेस्क्यू में परेशानी आ रही है।

नशे के खिलाफ जम्मू-कश्मीर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 20 वरिष्ठ अधिकारी बने 'जिला मेटर'

एजेंसी
जम्मू। जम्मू-कश्मीर में नशीले पदार्थों के बढ़ते दुष्प्रभाव को खत्म करने के उद्देश्य से प्रशासन ने मुहिम को तेज कर दिया है। सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक अहम कदम उठाते हुए सभी जिलों में नशा विरोधी गतिविधियों को सशक्त बनाने के लिए 20 वरिष्ठ अधिकारियों को 'जिला मेटर' नियुक्त किया है। जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य में लगातार हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी पर नजर रखे हुए थी, जिसके बाद इन्होंने इस अभियान को और तेज करने के लिए 20 वरिष्ठ अधिकारियों को 'जिला मेटर' नियुक्त किया है। ये अधिकारी अपने-अपने जिलों में जागरूकता अभियानों, प्रवर्तन उपायों, नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली और सामुदायिक सहभागिता को निगरानी करेंगे। प्रशासन का उद्देश्य है कि विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर एक समग्र और प्रभावी रणनीति लागू की जाए। इस पहल ने न केवल नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी, बल्कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास और समाज में पुनर्स्थापन को भी बल मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि यह 100 दिवसीय अभियान जम्मू-कश्मीर को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पथर साबित होगा। इसी क्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक उच्च स्तरीय बैठक में 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत आगामी 100-दिवसीय गहन अभियान की तैयारियों को विस्तृत समीक्षा की। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश से नशे के दुरुपयोग को जड़ से समाप्त करना और समाज को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक बनाना है। बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अभियान को प्रभावी बनाने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की जाए, जिसमें जागरूकता कार्यक्रमों, प्रवर्तन कार्रवाई और पुनर्वास सेवाओं को समान रूप से प्राथमिकता दी जाए।

महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा निकली नाबालिग, एनसीएसटी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

एजेंसी
भोपाल। मध्य प्रदेश के खराोन जिले की पारधी जनजाति से जुड़ी युवती मोनालिसा के मामले में नया मोड़ सामने आया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की जांच में युवती को नाबालिग बताया गया है। दावा किया

गया है कि केरल में संपन्न विवाह के समय उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। मामले के अनुसार, अधिवक्ता प्रथम दुबे ने 17 मार्च 2026 को आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी। इसके बाद आयोग के निर्देश पर गठित जांच दल ने केरल से लेकर महेश्वर तक दस्तावेजों और तथ्यों की पड़ताल की।

एनसीएसटी ने खुलासा करते हुए जानकारी दी कि आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में एनसीएसटी के पूर्व न्यायाधीश व सलाहकार प्रकाश उड्के के मार्गदर्शन में अधिवक्ता प्रथम दुबे द्वारा की गई कानूनी पैरवी ने यह साबित कर दिया है कि जिस युवती को बालिग बताया

विवाह कराया गया था, वह वास्तव में पारधी जनजाति समुदाय की एक नाबालिग लड़की है। जांच के दौरान महेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रिपोर्टों में युवती की जन्म तिथि 30 दिसंबर 2009 पाई गई। इसके आधार पर 11 मार्च 2026 को हुए विवाह के समय उसकी उम्र करीब

16 वर्ष बताई गई है। जांच में यह भी सामने आया कि केरल में विवाह पंजीवन के लिए उपयोग किए गए जन्म प्रमाण पत्र में अलग नाम तिथि दर्ज थी। जांच टीम ने इसे सफ़िद बताते हुए संबंधित दस्तावेजों के आधार पर निरस्त करने के निर्देश दिए जाने की बात कही है। आयोग

की अनुसंधान के बाद गुरुवार की रात महेश्वर थाने पर अपहरण सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इंदौर आईजी अनुगम ने बताया कि उक्त मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आगे विवेचना की जा रही है।

राजनीतिक व अन्य पहलुओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस विवाह को लेकर कड़ संघठनों और राजनेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और संबंधित पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आयोग और

पुलिस की विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक होना अभी बाकी है। इस खुलासे के बाद आयोग अब दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। आयोग ने 22 अप्रैल 2026 को केरल एवं मध्य प्रदेश के डीजीपी को आयोग मुख्यालय नई दिल्ली तलब किया है।

आईपीएल में आज सीएसके पर जीत के इरादे से उतरेगी कैपिटल्स

चेन्नई (एजेंसी)। आईपीएल में शनिवार को होने वाले दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इस मैच में सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपने घरेलू मैदान पर टीम को जीत दिलाना चाहेंगे। अब तक सीएसके ने इस सत्र में एक भी मैच नहीं जीता है। उसके गेंदबाजों और बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है जिससे टीम मुश्किल में है। इस मैच में उसके पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खेलने की संभावना है। अगर धोनी खेलते हैं तो ये सीएसके लिए काफी फायदेमंद होगा। वहीं दूसरी ओर अक्षर पटेल की कप्तानी में उतर रही दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन सीएसके से अच्छा रहा है। ऐसे में उसके हौंसले बुलंद हैं।

सीएसके के लिए इस सत्र की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। टीम अपने शुरुआती मैच में आरसीबी और पंजाब किंग्स से हारी है। टीम की बल्लेबाजी ही नहीं गेंदबाजी भी कमजोर रही है। वहीं कैपिटल्स ने सत्र की शुरुआत बेहतर तरीके से की है। उसने अपने पहले तीन मैचों में से 2 में जीत हासिल की है। उसे लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत मिली जबकि गुजरात टाइटन्स से उसे केवल एक रन से ही हार मिली।

आंकड़ों पर नजर डालें तो दोनों ही टीमों के बीच अबतक हुए पिछले 31 के मुकाबलों में, दिल्ली ने 12 जीत दर्ज की हैं, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 जीत हासिल की हैं।



टीम इस प्रकार है

चेन्नई सुपर किंग्स: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), आयुष ध्वजे, सरफराज खान, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद, मेट हेनरी
दिल्ली कैपिटल्स: अक्षर पटेल (कप्तान), पृथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिजवी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्राज निगम, कुलदीप यादव, टी नटराजन, लुंगी एनगिडी

थर्ड अंपायर के पास जाना चाहिए था फैसला, रोवमन पॉवेल ने दिग्वेश राठी के कैच पर उठाए सवाल



कोलकाता (एजेंसी)। आईपीएल 2026 में गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के बीच इंडन गार्डेन्स में एक रोमांचक मुकाबला खेला गया जिसे एलएसजी ने मुकुल चौधरी की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर 3 विकेट से जीता। केकेआर की पारी के दौरान सलामी बल्लेबाज फिन एलन का कैच एलएसजी के स्पिनर दिग्वेश राठी ने पकड़ था जिस पर विवाद हुआ था। मैच के बाद रोवमन पॉवेल ने कहा कि इसे तीसरे अंपायर को भेजा जाना चाहिए था। रोवमन ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट्स से कहा, 'यह उनकी तरफ से एक बड़ी गलती थी, लेकिन हम इस पर गौर नहीं करेंगे और यह नहीं कहेंगे कि आज रात हमें दो पॉइंट्स का नुकसान हुआ, लेकिन मैदान पर मौजूद अंपायरों

को फैसला थर्ड अंपायर को भेजना चाहिए था।' केकेआर की पारी का दूसरा ओवर प्रिंस यादव कर रहे थे। ओवर की चौथी गेंद प्रिंस ने बैक-ऑफ-ए-लेंथ डिलीवरी फेंकी, और फिन एलन ने उसे लाइन के पार मारा, लेकिन टॉप एज लग गया। बॉल थर्ड मैच पर खड़े दिग्वेश के पास गई। ऐसा लगा कि बॉल दूर तक जाएगी, लेकिन राठी ने खुद को बाउंड्री लाइन के किनारे पर संभाला और दोनों हाथों से कैच लेने के लिए अपनी बाईं ओर खड़े हो गए। राठी बाउंड्री लाइन के बहुत करीब थे, और अंपायर जो कुछ भी हुआ उससे खुश लग रहे थे। एलन को आउट दिया गया। फैसला थर्ड अंपायर को नहीं भेजा गया, और बाद में रिप्ले से पता चला कि राठी ने शायद कुशन पर पैर रख दिया था। हालांकि, रिप्ले से कुछ भी पक्का पता नहीं चल सका।

आईपीएल में आज होगा पंजाब और सनराइजर्स का मुकाबला

मुम्बई (एजेंसी)। आईपीएल में शनिवार को होने वाले पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। कप्तान श्रेयस अय्यर की पंजाब का लक्ष्य इस मैच में भी अपनी जीत का सिलसिला बनाये रखना रहेगा। पंजाब ने अभी तक इस सत्र में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे वह जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। उसे इस मैच में धरेलू मैदान का भी लाभ मिलेगा। उसने तीन में से अपने दो मैच जीते हैं वहीं उसका एक मैच बारिश के कारण पूरा नहीं हो पाया था। पंजाब ने इस सत्र में 200 रन से अधिक रनों का लक्ष्य भी आसानी से हासिल कर लिया था।

टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने अब तक के मैचों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है।

सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह के अलावा कूपर कोनोली ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं गेंदबाजी में विजयकुमार वैशाक ने प्रभावी प्रदर्शन किया है।

वहीं दूसरी ओर ईशान किशन की कप्तानी में सनराइजर्स अभी तक केवल एक मैच ही जीत पायी है। टीम की ताकत उसकी बल्लेबाजी है पर उसके बल्लेबाज इस सत्र में असफल रहे हैं। सलामी बल्लेबाज टैविस हेड और अभिषेक शर्मा भी अबतक असफल रहे हैं। उसके प्रमुख गेंदबाज हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट भी अबतक प्रभावी नहीं रहे हैं। केवल नितीश कुमार रेड्डी और हेनरिक क्लासेन ही अब तक सफल रहे हैं। स्पिनर हर्ष दुबे ने पावरप्ले में अच्छा प्रदर्शन बनाये रखा है।

आईपीएल इतिहास में अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 23 मैच खेले गए हैं। इसमें पंजाब किंग्स ने 7 तो हैदराबाद ने 17 मुकाबलों में जीत हासिल की है।

दोनों ही टीमों इस प्रकार हैं
पंजाब किंग्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अर्शदीप सिंह, प्रियांस आर्य, पाइला अविनाश, अजमतुल्लाह उमरजई,



जेवियर बार्दलेट, युजवेंद्र चहल, कूपर कोनोली, प्रवीण दुबे, वेन ड्वाराशुइस, लॉकी फर्ग्युसन, हरनूर सिंह, हरप्रत बराड़, मार्को यानसन, मुशीर खान, विशाल निशाद, मिचेल ओवेन, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस्, सूर्याश शेडो, विष्णु विनोद, विजयकुमार वैश्यक, नेहल वंडेडा, यश ठाकुर।
सनराइजर्स हैदराबाद: ईशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर),

अभिषेक शर्मा, अमित कुमार, सलिल अरोड़ा, ब्रायडन कार्स, पैट कर्मिसन, हर्ष दुबे, केन्स फ्लेड्यू, ट्रैविंस हेड, प्रफुल्ल हिगे, हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, ईशान मलिंगा, कामिंडु मोंडिस, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, डेविड पायने, साकिब हुसैन, शिवम मावी, शिवांग कुमार, रविचंद्रन स्मरण, ओंकार तर्माले, जयदेव उनादकट, अनिकेत वर्मा, जीशान अंसारी।

भारत के खिलाफ टेस्ट में राशिद के बिना ही उतरेगी अफगानिस्तान

नई दिल्ली। अफगानिस्तान की टीम को जून में भारत के खिलाफ मुम्बई में होने वाले एकमात्र टेस्ट में अपने स्टार स्पिनर राशिद खान के बिना ही उतरना होगा। इसका कारण है कि राशिद को डॉक्टर ने सलाह दी है उन्हें अपनी कमर को आराम देना होगा। आजकल आईपीएल खेल रहे राशिद से डॉक्टर ने कहा है कि अगर वह अपना करियर लंबा करना चाहते हैं तो टेस्ट क्रिकेट से दूर रहें। इसी कारण राशिद मैच से बाहर रहेंगे। राशिद का कहना है कि उनकी प्राथमिकता साल 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले एकदिवसीय विश्व कप को देखते हुए पिछले साल हासिल करना है। राशिद ने साल 2023 वनडे विश्व कप के बाद कमर की सर्जरी कराई थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट क्रिकेट से दूर रहने की सलाह दी थी पर इसके बाद भी पिछले साल उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक टेस्ट खेलकर 54 ओवर किये थे।

राशिद के अनुसार डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट क्रिकेट से दूर रहने के लिए ही कहा था। इसके बावजूद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट खेला। उन्होंने कहा, एकदिवसीय क्रिकेट में मुझे मजा आता है और मैं अफगानिस्तान के लिए लंबे समय तक खेल सकता हूँ पर फिनाल अपनी कमर को आराम देना चाहता हूँ जिससे कि उसपर अधिक दबाव न पड़े। आईपीएल के बाद भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के बारे में खेलने को लेकर राशिद ने कहा कहा, ये काफी कठिन सवाल है। मैं 2025 में एक टेस्ट खेल चुका हूँ और अब विश्व कप की तैयारी करूंगा। ऐसे में एक टेस्ट खेलकर अपना करियर खतरे में नहीं डाला जा सकता।

हार से निराश रहाने बोले, मुकुल ने हमसे मैच छीन लिया

कोलकाता। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में मिली हार पर निराशा जताते हुए कहा कि इस प्रकार की हार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। केकेआर को इस सत्र में सभी तीन मैचों में हार झेलनी पड़ी है जबकि एक मैच बारिश के कारण नहीं हो पाया। सुपरजायंट्स के खिलाफ उसे मैच की अंतिम गेंद पर हार मिली। इस मैच में एक समय केकेआर काफी अच्छी स्थिति में थी पर मुकुल चौधरी ने अंतिम ओवरों में अंधशंका लगाकर मैच पलट दिया। हार को लेकर रहाणे ने कहा, 'इसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल क्योंकि अंत तक हम मैच में बने हुए थे। मुकुल ने अंत में जबरदस्त शॉट खेलकर मैच हमसे छीन लिया। ऐसे करीबी मैचों में ज्यादा कामियां नहीं निकाली जा सकती।' उन्होंने कहा, 'फ्रीलैंग में शायद एक-दो गलतियां हुईं पर हमारे गेंदबाजों ने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई। हारने के बाद कामियां निकालना आसान होता है। हमें लगा था कि इस पिच पर 180-185 का स्कोर अच्छा था क्योंकि बड़े शॉट खेलना आसान नहीं था। धीमी रेंडें कर आ रही थी इंसॉल्व बल्लेबाजी करना कठिन था।' रहाणे ने कहा, 'मुझे लगता कि 18 ओवर तक हम बहुत अच्छी स्थिति में थे पर अंत के दो ओवरों में स्थिति खराब हो गयी क्योंकि मुकुल ने मैच पलट दिया। हमारी गेंदबाजी अच्छी थी पर मुकुल ने उससे भी अच्छी बल्लेबाजी की और उसे जीत का श्रेय मिलना ही चाहिये।'

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने की भविष्यवाणी, आईपीएल खिताब का बचाव कर सकती है आरसीबी

फरीदाबाद (हरियाणा) (एजेंसी)। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा ने पूरा भरोसा जताया है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अपना इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खिताब बचाने में सक्षम है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी सफल फ्रैंचाइजी से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करना ही सबसे जरूरी है। RCB ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2025 IPL के फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर अपना पहला IPL खिताब जीता था जिससे ट्रॉफी के लिए उनका 18 साल का इंतजार खत्म हो गया था। चोपड़ा ने आगे कहा कि जो टीमों शुरुआत में ही लय पकड़ लेती हैं और अपनी फार्म बरकरार रखती हैं, वे आखिर तक जा सकती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस सीजन में कोई नया चैंपियन भी उभर सकता है, और RCB भी अपना खिताब बचा सकती है। बात करते हुए अंजुम चोपड़ा ने कहा, 'हां, वे निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। मुंबई ने ऐसा किया है, चेन्नई ने ऐसा किया है, RCB भी ऐसा कर सकती है। और फिर से, जो टीम लगातार अच्छा खेलेंगी, वह प्लेऑफ में पहुंचेगी। प्लेऑफ में पहुंचने वाली सभी टीमों में वहीं से शुरुआत करती हैं, जहां उन्होंने पिछली बार छोड़ा था इसलिए वे निश्चित रूप से ऐसा कर सकती हैं। कोई नया चैंपियन भी बन सकता है और RCB भी अपना IPL खिताब बचा सकती है।'

चोपड़ा का मानना है कि RCB इस सीजन में सबसे ज्यादा व्यवस्थित टीम लगे रही है और मौजूदा चैंपियन होने के नाते अपनी मजबूत लय को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने आगे



कहा कि उन्होंने न केवल वहीं से शुरुआत की है जहां उन्होंने पिछले साल छोड़ा था बल्कि मौजूदा सीजन में वे और भी ज्यादा प्रभावशाली और संतुलित नजर आ रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा, 'RCB अच्छी लगे रही है, वे सबसे ज्यादा व्यवस्थित टीम लगे रही हैं क्योंकि वे मौजूदा चैंपियन हैं। उन्होंने वहीं से शुरुआत की है जहां उन्होंने पिछले सीजन में छोड़ा था। असल में इस सीजन में वे और भी बेहतर लगे रहे हैं।' RCB ने 2026 IPL के अपने दोनों शुरुआती मैच जीते हैं और अब वह पॉइंट्स टेबल में चार अंकों और +2.501 के शानदार नेट रन रेट (NRR) के साथ तीसरे स्थान पर है। चोपड़ा को यह भी लगा कि पंजाब किंग्स (PBKS)

भी जबरदस्त फॉर्म में है, पिछले सीजन में फाइनल तक पहुंचने की वजह से उन्हें ठीक-ठीक पता है कि उस अनुभव का फायदा उठाकर आगे कैसे बढ़ना है। उन्होंने कहा, 'पंजाब भी बहुत अच्छी दिख रही है। उन्होंने पिछले साल फाइनल भी खेला था, इसलिए उन्हें पता है कि उनका सफर कहां खत्म हुआ था और उन्हें दोबारा कहां से शुरुआत करनी है। उन्होंने शुरुआत भी अच्छी की है।' PBKS ने भी 2026 IPL सीजन की शुरुआत जोरदार तरीके से की है। उन्होंने अपने तीन मैचों में से दो में जीत हासिल की, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा। IPL पॉइंट्स टेबल में पंजाब 5 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है।

हॉकी इंडिया का बड़ा निर्णय, टिम व्हाइट को जूनियर महिला टीम का कोच बनाया

नई दिल्ली (एजेंसी)। हॉकी इंडिया ने शुक्रवार को टिम व्हाइट को जूनियर महिला टीम का कोच बनाने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलियाई हार्ड-परफॉर्मिंग कोच व्हाइट ने हॉकी इंडिया लीग में अर्कांड तमिलनाडु ड्रैगन्स के हेड कोच के तौर पर काम किया था। वह भारत महिला हॉकी की अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिकी ने इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए कहा, 'हम टिम व्हाइट को टीम में शामिल करने के बहुत खुश हैं। बेल्जियम और ऑस्ट्रेलियाई जूनियर कार्यक्रम के साथ उनका पुराना रिकॉर्ड अपने आप में बहुत कुछ कहता है, खासकर जूनियर विश्व कप में टीमों को फाइनल फिनिश तक ले जाने में उनकी सफलता। हमारा

मानना है कि हार्ड-परफॉर्मिंग कोचिंग और एथलीट विकास में उनका बहुत बड़ा अनुभव हमारी जूनियर महिलाओं को सीनियर अंतरराष्ट्रीय हॉकी की चुनौतियों के लिए तैयार करने में बहुत जरूरी होगा।' हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा, 'टिम की नियुक्ति हमारी जूनियर टीमों को विश्व स्तरीय कोचिंग देने के हमारे लक्ष्य से मेल खाती है। जूनियर से सीनियर हॉकी में बदलाव एक अहम दौर है, और हमें विश्वास है कि टिम के निर्देशन में हमारे युवा एथलीट सबसे ऊंचे लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जरूरी तकनीकी परिपक्वता हासिल करेंगे। व्हाइट ने अपनी नियुक्ति पर कहा, 'हाल ही में तमिलनाडु ड्रैगन्स के कोच के तौर पर इंडिया में समय बिताने के

बाद, मैं देश के जबरदस्त पैशन और समृद्ध हॉकी संस्कृति से वापस आया। मैंने जूनियर वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ कोचिंग करते हुए यहां बहुत सारी युवा प्रतिभाएं देखीं। ऐसे पथनीटर्स के साथ फुल-टाइम काम करने का मौका मिलना एक विशेषाधिकार की तरह है। मेरा लक्ष्य तकनीकी रूप से मजबूत खिलाड़ियों को तैयार करना है जो गैप को भरने और सीनियर टीम में जगह बनाने के लिए तैयार हों। टीम के प्रति अपने विजन के बारे में उन्होंने कहा, 'मैं गैप को सिलप रखना चाहता हूँ और सामूहिक साथ ही व्यक्तिगत मजबूती पर फोकस करना चाहता हूँ। हमारा लक्ष्य एक ऐसी टीम बनना होगा जो आक्रामक हॉकी को अहमियत दे लेकिन अपने रक्षात्मक खेल में भी अनुशासित रहे। यह जरूरी है

कि हम पूरे 60 मिनट तक उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए शारीरिक रूप से कड़ी मेहनत करें। 'टीम-फस्ट' की अवधारणा को आगे रखते हुए हम किसी भी अंतरराष्ट्रीय चुनौती के लिए अच्छी तरह तैयार रहेंगे।' व्हाइट की नियुक्ति को भारत में जूनियर हॉकी को आधुनिक तकनीक और अनुशासन को शामिल करने के लिए एक रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। उनके बैकग्राउंड में हॉकी ऑस्ट्रेलिया के लिए नेशनल जूनियर कोच के तौर पर काम करना और यूरोप में हार्ड-परफॉर्मिंग पाथवे की देखरेख करना शामिल है। व्हाइट के कोचिंग करियर में ऑस्ट्रेलिया में हाल की सफलता और ऑस्ट्रेलिया के साथ पिछला अनुभव शामिल है। भारत आने से पहले, उन्होंने



बेल्जियम अंडर-21 महिला टीम के कोच के तौर पर काम किया, और दिसंबर में 2025 जूनियर वर्ल्ड कप में उन्हें कांस्य पदक दिलाया था। 2021 और 2024 के बीच, वह बेल्जियम की महिला राष्ट्रीय टीम के कोचिंग स्टाफ का भी एक अहम हिस्सा थे। इस दौरान टीम ने विश्व रैंकिंग में

काफी सुधार किया और 12 वें से 3 वें पर आ गई। 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स में सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। अपने करियर की शुरुआत में, वह ऑस्ट्रेलिया के लिए राष्ट्रीय जूनियर कोच के पद पर थे, जहां टीम ने जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक जीता था।

ऑरेंज और ब्लैक कैप की सूची में बदलाव, अंगकृश रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे शीर्ष पांच में शामिल



कोलकाता (एजेंसी)। कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले हुए आईपीएल मुकाबले के बाद सबसे अधिक रनों के लिए मिलने वाली ऑरेंज कैप और सबसे अधिक विकेट के दावेदारों में बदलाव आये हैं। अब राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी और मुंबई के राहित शर्मा शीर्ष पांच से बाहर हो गये हैं। वहीं केकेआर के अंगकृश रघुवंशी और कप्तान अजिंक्य रहाणे अपनी अच्छी पारियों की बदौलत शीर्ष पांच में पहुंच गये हैं। वहीं पंपल कैप की वीड में लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रिंस यादव को लाभ हुआ है।

ऑरेंज कैप की सूची में राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पहले स्थान पर हैं। उन्होंने अभी तक खेले 3 मुकाबलों में 163.46 के स्ट्रोक रेट के साथ 170 रन बनाये हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी और केकेआर के अंगकृश रघुवंशी दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। शीर्ष पांच बल्लेबाजों में सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन और केकेआर के अजिंक्य रहाणे चौथे और पांचवें नंबर पर हैं। पंपल कैप की सूची में राजस्थान रॉयल्स के स्टर स्पिटर रवि बिश्नोई नंबर एक पर बने हुए हैं। उन्होंने इस लीग में अभी तक तीन मैचों में 7 विकेट लिए हैं। वहीं गुजरात टाइटन्स के प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान के साथ-साथ दिल्ली कैपिटल्स के लुंगी एनगिडी और राजस्थान रॉयल्स के नंदे बार शीर्ष-5 में शामिल हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रिंस यादव 5 विकेट के साथ 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं केकेआर के वैभव अरोड़ा 9वें पायदान पर हैं।

यूईएफ यूरोपा लीग-कार्टरफाइनल के पहले लेग में ब्रागा और रियल बेटिस के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा

ब्रागा। यूईएफ यूरोपा लीग कार्टरफाइनल के पहले लेग में ब्रागा और रियल बेटिस के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की हाराबरी पर समाप्त हुआ। एट्राडिओ म्युनिसिपल डे ब्रागा में खेले गए इस मैच में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। मैच की शुरुआत में ब्रागा ने आक्रामक अंदाज अपनाया और इसका फायदा उन्हें जल्दी ही मिल गया। डिगो रोड्रिगस के कॉर्नर पर पलोवरियन गिल्लिटा ने शानदार गोल के जरिए गोल दागते हुए टीम को बढ़त दिलाई। इस शुरुआती गोल ने घरेलू टीम को आत्मविश्वास दिया और उन्होंने खेल पर नियंत्रण बनाए रखा। हालांकि, रियल बेटिस ने धीरे-धीरे वापसी की कोशिश की। 24वें



मिनट में मार्क बार्दा ने हेडर के जरिए बराबरी का मौका बनाया, लेकिन गेंद पोस्ट से टकराकर बाहर चली गई। इसके बाद भी बेटिस ने बचाव बनाए रखा और ब्रागा के गोलकीपर लुकास हॉर्निसेक को कई बार सतर्क रहना पड़ा, खासकर कुचो हर्नांडेज के लोज-रेज हेडर को रोकते समय। दूसरे हाफ में मैच और रोमांचक हो गया। बेटिस ने आक्रमण को तेज करने के लिए बदलाव किए, जिसमें विंगर एंटनी को मैदान पर उतारा गया। हालांकि, ब्रागा ने भी मौके बनाए और गिल्लिटा का एक शॉट गोलकीपर पाक लोपेज ने शानदार तरीके से बचाया। मैच का टर्निंग पॉइंट तब आया जब ब्रागा की जीन-बैटिस्ट गौरी ने बॉक्स में फाउल कर दिया, जिससे बेटिस को पेनल्टी मिला।

जोनाथन क्रिस्टी को हराकर आयुष शेट्टी ने किया उलटफेर, सेमीफाइनल में पहुंचे

निम्बो (चीन)। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने शुक्रवार को बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी जोनाथन को हराकर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली। आज यहां टॉप-4 में जगह बनाने के साथ ही आयुष शेट्टी 2018 में एच.एस. प्रणय के बाद इस कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एकल बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। यह 2023 में विराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी के पुरुष डबल्स गोल्ड मेडल के बाद बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत का पहला मेडल भी होगा। पुरुष एकल बैडमिंटन रैंकिंग में 25वें स्थान पर मौजूद आयुष शेट्टी ने कार्टर-फाइनल में इंडोनेशिया के ओलंपियन और तीसरी वरीयता प्राप्त जोनाथन क्रिस्टी को 23-21, 21-17 से हराया। पहला गेम बेहद कड़ा रहा, जिसमें कोई भी खिलाड़ी निर्णायक बंदूत नहीं बना पाया। पूर्व एशियाई चैंपियन जोनाथन क्रिस्टी 11-10 की मामूली बढ़त के साथ मिड-गेम ब्रेक में गए। जोनाथन क्रिस्टी 18-15 की बढ़त बनाकर मैच पर नियंत्रण बनाते दिख रहे थे और उन्हें गेम पॉइंट भी मिल गया था, लेकिन आयुष शेट्टी ने जोरदार वापसी की और मैच को टाई-ब्रेक में ले जाकर पहला गेम जीत लिया। दूसरा गेम भी उतना ही कड़ा रहा। आयुष शेट्टी 11-9 की मामूली बढ़त के साथ ब्रेक में गए, जिसके बाद 7 विकेट मैच पर अपनी पकड़ मजबूत की और जीत हासिल करके सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। दोनों खिलाड़ियों के बीच यह पहली भिड़त थी, जिसमें आयुष शेट्टी ने जोनाथन क्रिस्टी के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की। इससे पहले टूर्नामेंट में, आयुष शेट्टी ने पहले राउंड में दुनिया के सातवें नंबर के खिलाड़ी और मौजूदा एशियाई खेलों के चैंपियन ली शी फेंग को चौका दिया था। इसके बाद उन्होंने चीनी ताइपो के वी यू जेन को हराकर कार्टर-फाइनल में जगह बनाई थी। सेमीफाइनल में, आयुष शेट्टी का मुकाबला थाईलैंड के पेरिस 2024 रन पदक विजेता कुनलवुत विटिउसरन और चीन की एशियाई खेलों की गोल्ड मेडल विजेता पुरुष टीम के सदस्य वेंग होंगयांग के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा।

बिली जीन किंग कप : इंडोनेशिया से हारा भारत, कोरिया की जीत का सिलसिला जारी

नई दिल्ली। बिली जीन किंग कप ग्रुप-बू एशिया/ओशियाना मुकाबलों में भारत को गुरुवार को इंडोनेशिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। डीएलटीए कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मुकाबले में इंडोनेशिया ने दोनों सिंगल्स में जीतकर अजेय बढ़त हासिल कर ली। पहले सिंगल्स मुकाबले में वैष्णवी अडकर को प्रिंस्का मैडलिन न्युग्रो के खिलाफ कड़े मुकाबले में 7-6(3), 6-7(3), 6-3 से हार झेलनी पड़ी। मैच काफ़ी उतार-चढ़ाव भरा रहा, जहां अडकर ने दूसरे सेट में वापसी करते हुए मुकाबला निर्णायक सेट तक पहुंचाया, लेकिन तीसरे सेट में इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने बाजी मार ली। दूसरे सिंगल्स में सहजा यमलापल्ली को जेनिस् त्जेन के खिलाफ 6-2, 6-1 से एकतरफा हार का सामना करना पड़ा, जिससे इंडोनेशिया ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। खबर लिखे जाने तक रुतुजा भोसले और अंकिता रेना इंडोनेशियाई जोड़ी के खिलाफ डबल्स मुकाबला खेल रही थीं। अन्य मुकाबलों में कोरिया गणराज्य ने न्यूजीलैंड को हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। दायोन बैक ने वैंलेंटिना इवानोव को 7-5, 6-3 से हराया, जबकि सोह्युन पार्क ने मोनिक बैरी को 6-0, 6-1 से हराकर टीम की जीत पक्की कर दी। कोरिया और इंडोनेशिया दोनों ही टीमों अब तक अपने सभी मुकाबले जीतकर तालिका में शीर्ष पर बनी हुई हैं। वहीं थाईलैंड ने भी शानदार वापसी करते हुए मंगोलिया को 3-0 से वलीन स्टीप किया। वापसार्न नाकतो ने अनु-वजिन गैंटो को 6-1, 6-0 से हराया, जबकि पाचारिन चीपचोदेज ने खोंगोनुजल अणदारखिंगिंग को समान स्कोर से जीत की पाविका में शामिल किया।



'हेरा फेरी 3' में देरी की अफवाहों को परेश रावल ने किया खारिज

फिल्म 'हेरा फेरी 3' को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह है। फैंस इस फिल्म को लेकर जिस बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं, इसे लेकर उतनी ही तरह-तरह की अफवाहें आती रहती हैं। फिल्म को लेकर बीते दिनों ऐसी खबरें आईं कि इसमें देरी होगी। मगर, अब परेश रावल ने इस पर बात की और ऐसी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने फिल्म की शूटिंग पर भी अपडेट दिया।

जल्द शुरू करेंगे शूटिंग

परेश रावल ने हाल ही में अपनी आगामी फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन के दौरान फिल्म 'हेरा फेरी 3' में देरी होने की अफवाहों को खारिज कर दिया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि जिस सीक्वल का बेसबी से इंतजार हो रहा था, वह जरूर बनेगा। अभिनेता ने मनी कंट्रोल से बात करते हुए कहा, 'किसी भी बात पर ध्यान न दें। 'हेरा फेरी 3' आ रही है। मैं जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू करूंगा'।

कब रिलीज होगी 'भूत बंगला'

बता दें कि इस फिल्म का एलान बीते वर्ष हुआ था। तब से ही 'हेरा फेरी 3' सुर्खियों में छाई हुई है। पहले ऐसी चर्चा थी कि परेश रावल ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है, लेकिन अब वे इस फ्रैंचाइजी के साथ फिर से जुड़ गए हैं। परेश रावल के 'हेरा फेरी 3' छोड़ने के बाद यह खबर फैल गई कि अक्षय ने उन पर 25 करोड़ रुपये के हर्जाने का मुकदमा किया है। उन्होंने समय रहते चीजों को सुलझा लिया, जिसके चलते अक्षय को मामला वापस लेना पड़ा। बात करें 'भूत बंगला' की तो यह फिल्म 16 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इसमें अक्षय कुमार लीड रोल में हैं। 'भूत बंगला' हॉरर-कॉमेडी फिल्म है। इसका निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है। इस फिल्म में अक्षय और प्रियदर्शन ने 14 साल बाद काम किया है। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी, मिथिला पावलकर और वामिका गब्बी मुख्य भूमिकाओं में हैं।



एक्ट्रेस न होती, तो जानवरों को रेस्क्यू कर रही होती

वामिका के बारे में सभी जानते हैं कि वे एनिमल लवर भी हैं। असमय -सामय पर वे जानवरों के हक में आवाज बुलंद करती रहती हैं। वे कहती हैं, 'अगर मैं अभिनय न कर रही होती, तो यकीनन जानवरों को रेस्क्यू कर रही होती। मैं एक एनिमल लवर हूँ और मुझे उनके बीच उन्हीं की तरह रहना पसंद है। मेरे पास 6 डॉग हैं मैंने इन्हें कोविड के दौरान रेस्क्यू किया था। मेरे कुत्तों का नाम है, फोबे, मिल्ली, जूली, फलुकी, गब्बर और मामी।

वो लड़की नहीं बनूंगी जो 40 साल में भी एक्टिंग में कुछ कर न पाए

पंजाबी फिल्मों की हीरोइन रही वामिका गब्बी के लिए बॉलिवुड का सफर आसान नहीं रहा। हिंदी फिल्मों में छोटी-छोटी भूमिकाएं करने वाली वामिका ने मुख्यधारा की नायिका बनने के लिए लंबा इंतजार किया। ग्रहण जैसी वेब सीरीज से चमकी वामिका ने जुबली और खुफिया जैसे ओटीटी प्रोजेक्ट्स से अपनी जमीन पुख्ता की। आज तो वे राजकुमार राव और अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम कर रही हैं। इन दिनों वे चर्चा में हैं प्रियदर्शन निर्देशित भूत बंगला से।

उस साल इंडस्ट्री से बोरिया -बिस्तर बांधकर जाने की सोच चुकी थी

राजकुमार राव के साथ भूलचूक माफ कर चुकी वामिका इन दिनों अक्षय कुमार जैसे बड़े हीरो की हीरोइन बन चुकी हैं, मगर एक समय ऐसा भी था, जब स्ट्रगल डेज में वे इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना चुकी थीं। वे बताती हैं, 'साल 2019 मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। तब मैंने सोच लिया था, मुझे नहीं बनना एक्टर। यहां कुछ नहीं हो रहा, तो मैं एक्टिंग ही छोड़ देती हूँ। उस साल मैंने अपना बोरिया-बिस्तर बांधने का फैसला कर लिया था। उस उमेर वक्त की बात है, जब मैंने विशाल सर (फिल्मकार विशाल भारद्वाज) की फिल्म मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए ऑडिशन दिया था और मैं शॉर्ट लिस्ट हो गई।

वो लड़की नहीं बनूंगी, जो 40 साल में भी एक्टिंग में कुछ कर न पाए

पंजाबी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाली वामिका गब्बी ने बॉलिवुड में जब वी मेट जैसी फिल्म में करीना कपूर की कजन की छोटी सी

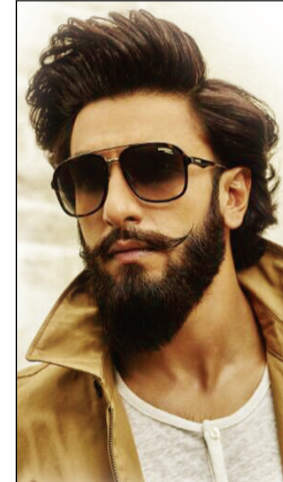
भूमिका भी की। फिर मुंबई में अपने 8 साल के करियर में फिल्मों और किरदारों के मामले में अच्छी-खासी मेहनत की है। अपने सफर को लेकर वे कहती हैं, 'मुझे तो हमेशा से अभिनय करना था, मगर आठ-नौ साल से मैं जब तक मुंबई में थी, तब जब करियर में कुछ हो नहीं रहा था। आज सोचती हूँ कि तब मैंने हार क्यों नहीं मानी? मैंने ऐसी कई कहानियां सुनी थीं कि लड़कियां 17-18 साल की उम्र में हीरोइन बनने जाती हैं और 40 साल की होकर जब वापिस आती हैं, तब उनका इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता।

डैड के लिए असरानी जी फोटो छिपकर ली थी

उनका परिवार उनके स्टारडम को कैसे देखता है? इस पर वे कहती हैं, 'आपको एक दिलचस्प बात बताऊं? मेरे डैड से उनके दोस्त अक्सर कहा करते थे, गब्बी, तेरी बेटी एक्ट्रेस तो बन ही जाएगी। उसे फिल्में तो मिल ही जाएंगी, मगर क्या वो किसी बड़े स्टार के साथ काम कर पाएगी? अब जब मेरी फिल्म भूत बंगला आई, तो वे बोले, अब मैं अपने दोस्तों से कह सकता हूँ कि मेरी बेटी अक्षय कुमार जैसे सुपर स्टार के साथ काम कर रही है, प्रियदर्शन उसे डायरेक्ट कर रहे हैं। मेरा परिवार बहुत खुश है कि मुझे असरानी और परेश रावल सरीखे दिग्गजों के साथ काम करने का अवसर मिला। मैंने तो शूटिंग के दौरान चुपके से स्वर्गीय असरानी जी का फोटो खींचकर अपने डैड को भेजी थी। वे बहुत एक्साइटेड थे कि मैं प्रीमियर पर असरानी जी से मिलूंगा। मगर अफसोस आज वे हमारे बीच नहीं हैं।'

चंद्रगुप्त मौर्य पर फिल्म कर सकते हैं रणवीर सिंह

'धुरंधर' फ्रैंचाइजी की सफलता के बाद अब सभी की नजर इस बात पर है कि डायरेक्टर आदित्य धर का अगला प्रोजेक्ट कौन सा होगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि आदित्य, रणवीर सिंह के साथ भी एक प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया... 'आदित्य इस समय तीन स्क्रिप्ट पर विचार कर रहे हैं। इनमें 'द इम्पोर्टेंट अश्वत्थामा', एक ऐतिहासिक फिल्म और एक बड़े लेवल की स्पॉट्स फिल्म शामिल है। उनकी अगली फिल्म इनमें से कोई एक हो सकती है, जब तक कि कोई नया प्रोजेक्ट प्राथमिकता में न आ जाए। 'द इम्पोर्टेंट अश्वत्थामा' आदित्य का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इस फिल्म पर उन्होंने पहले काफी काम किया था, लेकिन ज्यादा बजट के कारण इसे रोक दिया गया था।



सारा अर्जुन को कैसे मिला रणवीर के अपोजिट 'धुरंधर' का किरदार

फिल्म 'धुरंधर' में हर किरदार ने दर्शकों पर अपना असर छोड़ा है। इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आए हैं, वहीं उनके अपोजिट सारा अर्जुन दिखाई हैं। सारा अर्जुन ने यलीना का रोल निभाया है। यलीना की भूमिका के लिए 1200 दावेदार थे। मगर, यह रोल सारा की झोली में आया। फिल्म 'धुरंधर' के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने हाल ही में इसका जिक्र किया।

फ़ेश चेहरे को तवज्जो देना चाहते थे छाबड़ा

मुकेश छाबड़ा ने बताया कि रणवीर सिंह के किरदार हमजा के अपोजिट यलीना का रोल पाने के लिए कई एक्टरों ने कोशिश की थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में मुकेश छाबड़ा ने बताया कि उन्हें और आदित्य धर दोनों को ही उन एक्टरों से देरी रिक्वेस्ट मिल रही थी, जो इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए बेताब

थे। हालांकि, टीम एक बात को लेकर बिल्कुल साफ थी। कलाकार ऐसा हो, जो वाकई 'धुरंधर' की दुनिया का हिस्सा लगे, जिसकी पहल से कोई बनी-बनाई इमेज न हो।

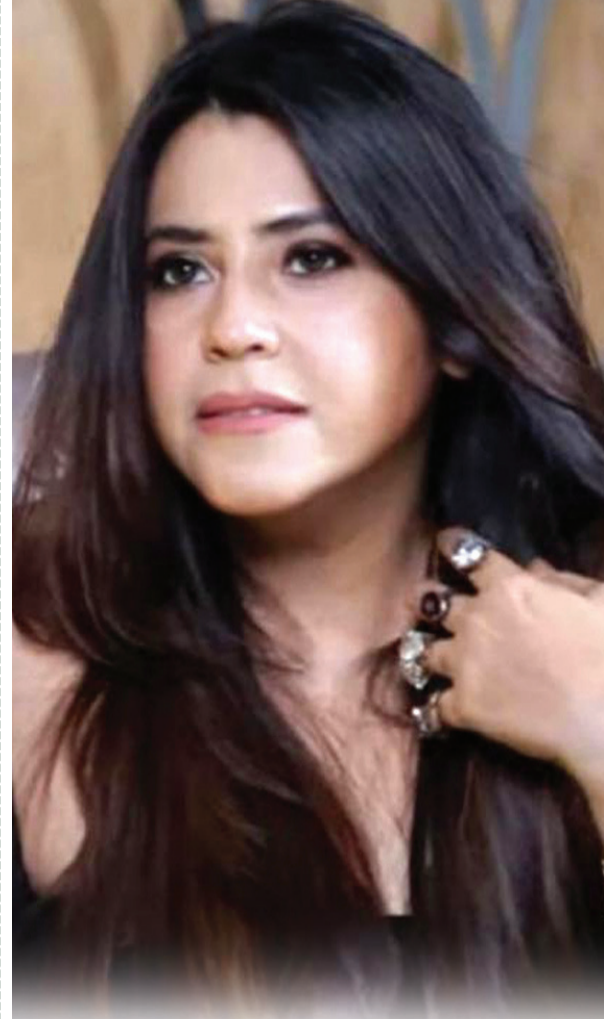
मुकेश छाबड़ा और आदित्य धर को आ रहे थे लगातार मैसेज

मुकेश छाबड़ा ने कहा, 'बहुत से लोग आदित्य को भी मैसेज कर रहे थे और कह रहे थे कि वे रणवीर के अपोजिट कास्ट होना चाहती हैं। मुझे भी मैसेज मिल रहे थे। लेकिन मैंने आदित्य से बहुत साफतौर पर कहा कि हमें एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो सचमुच उस जगह का लगे, जिसके साथ कोई पुराना बैगज न जुड़ा हो। इसलिए एक नया चेहरा ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा एक्टर हो जिसने रणवीर के साथ पहले दो फिल्मों की हों, तो वह कनेक्शन नहीं बन पाएगा, क्योंकि

फिल्म में रणवीर का किरदार पाकिस्तान जाकर उस लड़की से मिलता है।

हजार से ज्यादा एक्टरों ने दिए ऑडिशन

दिलचस्प बात यह है कि बचपन में एक्टिंग करने के बावजूद सारा अर्जुन ने अभी तक बॉलिवुड में कोई पूरी तरह से लीड रोल नहीं किया था। यह बात उनके पक्ष में रही। फिल्म बनाने वाले एक ऐसे चेहरे को पेश करने के इच्छुक थे, जो दर्शकों को बिल्कुल नया और अनजान लगे। उन्होंने आगे कहा, 'हमारा यह साफ मानना था कि अगर हम उस दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो यह एक पूरी तरह से चौकाने वाला अनुभव होना चाहिए। लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि यह लड़की कौन है? हमने बहुत सारे ऑडिशन लिए, कुल मिलाकर लगभग बारह सौ से तेरह सौ के करीब। फिर, आखिरकार हमने सारा का ऑडिशन लिया।



'धुरंधर: द रिवेज' का जबरदस्त प्रदर्शन हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है

अक्षय कुमार 14 वर्षों के बाद मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन के साथ फिल्म 'भूत बंगला' लेकर आ रहे हैं। आज इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में वामिका गब्बी, राजपाल यादव, असरानी और तब्बू जैसे कलाकार भी हैं। 'भूत बंगला' पहले 10

अप्रैल को रिलीज होने वाली थी लेकिन मेकर्स ने फिल्म को पोस्टपोन करने का फैसला किया। अब यह 17 अप्रैल को रिलीज होगी। इस बीच 'भूत बंगला' की निर्माता एकता कपूर ने फिल्म के पोस्टपोन होने की असली वजह बताई है। 'भूत बंगला' की रिलीज की तारीख आगे बढ़ाने पर एकता कपूर ने मीडिया से कहा कि फिल्म इसलिए लेट नहीं हुई क्योंकि थिएटर में 'धुरंधर 2' चल रही थी। मैं 10 अप्रैल को भी 'भूत बंगला' के लिए अच्छी स्क्रीन और शो-टाइम हासिल कर सकती थी। वैसे भी आजकल फिल्में आम तौर पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। अगर 'धुरंधर: द रिवेज' अच्छा कर रही है, तो अच्छी बात है। हम उसके साथ किसी जंग में नहीं हैं! हमने सोचा कि हमें थिएटर में आने से पहले उसे अपना करीब 85 परसेंट रन पूरा करने देना चाहिए।' इससे पहले 'भूत बंगला' के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज टालने को लेकर कहा था 'धुरंधर: द रिवेज का जबरदस्त प्रदर्शन हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। प्रदर्शकों को लगता है कि 'भूत बंगला' की रिलीज टालने से दोनों फिल्मों को वह जगह, फोकस और अटेंशन मिल पाएगी, जिसकी वे हकदार हैं।'



इंडस्ट्री में अपना काम खुद बताना पड़ता है

अमिताभ थपलियाल इन दिनों वेब सीरीज 'एस्पिरेंट्स' के सीजन 3 को लेकर चर्चा में हैं, जहां उनका 'एसके' का किरदार दर्शकों के दिलों में खास जगह बना चुका है। दैनिक भास्कर से बातचीत में अमिताभ ने बताया कि इस बार भी शो को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, खासकर दोस्ती से जुड़े इमोशनल सीन लोगों को गहराई से छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'एसके' का किरदार उन लोगों की कहानी है जो जिंदगी में फेल होते हैं, इसलिए दर्शक उससे खुद को जोड़ पाते हैं। अमिताभ ने अपने करियर की शुरुआत, रेडियो जॉकी से लेकर फिल्मों और वेब सीरीज तक के सफर को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि एक्टिंग उनका पहला सपना नहीं था, बल्कि वह आर्मी जॉइन करना चाहते थे। इंडस्ट्री में आउटसाइडर होने के कारण आई चुनौतियों और लगातार खुद को साबित करने की जरूरत पर भी उन्होंने खुलकर बात की।

'एस्पिरेंट्स' सीजन 3 को लेकर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है?

बहुत शानदार। एस्पिरेंट्स से लोग पहले ही जुड़ चुके हैं, इसलिए इस बार भी प्यार मिल रहा है। खासकर दोस्ती वाले सीन काफी वायरल हुए हैं। लोग कहते हैं कि देखकर भावुक हो गए।

आपके किरदार 'एसके' से लोग इतना कनेक्ट क्यों करते हैं?

क्योंकि ये सिर्फ टॉपर की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी है जो फेल हो जाते हैं। हम सब कहीं न कहीं वैसा ही महसूस करते हैं, इसलिए कनेक्शन बनता है। क्या बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। मैं तो आर्मी जॉइन करना चाहता था। मैं फौजी परिवार से हूँ, हट्ट विलियर करना सपना था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ।

एक्टिंग में एंट्री कैसे हुई?

मैं दिल्ली में रेडियो जॉकी था। वही फिल्म 'तेवर' के डायरेक्टर अमित शर्मा से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे फिल्मों में ट्राई करने को कहा। फिर मुंबई आया और पहली फिल्म पहली फिल्म 'दिल जंगली' मिली।

'एस्पिरेंट्स' से पहले करियर कैसा था?

शुरुआत में फिल्म में ज्यादा नहीं चली, फिर टीवी और कॉमेडी शोज किए। सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल सटायर भी करता था। लेकिन असली पहचान 'एस्पिरेंट्स' से मिली।

'एसके' का रोल कैसे मिला?

मैंने ऑडिशन दिया था। पहले मुझे लगा मैं 'अभिलाष' का किरदार करूंगा, लेकिन बाद में पता चला कि मुझे 'एसके' का रोल मिल रहा है।

'एस्पिरेंट्स' सीजन 1 के बाद क्या जिम्मेदारी बढ़ गई थी?

हां, लेकिन मैं स्क्रिप्ट में ज्यादा बदलाव नहीं करता। जो लिखा होता है, उसे इमानदारी से निभाता हूँ। मेरा मानना है 'कम में बम', कम सीन हों, लेकिन असरदार हों।

क्या आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है?

नहीं, मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। जो सीखा, लाइफ से सीखा। अलग-अलग जगह रहने से अलग-अलग भाषा और एक्सपेंस पकड़ना आसान हो गया।

'एस्पिरेंट्स' के बाद करियर में क्या बदलाव आया?

इसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं खुद को एक्टर कह सकता हूँ। फिर मैंने अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टरों के साथ काम किया और अलग-अलग रोल मिले।

आपने किन-किन फिल्मों और प्रोजेक्ट्स में काम किया है?

'एस्पिरेंट्स' के बाद मुझे कई अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले। मैंने फिल्म 'ब्लर' में काम किया, अनुराग कश्यप के साथ फिल्म 'केनेडी' में काम किया। और अश्विनी अय्यर तिवारी के साथ वेब सीरीज 'फाटू' में काम किया। इन प्रोजेक्ट्स ने मुझे एक एक्टर के तौर पर काफी कॉन्फिडेंस दिया।

इंडस्ट्री में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा?

आउटसाइडर होने का। आपको खुद जाकर लोगों को बताना पड़ता है कि आप क्या कर सकते हैं। यहां कोई गॉडफादर नहीं होता। मैं आज भी डायरेक्टरों और प्रोड्यूसर्स से मिलता हूँ, खुद को पिच करता हूँ। यह प्रोसेस कभी खत्म नहीं होती।

सभी शिशु रोते हैं, यह बिलकुल सामान्य बात है। अधिकांश शिशु प्रत्येक दिन कुल एक घंटे से लेकर तीन घंटे तक के समय के लिए रोते हैं। आपका नन्हा सा शिशु अपने आप खुद कुछ नहीं कर सकता है और वह आप पर अपनी हर जरूरत के लिए निर्भर करता है-चाहे वह भूखा है, आराम चाहता है या फिर प्यार और दुलार। आपका शिशु रो कर ही आपको यह बता सकता है की उसे किसी चीज की जरूरत है।



जानें आखिर क्यों इतना रोता है आपका बच्चा और उसे संभालने के उपाय

आपके लिए कई बार यह पता चलना मुश्किल हो जाता है की आखिर शिशु रो क्यों रहा है। लेकिन समय के साथ आप पहचानने लगेंगे और समझने लगेंगे की आपके शिशु के रोने का कारण क्या है। और जैसे जैसे आपका शिशु बढ़ता है वह आप के साथ बात चीत करने के अन्य तरीके सीख लेता है जैसे की आंखों का सम्पर्क, शोर मचाना या फिर मुस्कुराते हुए आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना। अगर आपका शिशु रो रहा है और चुप नहीं हो रहा है तो हो सकता है वह आपसे से यह कहने की कोशिश कर रहा है...



मुझे भूख लग रही है

भूख किसी नवजात शिशु के रोने का सबसे बड़ा कारण है। किसी बच्चे का छोटा सा पेट बहुत कुछ भंडार में नहीं रख सकता। इसीलिए अगर आपकी संतान रोती है, तो उसे दूध पिलाने की कोशिश करें, क्योंकि वह भूखी हो सकती है।

मेरी नैपी (कलोट) बदलो

कुछ शिशु अपनी नैपी बदलने की जरूरत पर बहुत ध्यान नहीं देते लेकिन कई दूसरे तुरंत ही चीख कर आपका ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। खासकर तब, अगर उनकी कोमल त्वचा में खुजली या खुश्की हो। यह भी देखें कि कौन सी नैपी बहुत कस कर तो नहीं बंधी है, या उसके कपड़े तो उसको परेशान नहीं कर रहे हैं।

मुझे अधिक गर्म या अधिक ठंड लग रही है

जांच करें कि आपका शिशु अपने बिस्तर में कहीं बहुत अधिक गर्म या ठंडा तो नहीं महसूस कर रहा। इसे आप उसके पेट को छूकर पता कर सकते हैं (उसके हाथ या पैर से पता नहीं लगेगा, वे सामान्य तौर पर ठंडे होते हैं)। अगर उसका शरीर अधिक गरम है, तो एक कंबल हटा दें। अगर वह ठंडा है तो एक और उद्दा दें। मौसम के अनुसार कपड़े का तापमान 22 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखें।



मुझे गोद में ले लो

कई बार आपका शिशु केवल दुलार चाहता है। चिंता न करें, अगर आप अपने शिशु को शुरूआती कुछ महीनों में अधिक समय तक उठा भी लेंगे, तो वह बिगड़ नहीं जायेगा। छोटे बच्चों को शारीरिक आराम और आश्रय की बहुत जरूरत है। यदि आप अपने बच्चे को सोने से लगा के रखेंगे तो उसे आपकी दिल की धड़कन सुनकर दिलासा मिलेगा आप शिशु को एक बेबी स्लिंग या केरीयर में भी रख सकते हैं जो आपके सीने या पीठ पर बंधता हो ऐसा करने से शिशु को आपकी गोद में रह सकेंगे और बाकी कामों के लिए आपके हाथ भी मुक्त रहेंगे।

मुझे आराम की जरूरत है

नवजातों के लिए काफी सक्रिय रहना कठिन होता है। उसके रोने का एक मतलब होता है- बस, मेरे लिए काफी है। रोना, चिड़चिड़ाता, उदास हो कर छत के ओर घूरना नींद आने के कुछ उदाहरण हैं। उसे किसी शांत और खामोश जगह ले जाएं। कुछ देर बाद आप पाएंगे कि वह सोने के लिए तैयार है।

मेरी तबियत ठीक नहीं है

अपने बच्चे में किसी भी परिवर्तन के बारे में सतर्क रहे। अगर वह अस्वस्थ है, वह शायद वह हमेशा की तरह न रोये। रोने का अलग ही स्वर हो सकता है, थोड़ा कम या अधिक या फिर चीख कर लगातार रोना। और अगर आपका शिशु आम तौर पर बहुत रोता है,

लेकिन असामान्य रूप से शांत हो गया है, तो यह भी एक संकेत है कि उसकी तबियत ठीक नहीं है। कोई भी आपके शिशु को इतनी अच्छी तरह से नहीं जान सकता जैसे की आप। यदि आपको लगता है कि आपके शिशु की तबियत ठीक नहीं लग रही है तो डॉक्टर से बात करें और अपनी चिंताओं पर चर्चा करें। डॉक्टर को तुरंत बुलाएं अगर आपका शिशु को रोते समय सांस लेने में कठिनाई हो रही है, या अगर रोने के साथ उसे बुखार, उल्टी, दस्त या कब्ज भी हो रहा हो।

मुझे कुछ चाहिए...पर पता नहीं क्या

कभी कभी आपको समझने में कठिनाई होगी की आखिर शिशु रो क्यों रहा है। देखा गया है की अक्सर नवजात शिशु बीच में कुछ दिनों के लिए चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर रोते ही रहते हैं।

कभी कभी आपको समझने में कठिनाई होगी की आखिर शिशु रो क्यों रहा है। देखा गया है की अक्सर नवजात शिशु बीच में कुछ दिनों के लिए चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर रोते ही रहते हैं।

मेरा शिशु लगातार रो रहा है मैं क्या करूं? यहां कुछ नुस्खे हैं जिससे आप अपने शिशु को आराम पहुंचा सकते हैं

उसे लपेटें और कस कर पकड़ें

कई माता पिता यह देखते हैं की उनके शिशु गोद में आते ही चुप हो जाते हैं खासकर जब वह आपके दिल की धड़कन को सुन के सुखदायक महसूस करते हैं। कई नवजात लिपटना और सुरक्षित महसूस करना पसंद करते हैं। जैसा कि वह गर्भ में रहते हैं, तो आप अपने शिशु को कंबल में लपेटें (यह स्वेडलिंग के नाम से जाना जाता है) या बेबी स्लिंग में भी उसे रख सकते हैं ताकि जान सकें कि क्या वह उसे पसंद करता है। हलाकि कुछ शिशु ऐसे भी होते हैं जिन्हें लिपेटे हुए रहना बिलकुल पसंद नहीं होता।

एक लगातार ध्वनि खोजें

गर्भ में आपका शिशु आपके दिल की धड़कन लगातार सुनता रहता है। इसलिए मधुर संगीत की आवाज या लोरी से आपके शिशु को आश्रयान मिलेगा। कई माता पिता को लगता है कि घड़ी की टिक टिक के स्थिर लय

कभी खुद से बहुत अधिक न मांगें

एक नवजात जो लाभग लगातार रोता है वह खुद को तो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अपने अभिभावकों को जरूर तनावग्रस्त कर सकता है। खैर, अगर आपने अपनी सोच के मुताबिक सब कुछ आजमा लिया है, तो समय आ गया है कि आप खुद की चिंता करें।
-यदि आप बाद प्रसव पूर्ण एकांतवास में हैं तो बाकि घर वालों की मदद लें।
-कुछ शांत संगीत सुनकर आराम करें।
-अपने शिशु को किसी सुरक्षित जगह लिटा दें और कुछ देर तक रोने दें-अपनी सुनने की सीमा के भीतर कुछ गहरी सांस लें।
-यदि आप और आपका शिशु दोनों ही परेशान हैं और आपकी सारी कोशिशो नकाम सी लग रही है तो अपने पति या घर के किसी और रिश्तेदार की मदद लें।
-अपने डॉक्टर से स्थानीय समर्थन समूहों (लोकल सपोर्ट ग्रुप) का पता लगाएं, जहां आप दूसरे नए अभिभावक बने लोगों से अपने अनुभव साझा कर सकें।
-मित्रों या फिर माता पिता से बात चीत करें और कुछ रणनीतियां बनायें अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए और अन्य नए माता पिता के साथ बात करें।

अक्सर शिशु को खामोश करते हैं और सोने में भी मदद करते हैं। अब बाजार से संगीत के सीडी या फिर टेप खरीद सकते हैं जो नन्हे शिशुओं को सुलाने में मदद करेंगे।

अपनी बाहों में शिशु को घुमाएं

अधिकतर बच्चे धीरे-धीरे हिलना पसंद करते हैं, या तो आप उसे टहलाने या गोद में लेकर एक हिलनेवाली कुर्सी में बैठें। खास तौर पर बच्चों के लिए बनाए शूल भी कुछ बच्चों को शांत कर देते हैं, पर कई सो भी जाते हैं, जैसे ही उनको किसी कार में कहीं ले जाया जा रहा हो।

दूध पिलाने के लिए अलग स्थिति खोजें

कुछ बच्चे दूध पीते समय रोते हैं यदि आप स्तनपान करा रही हैं तो आपने देखा होगा की



शिशु आराम से स्तन मुह में लेता है जब वह शांत होता है। अगर फीड के दौरान शिशु को गैस हो रहा है, तो आप ऐसी स्थिति ढूँढें जिसमें वह थोड़ा और सीधा होकर दूध पी सके। दूध पिलाने के बाद शिशु को डकार अवश्य दिलाएं। अगर आपका शिशु दूध पीने के बाद भी रोता है तो हो सकता है वह अब भी भूखा है। दोबारा से उसे दूध पिलाने की कोशिश करें।

उसे कुछ चूसने को दें

कुछ नवजातों में चूसने की इच्छा काफी तीव्र होती है और एक चुसनी या (साफ) उंगली या अंगुठा उसे काफी आरामदेह लगता है। कम्फर्ट सकिंग किसी बच्चे के दिल की धड़कन को नियंत्रित कर सकता है, उसके पेट को आराम पहुंचाता है, और उसे शांत कर देता है।

उसे एक गुनगुना स्नान दें

गुनगुने पानी से स्नान आपके बच्चे को शांत करने में मदद करेगा पहले पानी का तापमान की जांच करें फिर शिशु को तब में डालें। यह बात ध्यान में रखें की अगर आपका शिशु को स्नान पसंद नहीं है तो यह तरीका काम नहीं करेगी-उल्टा शिशु और जोर से रोने लग सकता है।

इन गेम में रखें बच्चे को बिजी शैतान नहीं बनेंगे समझदार

कोरोना महामारी के कारण हर जगह लॉकडाउन किया गया। वैसे तो अब लोगों ने काम पर जाना शुरू कर दिया है। मगर बात बच्चों की करें अभी भी बहुत से बच्चे ऑनलाइन क्लासिस लगा रहे हैं। ऐसे में घर पर रहने से बच्चे भी परेशान हो गए हैं। साथ ही उनकी शरारतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। कुछ बच्चों की शरारतों के चलते मां-बाप बेहद परेशान हो गए हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी गेम्स बताते हैं, जिसकी मदद से आप बच्चों को बिजी कर सकते हैं। साथ ही इससे वे नई चीजों को सीख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन एक्टिविटी के बारे में...



गार्डनिंग सिखाएं
अगर आपको व बच्चों को पौधे पसंद है तो उनकी गार्डनिंग में मदद लें। उन्हें पौधों का महत्व बताते हुए रोजाना पानी देने की सीख दें। इससे उनके अंदर एक अच्छी आदत भी विकसित होगी।

कुकिंग सिखाना भी अच्छा आइडिया
आजकल के बच्चों को हर काम आना चाहिए। ऐसे में आपका बेटा हो या बेटा आप उन्हें कुकिंग सिखा सकते हैं। अगर आपके बच्चा ज्यादा छोटा है तो आप उनसे सैंडविच, बेल पुरी, चाट आदि बनवा सकते हैं। इसके अलावा केक, कुकिंग बेक करवाना भी सही रहेगा। ऐसे में उसके अंदर एक और हुनर आएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर वे खुद के लिए खाना बना कर खा सकते हैं।

ड्राइंग सिखाना भी सही
बच्चों को कलर की दुनिया में खोने का अलग ही मजा आता है। ऐसे में आप उनसे पेंटिंग करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक ड्राइंग बुक व कलर खरीद कर उन्हें दें। अगर आपके बच्चे 5 से बड़े हैं तो आप उन्हें बबल पेंटिंग, पैबल पेंटिंग और स्प्रे पेंटिंग सिखा सकते हैं। इससे वे बिजी

भी रहेंगे साथ ही उनकी क्रिएटिविटी निखर कर सामने आएगी।

पजल गेम से होगा दिमाग तेज
शरारती बच्चों को हमेशा से दिमाग वाला काम करने का शौक होता है। ऐसे में आप उन्हें पजल गेम लाकर दे सकते हैं। आपको बाजार में बहुत सी पजल गेम्स आसानी



से मिल जाएगी। इस तरह तरह वे उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। इससे उनका टाइम पास होने के साथ दिमाग का विकास होगा। साथ ही आपको भी उनकी शरारतों से आराम मिलेगा।

अलग-अलग क्लासिस करवाएं ज्वाइन
ज्यादा शोर मचाने वाले बच्चों को अक्सर इंस्ट्र्यूमेंट पसंद होते हैं। ऐसे में आप उन्हें गिटार, पियानो, तबला, सिंगिंग या डांस की क्लासिस ज्वाइन करवा सकते हो। इसके लिए आपको ऑनलाइन क्लासिस आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब की भी मदद ले सकते हैं। इस तरह बच्चे मजे-मजे में एक नई चीज आसानी से सीख लेंगे। साथ ही उन्हें आगे अपना लक्ष्य चुनने की भी प्रेरणा मिलेगी।



आप थोड़ी सी सूझबूझ से निपटा सकते हैं माई-बहनों के आपसी मसले, ये टिप्स आजमाएं

घर में अगर दो बच्चे हैं तो उनकी परवरिश के लिए समझ-बूझ की जरूरत होती है। सब बच्चों पर एक ही नियम लागू नहीं हो सकता, क्योंकि भाई-बहन में जहां प्यार होता है तो वहीं छोटे-मोटे झगड़े भी होते हैं। हर छोटी-बड़ी बात पर मम्मी-पापा को इनके झगड़े का हिस्सा बनना पड़ता है। अगर पैरेंट्स एक बच्चे के व्यवहार को सही कहें और दूसरे के व्यवहार को गलत तो उसमें भी मुश्किल है, क्योंकि इससे एक बच्चे को बुरा लग सकता है। हम आपको कुछ ऐसी ही छोटी-छोटी बातें बता रहे हैं, जिससे आप अपने बच्चों की आपसी नोक-झोंक को समझदारी से सुलझा सकते हैं।



झगड़े की वजह जानें

अक्सर बच्चों के बीच झगड़ा होने पर पैरेंट्स उनके साथ समान व्यवहार पर ध्यान नहीं दे पाते। कई बार किसी बच्चे को गलती के लिए ज्यादा डांट पड़ जाती है, तो कई बार दूसरे बच्चे को जल्दी इनाम हो जाती है। किसी बच्चे को डांटने या उसकी गलती निकालने से पहले दोनों से पूरी बात जानें।

रिस्पेक्ट का नियम बनाएं

बच्चों के लिए व्यवहार के नियम बनाएं कि उन्हें कैसे एक-दूसरे के साथ पेश आना चाहिए। चाहे कितना भी गुस्सा क्यों न आए, बच्चों को

एक-दूसरे को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, अगर पहले से ही इस बारे में नियम बनाकर रखेंगे तो बच्चे अपनी लिमिट में रहेंगे और सभी संभव उपायों पर काम करेंगे।

झगड़े का निपटारा करना सिखाएं

बच्चों को सिखाएं कि किसी प्रॉब्लम से उन्हें कैसे डील करना है। आप बच्चों को एक ही सिचुएशन को अलग-अलग तरह से देखने के लिए प्रेरित करें। इससे उनका नजरिया बदलने में मदद मिलेगी और बच्चों की आपसी नाराजगी भी कम होती जाएगी।

कई बार बच्चों की अलग रुचि ही उनके आपसी झगड़े की वजह बनती है। एक बच्चे को नृत्य और बाहरी गतिविधियों, खेलकूद में आनंद आता है, तो दूसरे को इंडोर गेम्स और क्रिएटिव चीजों में। अगर पैरेंट्स के इंटरैक्ट किसी बच्चे से मेल खाते हैं तो वे उसकी तारीफ करने लगते हैं, वहीं दूसरे बच्चे की पसंद उनसे मेल नहीं खाती तो वे उसकी हानियों को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं करते। ऐसा करने से बच्चों में कॉम्प्लेक्स आ सकता है। ध्यान रखें कि बच्चे के इंटरैक्ट चाहे आपसे मेल खाए या नहीं, आपको दोनों पर ध्यान देने और सराहना करने की जरूरत है।

प्रतीक्षा का 12 साल का बेटा है जो खेल-कूद में तो आगे है, लेकिन किताबों के नाम से दूर भागता है। जिसे लेकर वो काफी परेशान रहती हैं। ये समस्या हर उस घर की है जहां बढ़ती उम्र के बच्चे हैं। पैरेंट्स किताबें पढ़ने के लिए बच्चों पर तरह-तरह का दबाव तो डालते हैं, लेकिन सही तरीके नहीं अपनाते। चलिए हम बताते हैं कुछ ट्रिक्स, जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चों में डेवलप कर सकते हैं रीडिंग हैबिट।

पहले पढ़कर सुनाएं : इंस्ट्रस्टिंग किताबें लाएं। पहले खेल-खेल में किताब पढ़कर सुनाएं। इससे बच्चे में धीरे-धीरे पढ़ने की रुचि बढ़ेगी। इंस्ट्रेस्ट की बुक लाएं : बच्चों की उम्र के अनुसार उनके इंस्ट्रेस्ट की किताबें लाएं। अपनी पसंद की किताबें

रीडिंग हैबिट : अभिभावक रूम में बुक कॉर्नर बनाएं और उनको किताबें करें गिफ्ट

...बच्चे भी कर लेंगे किताबों से दोस्ती



पढ़ने का प्रेशर न डालें। इससे उनकी अरुचि और बढ़ेगी।
हेल्पफुल हो सकते हैं न्यूज पेपर : पढ़ने की आदत डालने में न्यूज पेपर हेल्पफुल बन सकते हैं। जब आप अखबार पढ़ें तो बच्चे को भी पास बैठा कर पेपर पढ़ने के लिए प्रेरित करें। नई-नई खबरों के बारे में उससे बात करें। इससे बच्चे की जानकारी भी बढ़ेगी और पढ़ने की आदत भी बनेगी।
गिफ्ट करें किताबें : बच्चे के बर्थ डे पर या किसी खास मौके पर उसे उपहार के तौर पर किताबें गिफ्ट करें।

लाइब्रेरी फ्रेंडली बनाएं : बच्चे को लाइब्रेरी ले जाएं। बहुत सारी किताबें देखकर उसकी रुचि जागेगी। बच्चे को अलग-अलग विषयों की किताबों के बारे में बताएं। वहां बैठे बहुत से लोगों को पढ़ते देख बच्चे को भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
रूम में बनाएं बुक कॉर्नर : बच्चे के रूम में एक बुक कॉर्नर बनाएं। जिसमें अलग-अलग विषयों की किताबें रखें। बुक शेल्फ को रोचक तरीके से सजाएं। ये ट्रिक्स मददगार साबित होगी।
ई-बुक यूज न करें : बच्चे को ई-बुक यानी मोबाइल, लैपटॉप या टैब से किताबें पढ़ने की आदत बिल्कुल न डलवाएं। कई बार बच्चा पढ़ने का बहाना बनाकर गैजेट्स का मिस यूज भी कर

सकता है।
टाइम-टेबल बनाएं : बच्चों की पढ़ाई के लिए टाइम-टेबल बनाना बहुत जरूरी है। जब भी टाइम-टेबल बनाएं, बच्चों के साथ अपना भी टाइम-टेबल साझा रखें। सुबह बच्चों को जल्दी स्कूल पहुंचना होता है, आपको भी दफ्तर पहुंचने की जल्दी होती है। इसलिए सुबह का समय टाइम-टेबल में शामिल नहीं हो सकता। पर जब आप दफ्तर से लौटते हैं, टीवी देखने या दफ्तर का काम निपटाने के बजाय रात को कम से कम दो घंटे का समय बच्चों के लिए रखें। चूँकि माताएं रात के भोजन की तैयारी और दूसरे घरेलू कामों में लग जाती हैं, इसलिए पिता को ही अपना समय बच्चों को देना होगा। रात को ग्यारह बजे



तक जगा जा सकता है।
बच्चों को पढ़ाते समय या उनके पढ़ते समय साथ बैठते समय, चाहे तो आप भी कुछ पढ़-लिख या दफ्तर का काम कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि आपकी नजर उनकी पढ़ाई पर हो। जैसे ही बच्चों को खुद पढ़ने के लिए छोड़ेंगे, वे दूसरी तरफ ध्यान लगाएंगे। बीच-बीच में बच्चों से उनकी पढ़ी हुई बातों के बारे में पूछते रहें।